खण्ड-185, अंक-5
मंगलवार, 15 श्रावण, शक संवत् 1879
(6 अगस्त, 1957 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 185 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५७

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय	पृष्ठ-संख्या
सहारनपुर नगरपालिका के भंगियों की हड़ताल के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी) ..	१६३
प्रादेशिक कर्मचारियों को डाक व तार कार्यालयों में काम करने की आज्ञा देने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गई)	३६३–३६४
'नेशनल हेराल्ड' में कृषि मंत्री के भाषण को गलत ढंग से प्रकाशित करने पर कृषि मंत्री द्वारा आपत्ति	३६५
१९५७-५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या १९—लेखा शीर्षक : ३८—चिकित्सा तथा अनुदान संख्या २०—लेखा शीर्षक : ३९—जन स्वास्थ्य (स्वीकृत)	३६५–४०७
नत्थियां	४०८–४१५

उत्तर प्रदेश विधान सभा

६ अगस्त, १९५७ ई०

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य (३७१)

अक्षयवरसिंह, श्री
अज़ीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेश चन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अलीज़हीर, श्री सैयद
अल्लाह बख्श, श्री शेख
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अशफ़ाक़ अली खां, श्री
असग़र अली खां, कुंवर
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतज़ा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फ़तसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलकुमारी गोइंदी, कुमारी
कमलेशचन्द्र, श्री उपनाम कमले
कल्याणचन्द्र मोहिले, श्री उपनाम छुन्नन गुरु
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
किशोरीरमणसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
केशभानराय, श्री
केशवपांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह, चौधरी
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री

गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिका प्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जंगबहादुरसिंह विष्ट, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्त सिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ, चौधरी
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वर प्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
डूगरसिंह, श्री

ताराचन्द्र माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम, चौधरी
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
दुलारादेवी, श्रीमती
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंहदतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर प्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकर लाल श्रीवास्तव, श्री
पन्नरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह, चौधरी
प्रतापबहादुरसिंह, श्री

प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुशमेश , श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बृजवासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भूवनेशभूषण शर्मा, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनपांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूदअली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूदअली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकट बिहारी लाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मूलचन्द, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस' श्री,
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद फ़ारूक़ चिश्ती, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रघुनाथ सहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
उपनाम लाल साहब
रघुराजसिंह, चौधरी
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री

राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामगोपाल गुप्त, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखनमिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
राम समझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूपयादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूकनुद्दीन खां, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लायकसिंह, चौधरी
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ़अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह राजा, श्री
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
संग्रामसिंह, श्री
सईदअहमद अन्सारी, श्री

सजीवनलाल, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यवती देवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल घुसिया, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेव, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, ६ अगस्त, १९५७

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

सेक्रेटरिएट रिआर्गनाइजेशन स्कीम

**१—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सचिवालय रिआर्गनाइजेशन की जो योजना सरकार ने स्वीकार की है उसे किस तिथि से लागू किया जा रहा है ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—सरकार ने इस योजना को १२-१४ जुलाई, १९५७ को स्वीकृत किया। जैसे ही इस सम्बन्ध के कुछ प्रशासकीय ब्यौरे तय हो जायेंगे, इसे वन, शिक्षा और सिंचाई के तीन विभागों में लागू कर दिया जायगा।

**२—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस योजना के अन्तर्गत स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों को लखनऊ से बाहर जाना पड़ेगा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां। कुछ कर्मचारियों को जाना पड़ सकता है।

**३—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इन कर्मचारियों की नौकरी की कौन-कौन सी शर्तें हैं जिनमें रिआर्गनाइजेशन के कारण तब्दीलियां होंगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—योजना के अनुसार, उसके लागू किये जाने पर, न तो किसी को हटाया जायगा और न ही वेतन-क्रमों में कमी होगी।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १२ और १४ जुलाई को जो योजना स्वीकार की गई थी उसे शिक्षा और वन विभागों में लागू करने में कुछ कठिनाइयां हो रही हैं ? अगर हां, तो वह क्या हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मुझे ऐसी किसी कठिनाई का पता नहीं है।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस योजना को लागू करने के सिलसिले में सेक्रेटरीज ने इसका विरोध किया है ?

श्री अध्यक्ष--कोई रिकग्नाइज्ड एसोसियेशन अगर किसी चीज का हो और आप उसके बारे में पूछें तो मैं इजाजत दे दूंगा। वैसे सेक्रेटरीज लिखा करते हैं अपने नोट्स आदि, उनके बारे में प्रश्न की मैं इजाजत नहीं दूंगा ।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--क्या यह सही है कि यह निश्चय अभी नहीं किया जा सका कि कर्मचारियों को बाहर भेजना पड़ेगा या नहीं ? यदि नहीं, तो फिर यह योजना क्या है ?

श्री अध्यक्ष--यह तो जवाब में बताया जा चुका है ।

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)--क्या माननीय मंत्री जी इस योजना की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--योजना की मैं एक समरी सी बनवा रहा हूं। मैं कोशिश करूंगा कि वह माननीय सदस्यों की मेज पर रख दी जाय ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इस योजना का जो मुख्य आशय है उसको सदन को बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--उन्होंने जबाब दिया कि समरी बनवा कर दे देंगे। तो मैं इतनी बड़ी योजना बताने के लिये समय नहीं दूंगा ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलायेंगे कि जो योजना है उससे आय-व्यय पर कितना असर पड़ेगा और एफीशियेन्सी पर कितना असर पड़ेगा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--एफीशियेन्सी पर तो बहुत अच्छा असर पड़ेगा लेकिन खर्च पर कितना असर पड़ेगा इसका एस्टीमेट अभी नहीं बतलाया जा सकता ।

राजकीय स्त्री-चिकित्सालय गोसाईंगंज, जिला लखनऊ की महिला डाक्टर श्रीमती चन्द्रा के विरुद्ध शिकायत

****४--श्री खयाली राम** (जिला लखनऊ)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उस शिकायत के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है जो राजकीय स्त्री-चिकित्सालय, गोसाईंगंज, जिला लखनऊ, की महिला डाक्टर श्रीमती चन्द्रा के विरुद्ध गत ८ जुलाई, १९५७ को एक जच्चा का इलाज न करने के कारण नव जात शिशु की हो जाने वाली हत्या के सम्बन्ध में सरकार के पास आई है ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी)--इस विषय में जांच कराई गई और जांच की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है। परन्तु लेडी डाक्टर का स्थानान्तरण कर दिया गया है। जांच की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद अन्तिम आज्ञा दी जावेगी।

श्री खयालीराम--क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त लेडी डाक्टर अभी तक उसी अस्पताल में काम कर रही हैं ?

कृषि मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)--जी नहीं, उनका तबादला हो गया ।

श्री खयालीराम--ट्रांसफर हुआ तो उनकी नियुक्ति किस स्थान पर की गयी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--वहां से ट्रांसफर हो गया । कहां गयीं इसके लिये नोटिस दें तो बतलाया जा सकता है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस घटना का पूरा विवरण क्या है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---रिपोर्ट विचाराधीन है । तय करने के बाद कुछ कहा जा सकता है ।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)---क्या स्वास्थ्य मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि किस तारीख को लेडी डाक्टर का ट्रान्सफर किया गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---परसों ।

प्रान्तीय रक्षक दल का विघटन करने का विचार

****५---श्री लक्ष्मणराव कदम** (जिला झांसी)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह प्रांतीय रक्षकदल का विघटन कब से कर रही है ?

नियोजन उपमंत्री (श्री जगमोहन सिंह नेगी)---प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

****६---श्री लक्ष्मणराव कदम**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त विभाग कब खोला गया था और उसमें कितने व्यक्ति किन-किन पदों पर काम कर रहे हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---(१) यह विभाग १ अप्रैल, १९४८ में खोला गया था ।

(२) इसमें काम करने वालों की संख्या तथा पदों के नामों की सूची माननीय सदस्य की मेज पर रखी है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४०८-४१० पर)

****७---श्री लक्ष्मणराव कदम**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त लोगों के absorption के सम्बन्ध में उसने क्या निश्चय किया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस सम्बन्ध में विचार करने का प्रश्न कैसे पैदा हुआ ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---शासन से सम्बन्ध रखने वाले जितने प्रश्न हैं समय-समय पर सभी सरकार के सामने आते रहते हैं और सरकार का कर्त्तव्य है उन पर विचार करे ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि सरकार द्वारा दिये गये प्रश्न का वह उत्तर सही है जिसमें कहा गया है कि प्रान्तीय रक्षक दल को सरकार तोड़ रही है या वह उत्तर सही है कि यह विचाराधीन है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मैं समझा नहीं कि कहां सरकार तोड़ रही है और किस जगह पर विचाराधीन है । जो बजट सामने रखा गया है उससे जाहिर होगा कि उसमें खर्चे को कुछ कम करने का प्रस्ताव सदन के सामने रखा गया है । खर्चा कम करने के बाद प्रान्तीय रक्षक दल की क्या सूरत होगी इसके सम्बन्ध में १२-१३ को जब बजट सदन के सामने आयेगा तब सम्भवतः मैं व्योरेवार रख सकूंगा ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या गेंदासिंह जी के हाल में प्रश्नोत्तर में माननीय मंत्री जी ने इकोनोमी कमेटी की सिफारिशों को मानते हुए यह कहा था कि प्रान्तीय रक्षकदल को तोड़ देने का फैसला किया गया है जिससे २० लाख रुपये के करीब बचत होगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—लेकिन मैं यह निवेदन करूंगा कि यह बात जो कही गयी उसको जो बजट रखा गया है उसके प्रकाश में देखनी चाहिये। अगर बिल्कुल तोड़ देने की बात होती तो वैसे ही हम रखते लेकिन यहां तो खर्चे को कम करने की बात है। जिस कदर खर्चा कम हुआ उस हद तक वह जरूर तोड़ा जायगा।

श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार मेहरबानी करके बतलायेगी कि रक्षक दल जिस सूरत में चल रहा था उसका रूप बदलने की जरूरत आज क्यों पैदा हुई? किस वजह से उसको इस सूरत में नहीं चलाया जा रहा है, जिस सूरत में वह चल रहा था?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इसलिये कि जो उसका मौजूदा रूप है उससे ज्यादा बेहतर और रूप बन जाय तो अच्छा है।

लखीमपुर जेल में सोशलिस्ट सत्याग्रहियों द्वारा अनशन

८—डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा** (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि लखीमपुर जेल में १८ जुलाई को सोशलिस्ट सत्याग्रहियों तथा अन्य बंदियों ने सामूहिक अनशन किया था?

समाज सुरक्षा राज्य-मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)—सोशलिस्ट पार्टी के निश्चयानुसार केवल १० सोशलिस्ट सत्याग्रहियों ने दिनांक १८ जुलाई, १९५७ के शाम का भोजन नहीं किया। इनके अतिरिक्त दो विचाराधीन कैदियों ने भी जिन्होंने अपने को सोशलिस्ट पार्टी का बतलाया उक्त सत्याग्रहियों के प्रति सहानुभूति में उस शाम का भोजन नहीं किया। और किसी कैदी ने भूख-हड़ताल नहीं की।

वाराणसी औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा प्रशिक्षित ओवरसियरों को मान्यता देने पर विचार

९—श्री काशीप्रसाद पांडेय** (जिला सुल्तानपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वाराणसी औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा प्रशिक्षित ओवरसियरों को उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की गई है?

श्रम मंत्री के सभा-सचिव (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)—जी नहीं।

श्री काशीप्रसाद पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस संस्था को प्रदेशीय सरकार कुछ आर्थिक सहायता देती है?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—प्रदेशीय सरकार ४० प्रतिशत और केन्द्रीय सरकार ६० प्रतिशत खर्चा वहन करती है।

श्री काशीप्रसाद पांडेय—आर्थिक सहायता देते हुये मान्यता देने में इस सरकार को क्या कठिनाई है?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—इन सभी प्रश्नों पर विचार हो रहा है कि इस संस्था से निकले हुये विद्यार्थियों को भी मान्यता दी जाय।

राज्य कर्मचारियों का वेतन तथा भत्ता बढ़ाने के लिए द्वितीय पे-कमेटी नियुक्त करने का सुझाव

१०—श्री नारायणदत्त तिवारी**—क्या सरकार ने राज्य कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि समस्त प्रश्नों पर आमूल विचार करने के हेतु द्वितीय पे-कमेटी नियुक्त करने का निश्चय किया है?

वित्त मंत्री के सभासचिव (श्री धर्मसिंह)—जी नहीं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार उन कारणों पर प्रकाश डालने की कृपा करेगी कि जिनसे सन् ४७ की पे-कमेटी की रिपोर्ट को प्रकाशित हुये १० वर्ष के बाद भी द्वितीय पे-कमेटी न बैठाने का सरकार ने फैसला किया है ?

श्री धर्मसिंह---१९४७ की पे-कमेटी के समय के महंगाई के आंकड़ों का मुकाबिला करके सरकार यह महसूस करती है कि महंगाई नहीं बढ़ी है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार को ज्ञात है कि हाल ही में केन्द्रीय सरकार ने श्री जगन्नाथदास जी की अध्यक्षता में इंटेरिम रिलीफ के सम्बन्ध में भी विचार करने के लिये और अन्य महंगाई भत्ते के बारे में एक कमेटी बैठाई है और उसके टर्म्स आफ रेफ्रेंस में यह भी है कि वह प्रदेशीय सरकारों और केन्द्रीय सरकार के महंगाई भत्ते के सम्बन्ध में विचार करे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---तो क्या प्रदेशीय सरकार इस बात को देखते हुये कि केन्द्रीय सरकार भी स्वयं महंगाई के प्रश्न पर विचार कर रही है और महंगाई को बढ़ा हुआ मानती है उस कमेटी की सहायता के लिये या प्रदेशीय कर्मचारियों के वास्ते कोई द्वितीय पे-कमेटी कायम करने का आश्वासन देगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---यदि उनको हमारी किसी सहायता की आवश्यकता होगी तो हम जरूर सहायता देंगे । लेकिन मेरा ख्याल है कि माननीय सदस्य ने उनके टर्म्स आफ रेफ्रेंस को देखा नहीं है । वह प्रदेश के कर्मचारियों के सम्बन्ध में विचार करने वाली नहीं है । जो सिफारिश वह कमेटी करेगी उसमें इस बात का ध्यान रखने की बात है कि प्रादेशिक सरकारों के कर्मचारियों का वेतन बहुत कम है । इसके मानो हैं कि बहुत लम्बी-चौड़ी सिफारिश न की जाय । वेतन का अन्तर ज्यादा बढ़ने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है ।

तारांकित प्रश्न

आगरे में अन्डरग्राउण्ड सीवर्स का निर्माण-कार्य

*१---**श्री देवकीनन्दन विभव**---क्या स्वशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में Underground sewer का कार्य कब प्रारम्भ हुआ, अब तक उसमें कितना रुपया लग चुका है तथा अब वह कब से और क्यों अधूरा पड़ा है ?

स्वशासन मंत्री के सभा-सचिव (श्री रामस्वरूप यादव)---आगरे में Underground sewers का कार्य सन् १९४७ में प्रारम्भ हुआ था और सन् १९५२ तक Main Intercepting sewer का कार्य समाप्त कर दिया गया । सन् १९५५-५६ में National Water supply and Drainage योजना के अन्तर्गत कुछ और रुपया मिलने पर Branch sewers का काम शुरू किया गया, परन्तु ठेकेदारों से payment के बारे में कुछ मतभेद होने के कारण अक्तूबर, १९५६ से यह कार्य धीमा पड़ गया है । इन कार्यों में अब तक कुल ४२,७८,८०० रुपया व्यय हुआ है । अब रुपयों की कमी के कारण अधिक ध्यान सीवेज पंपिंग स्टेशन, सीवेज चेनेल तथा अन्य कार्यों के निर्माण की ओर दिया जा रहा है जिससे गंदा नाला जो आजकल यमुना नदी में गिरकर उसके स्वच्छ जल को दूषित करता है, शीघ्र रोका जा सके ।

श्री देवकीनन्दन विभव---क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि इस साल में जो लागत लगी है उसके ब्याज का व्यय कौन वहन करेगा ?

स्वशासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)---स्वभावतः वहां का बोर्ड करेगा ।

श्री देवकीनन्दन विभव---क्या माननीय मंत्री जी ने इस पर विचार किया है कि इन योजनाओं का बहुत लम्बा काम लेने से राज्य की आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ता है और क्या सरकार यह विचार कर रही है कि इस प्रकार की योजनाओं को शीघ्र ही समाप्त किया जाय ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---ऐसी कोई बात नहीं है । हम चाहते हैं कि सम्भव हो तो उन्हें जल्द से जल्द किया जाय, लेकिन ऐसी दिक्कतें सामने आ जाती हैं कि काम समय पर नहीं हो सकता है ।

श्री देवकीनन्दन विभव---क्या माननीय मंत्री जी का विचार इस सीवे की योजना को प्रारम्भ करने का है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---वह तो चल रही है लेकिन जितने परिमाण में चलाना चाहते हैं उतना रुपया नहीं है । कम रुपये के हिसाब से उसे बनाया जा रहा है ।

गोरखपुर जिला अदालतों में गांव सभाओं के मुकदमों की पैरवी करने वाले सरकारी वकीलों व मुख्तारों को मेहनताने का न मिलना

*२---**श्री केशव पांडेय** (जिला गोरखपुर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसने जिलों की अदालतों में गांव सभाओं के मुकदमों की पैरवी करने के लिये कुछ वकील एवं मुख्तारों की नियुक्ति की है ?

श्री रामस्वरूप यादव---मूलतया ग्राम सभाओं के मुकदमे की पैरवी करने के लिये वकील एवं मुख्तारों की नियुक्ति की गई है । इस सम्बन्ध में यह आदेश भी प्रसारित किये गये हैं कि गांव सभाओं के मुकदमे की पैरवी इन्हीं वकीलों एवं मुख्तारों के द्वारा कराई जाय ।

*३---**श्री केशवपांडेय**---क्या सरकार ने उक्त वकीलों एवं मुख्तारों को कुछ फीस भी देने को तय कर रक्खी है ? यदि हां, तो कितने रुपये ?

श्री रामस्वरूप यादव---माल के मुकदमों में रेवेन्यू कोर्ट मैनुअल के अनुसार तथा दीवानी के मुकदमों में मुकदमे की मिलकियत के आधार पर फीस दी जाती है । परन्तु कम से कम ५ रुपया प्रत्येक मुकदमे के लिये फीस निर्धारित की गई है ।

*४---**श्री केशव पांडेय**---क्या सरकार को यह ज्ञात है कि इन वकीलों, मुख्तारों के रूप में सरकारी पैरोकार होते हुये भी गांव सभापतियों को अलग से भी पैरोकार वकील रखना पड़ता है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री रामस्वरूप यादव---शासन को ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है । हां, नियमानुसार विशेष मुकदमों में जिलाधीश की अनुमति से अन्य वकील भी नियुक्त कर सकते हैं ।

श्री केशव पांडेय---क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि या उनको जानकारी है कि अभी तक इन वकील और मुख्तारों को एक भी पैसा सरकार की ओर से नहीं दिया गया है, गोरखपुर जिले में ?

श्री रामस्वरूप यादव---पैनेल आफ लाइयर्स की फीस का बिल लीगल रिमेंम्ब्रेन्सर के पास आता है । जिन्होंने कायदे के अनुसार अपने बिल भेजे होंगे उनको भुगतान दे दिया होगा, अगर कोई त्रुटि होगी तो उनका भुगतान अवश्य रुका हुआ होगा ।

श्री केशव पांडेय---क्या सरकार के पास गोरखपुर के वकीलों और मुख्तारों की ओर से जो सरकार की ओर से नियुक्त हुये हैं, कोई सूचना आई है कि उनके पास मुकदमों की पैरवी की कोई सूचना न होने से वह ठाक से पैरवो नहीं कर सकते हैं और उनका रुपया रोकना ठीक नहीं है ?

श्री रामस्वरूप यादव---जहां तक जानकारी है ऐसी कोई सूचना नहीं आई है, लेकिन इसके लिये सूचना की आवश्यकता है जिससे तलाश किया जा सके ।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)---क्या सरकार को मालूम है कि गांव सभाओं के अध्यक्षों से ये वकील अलग से हर मुकद्दमें में मेहनताना ले लेते हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव---सरकार की जानकारी में नहीं है । अगर ले लेते होंगे तो उनको देना नहीं चाहिये ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---क्या सरकार को मालूम है कि जो व्यवस्था इस समय गांव सभाओं की तरफ से पैरवी करने की है उससे गांवसभाओं के भूमि वापस लेने में कोई प्रगति नहीं है ?

श्री रामस्वरूप यादव---भूमि का प्रश्न ग्राम समाज से संबंधित होता है ।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि कभी-कभी गांव समाज के प्रधानों के भेजे हुए मुकदमों की पैरवी करने से वकील मुख्तार इंकार भी कर देते हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव---सरकार को ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)---क्या माननीय मंत्री जो यह बताने की कृपा करेंगे कि सम्बन्धित वकीलों को मुकदमों की सूचना किन नियमों के अनुसार दी जाती है ?

श्री रामस्वरूप यादव---नियमों के अनुसार एस० डी० ओ० उस सम्बन्ध के आवेदन-पत्र भेज देते हैं ।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---क्या माननीय मंत्री जी गांव सभाओं के मुकदमों को देखते हुये इस बात पर विचार करेंगे कि गांव सभाओं के वकील केवल गांव सभाओं के मुकदमें करें ?

श्री रामस्वरूप यादव---मैंने निवेदन किया कि गांव सभाओं के मुकदमें बहुत कम होते हैं, गांव समाज के मुकदमे ज्यादा होते हैं । वकील जो मुकर्रर होते हैं वे गांव सभा के होते हैं । इसलिये उनके पास इतना ज्यादा काम नहीं होता कि वे और काम न कर सकें ।

फीरोजाबाद-कोटला सड़क की खराब हालत तथा फीरोजाबाद तहसील में शंकरपुर में यमुना पर पुल की आवश्यकता

*५---**श्री जगन्नाथ लहरी** (जिला आगरा)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि फीरोजाबाद-कोटला रोड का निर्माण जिला बोर्ड के हाथ से लेकर वह अपने विभाग द्वारा कराने जा रही है ? अगर हां, तो कब तक उसका निर्माण-कार्य प्रारंभ कर दिया जायेगा ?

निर्माण मंत्री (श्री गिरधारीलाल)---प्रथम भाग---जी नहीं ।

द्वितीय भाग---प्रश्न नहीं उठता ।

*६---**श्री जगन्नाथ लहरी**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि फीरोजाबाद तहसील में ग्राम शंकरपुर में यमुना नदी पर पुल निर्माण करने की योजना है ? अगर हां, तो यह निर्माण-कार्य कब तक प्रारम्भ हो जायेगा ?

श्री गिरधारीलाल—प्रथम भाग—जी नहीं ।

द्वितीय भाग—प्रश्न नहीं उठता ।

श्री जगन्नाथ लहरी—क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि फीरोजाबाद-कोटला रोड एक महत्वपूर्ण सड़क है और उसकी हालत बहुत खराब हो रही है ?

श्री गिरधारीलाल—जी हां, होगी । लेकिन यह सड़क पी० डब्ल्यू०डी० के पास नहीं है ।

श्री जगन्नाथ लहरी—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जब इस सड़क की दशा इतनी खराब हो गयी है तो क्या वे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को इस प्रकार के आदेश देंगे कि वह तुरन्त उसको ठीक कराये ?

श्री गिरधारीलाल—सूबे में इस प्रकार की बहुत-सी सड़कें हैं जिनकी हालत खराब है और वे महत्वपूर्ण हैं, लेकिन पी०डब्ल्यू०डी० धनाभाव के कारण उनको लेने को तैयार नहीं है ?

श्री जगन्नाथ लहरी—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि आगरा जिले की प्लानिंग कमेटी ने इस सड़क को पी० डब्ल्यू० डी० द्वारा लिये जाने की प्रार्थना की थी ?

श्री गिरधारीलाल—जी हां, प्रार्थना की थी ।

इलाहाबाद इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को अनुदान देने की सिफारिश

*७—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि इलाहाबाद इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को कितना धन नगर सुधार हेतु अनुदान के रूप में सन् १९५३ से फरवरी, १९५७ तक दिया गया तथा उसमें कौन-कौन सी स्कीमें पूरी हुईं ?

श्री रामस्वरूप यादव—नगर सुधार हेतु अनुदान के रूप में कोई धन नहीं दिया गया ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या यह सही है कि इलाहाबाद इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने अधूरी स्कीम को पूरा करने के लिये सरकार को चार बार लिखा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसके लिये उसे अनुदान देने की कृपा करेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव—इलाहाबाद ट्रस्ट की ओर से किसी योजना के सम्बन्ध में अभी कोई मांग नहीं आयी ।

*८—श्री कल्याणचन्द मोहिले—[२० अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया ।]

भोपाल हाउस रिफ्यूजी मार्केट, लखनऊ का किराया

*९—श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)—क्या सरकार यह बतायेगी कि भोपाल हाउस रिफ्यूजी मार्केट के बनाने में सरकार ने कितना रुपया दिया तथा म्युनिसिपल बोर्ड, लखनऊ ने कितना रुपया लगाया ?

श्री रामस्वरूप यादव—भोपाल हाउस के निर्माण हेतु राज्य सरकार ने कुल ८,७८,००० रुपया दिया तथा नगरपालिका लखनऊ ने कुल ३,६२,५८२ रुपया अपने आय-व्ययक से लगाया ।

*१०—श्री त्रिलोकीसिंह—क्या सरकार यह बतायेगी कि उक्त बाजार में बसने वालों से म्युनिसिपल बोर्ड क्या लेता है ?

श्री रामस्वरूप यादव---भोपाल हाउस के निवासियों तथा दूकानदारों से नगर-पालिका भवन निर्माण के ऊपर कुल व्यय का लगभग ७.५ प्रतिशत धन किराये के रूप में वसूल करती है।

श्री गौरीशंकर राय---क्या यह सही है कि नगरपालिका का यह व्यय वास्तविक व्यय नहीं है बल्कि आनुमानिक व्यय है?

श्री रामस्वरूप यादव---यह व्यय तो वास्तविक व्यय है।

श्री भगवतीसिंह विशारद---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भोपाल हाउस से हाउस टैक्स और वाटर टैक्स कितना वसूल किया जाता है?

श्री रामस्वरूप यादव---प्रत्येक दूकान का प्रतिमास का कम से कम २२ रुपया तथा अधिक से अधिक १९३ रुपया २ आ० किराया है। प्रत्येक फ्लैट का कम से कम ६५ रुपया तथा अधिक से अधिक ८३ रुपया किराया है। शरणार्थियों को बसाने हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्मित बाजार से नगरपालिका लखनऊ को लगभग ५९,००० रुपया वार्षिक किराया आता है।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में भोपाल हाउस के रहने वाले किरायेदारों ने बहुत-सी शिकायतें अहलकारों द्वारा रुपया खा जाने तथा ठेकेदारों द्वारा रुपये में गड़बड़ी करने के बारे में भेजी थीं?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री भगवतीसिंह विशारद---माननीय मंत्री जी ने उत्तर में बतलाया है कि कुल लागत का ७.५ प्रतिशत किराया वसूल होता है। उस हिसाब से ९३,०४३ रुपया होता है जबकि उन्होंने बतलाया कि ६३,००० रुपया सालाना किराया वसूल होता है। तो क्या मेरे कथन को सत्य प्रमाणित करने की कृपा करेंगे तथा यह डयोढ़े का फर्क कैसे है?

श्री रामस्वरूप यादव---मैंने आपको ५९,००० रुपया बतलाया और वह भी कुछ ज्यादा ही बतलाया कि शरणार्थियों को बसाने के लिये राज्य सरकार द्वारा निर्मित बाजार से ५९,००० रुपया वार्षिक किराया मिलता है। जहां तक भूपाल हाउस की बात है, मैंने बतलाया कि ७.५ प्रतिशत के हिसाब से कुल लागत पर किराया आता है।

बरेली नगर की हाउस ऐलाटमेंट एडवाइजरी कमेटी

*११---श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)---क्या न्याय मंत्री बतायेंगे कि नगरों में जो हाउस एलाटमेंट एडवाइजरी कमेटियां बनाई गई हैं उसके Constitution के लिये कोई आदेश प्रदेश की ओर से जारी हुये हैं? यदि हां, तो क्या?

न्याय उपमंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)---जी हां। जिलाधीश को मकानों के एलाटमेंट के बारे में परामर्श देने के लिए सरकार ने १९४९ में हर जिले में हाउस एलाटमेंट एडवाइजरी कमेटियां बनवाईं। कमेटी का विधान सिवाय लखनऊ के इस प्रकार है :---

अध्यक्ष

जिलाधीश।

सदस्य

(१) चेयरमैन, म्युनिसिपल बोर्ड।

(२) सरकार द्वारा नामजद स्कूल अथवा कालिज का एक हेडमास्टर अथवा प्रिन्सिपल।

(३) सरकार द्वारा नामजद एक प्रमुख नागरिक अथवा जनसेवक।

अप्रैल, १९५३ से नामजद सदस्यों की संख्या दो से तीन कर दी गई है।

*१२—श्री जगदीशशरण अग्रवाल—क्या न्याय मंत्री बतायेंगे कि बरेली नगर की हाउस एलाटमेंट एडवाइजरी कमेटी सरकार के आदेशों के अनुकूल बनी हुई है?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जी हां।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार की ऐसी नीति है कि हेडमास्टर और प्रिंसिपल केवल वही नियुक्त किये जायं जो सरकारी एम्प्लायी हों?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—ऐसी तो कोई नीति नहीं है। स्थान-स्थान पर विभिन्न हैं, किसी स्थान पर कोई, किसी स्थान पर कोई?

श्री जगदीशशरण अग्रवाल—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि सन् १९४९ से अब तक बरेली में कभी किसी सरकारी स्कूल के हेडमास्टर के अतिरिक्त किसी और स्थानीय स्कूल के हेडमास्टर का नाम भी विचार करने के लिये आया और आया तो किन-किन स्कूलों के?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता पड़ेगी।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल—क्या मंत्री जी इस सुझाव पर विचार करेंगे कि जिन शहरों में हेडमास्टर्स के असोसियेशन स्थापित हो चुके हैं वहां पर उनसे इन नियुक्तियों के विषय में सलाह ले ली जाय?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—इस समिति को तो फिर से दोबारा रिवाइज किया जा रहा है, उस समय इस सुझाव पर भी विचार कर लिया जायगा।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि नागरिक की प्रमुखता और जनसेवक की उपयुक्तता सरकार किस आधार पर तय करती है?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जो नागरिक है और जनसेवक है।

श्री प्रतापसिंह—क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि बरेली में कौन नागरिक और जनसेवक इस समिति में हैं?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—हेडमास्टर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, दूसरे हैं श्री आगामिर्जा और तीसरे हैं शिवशरण अग्रवाल साहूकार।

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित (जिला कानपुर)—यह जो नई कमेटी बनाई जा रही है वह कब तक बन जायगी?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—अभी कोई समय नहीं बताया जा सकता, लेकिन वह रिवाइज हो रही है।

श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ में भी इस तरह की कोई कमेटी बनाई गई थी? वह किस विधान के अनुसार बनाई गई थी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---लखनऊ में २ कमेटियां हैं, एक तो वह जो ५० रुपए से कम के मकानों के सम्बन्ध में है और एक दूसरी वह जो ५० रुपये से अधिक किराये के मकानों के लिये सलाह देती है। इन दोनों के मेम्बर्स की अवधि एक वर्ष है।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---क्या सरकार प्रदेश के सब जिलों में इस कमेटी को रिवाइज करने का विचार कर रही है?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---जी हां, यह तो मैंने अभी निवेदन किया था।

श्री गौरीशंकरराय---क्या सरकार को ज्ञात है कि बहुत से जिलों में यह एडवाइजरी कमेटियां बुलाई ही नहीं जातीं?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---ऐसी कोई इत्तिला नहीं है।

इलाहाबाद जिले के लिए सीमेंट का कोटा

*१३---श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद जिले में १९५६ के प्रत्येक तीन माह में कितनी सीमेंट का कोटा दिया गया और उसमें कितना नगर में खर्च हुआ तथा जिले में कितना खर्च हुआ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---इलाहाबाद जिले में सन् १९५६ के प्रत्येक त्रिमास म सीमेन्ट की प्राप्ति तथा उसके नगर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण की सूची मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ४११ पर)

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में सब से ज्यादा सीमेंट किस तहसील में दिया गया और वह किस काम में लाया गया?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)---यह तो जो सूचना आपके सामने रखी गई है उसी से मालूम हो जायगा।

*१४-१६---श्री प्रतापसिंह---[२० अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

शाहजहांपुर जिले में नवनिर्वाचित ग्राम पंचायतों को मान्यता देने में विलम्ब

*१७---श्री देवनारायण भारतीय---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गांव पंचायतों तथा उनके प्रधानों को चुनाव हो जाने के बाद १६ मास व्यतीत हो जाने पर भी अब तक मान्यता क्यों नहीं दी गई है और पुरानी गांव पंचायतें तथा उनके प्रधान अब तक क्यों काम कर रहे हैं?

श्री रामस्वरूप यादव---नव-निर्वाचित गांव पंचायतों तथा उनके प्रधानों को मान्यता प्रदान की जा चुकी है। पुरानी गांव पंचायतें तथा उनके प्रधान अब काम नहीं कर रहे हैं।

*१८---श्री देवनारायण भारतीय---क्या सरकार को विदित है कि शाहजहांपुर में १ अप्रैल, १९५७ से ग्राम पंचायतों को मान्यता देकर काम करने की आज्ञा दी गई है?

श्री रामस्वरूप यादव---जी हां।

श्री देवनारायण भारतीय---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गांव सभाओं और उनके प्रधानों के चुनाव प्रदेश में नवम्बर, सन् १९५५ में हुये थे तो अप्रैल, सन् ५७ तक यह चुनाव बेकार क्यों रखे गये और उन ग्रामीण कमेटियों को काम करने की आज्ञा क्यों नहीं दी गई?

श्री रामस्वरूप यादव---ग्राम सभाओं का चुनाव नवम्बर, १९५५ में अवश्य हुआ था लेकिन शाहजहांपुर में पूरे जितने सदस्य होने चाहिये थे पूरे पर्चे दाखिल नहीं हुए। लिहाजा जगहें बहुत-सी नवम्बर, १९५५ में खाली हो गई थीं। उसके बाद फरवरी, १९५६ में तारीख नियत की गई और नवम्बर, १९५६ में पूरा चुनाव हो सका। उसके बाद यह आवश्यक था कि न्याय पंचायत के जो सदस्य चुने जाने थे उनके चुनाव के बाद ही ग्राम-सभायें संगठित होती हैं। इस वजह से उनका जो नोमीनेशन हुआ वह मार्च, सन् १९५७ में हुआ। इसलिये पहली अप्रैल से पहले संगठित नहीं हुई।

श्री देवनारायण भारतीय---जिन ग्रामसभाओं के पूरे सदस्य चुने जा चुके थे और उनके प्रधान चुने जा चुके थे तो क्या सरकार बतायेगी कि उन ग्रामसभाओं को काम करने की आज्ञा क्यों नहीं दी गई ?

श्री रामस्वरूप यादव---ऐसे आंकड़े तो मेरे पास नहीं हैं जिनसे यह पता चल सके कि कहां पूरा चुनाव हो चुका था। इसके लिये नोटिस चाहिये।

हमीरपुर जिले की राठ तहसील में सड़कों की निर्माण योजना

*१९---**श्री डूंगरसिंह** (जिला हमीरपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला हमीरपुर की राठ तहसील में प्रथम पंचवर्षीय योजना में कितने मील पक्की सड़क बनी ?

श्री गिरधारीलाल---प्रथम पंचवर्षीय योजना में हमीरपुर जिले में राठ तहसील में ओरई-राठ सड़क पर १२ मील लम्बाई में २ तह की गिट्टी इकट्ठा हो गई थी। इसके अतिरिक्त २२ मील लम्बी महोबा-राठ-मुसकेरा सड़क का पुनः निर्माण किया गया।

*२०---**श्री डूंगरसिंह**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला हमीरपुर की राठ तहसील में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कौन-कौन सी पक्की सड़कें बनाने की योजना है ?

श्री गिरधारीलाल---द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमीरपुर जिले की राठ तहसील में निम्नलिखित सड़कें पक्की बनाने की योजना है।

	मील	फ०	फि०
(१) धगवान-जरिया ..	६	०	०
(२) गोहद-जरिया	५	०	०
(३) चरखारी-मुसकेरा	१५	५	०

श्री डूंगरसिंह---क्या सरकार बतायेगी कि जब मुसकेरा-चरखारी रोड का कोई हिस्सा राठ तहसील से नहीं गुजरता तो वह राठ तहसील सड़क कैसे करार दे दी गई ?

श्री गिरधारीलाल---इसके लिये नोटिस चाहिये।

श्री डूंगरसिंह---क्या यह सत्य है कि राठ-उरई सड़क पहली पंचवर्षीय योजना में कम्पलीट होने को थी ?

श्री गिरधारीलाल---जी हां, यह बात ठीक है।

श्री डूंगरसिंह---क्या सरकार बतायेगी कि जब उसका प्रथम पंचवर्षीय योजना में कोई भाग नहीं बन पाया तो अभी कितनी पंचवर्षीय योजना उसके बनने में लगेंगी ?

श्री गिरधारीलाल---मैंने पहले ही कहा कि उरई-राठ सड़क जो है यह प्रथम पंचवर्षीय योजना में हमीरपुर में इस पर १२ मील पर दो तहें गिट्टी की इकट्ठी हो गई थीं।

जिला न्यायाधीश बरेली का निवास-स्थान न बन सकना

*२१---श्री जगदीशशरण अग्रवाल---क्या बरेली नगर में जिला प्रधान न्यायाधीश के लिये निवास-स्थान निर्माण करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब से और उसकी क्या स्थिति है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--जिला न्यायाधीश बरेली के लिये निवास-स्थान निर्माण करन का प्रश्न गत वर्षों में कई बार सरकार के सम्मुख आया है किन्तु धनाभाव के कारण यह अभी तक सम्भव नहीं हो सका है।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कब से यह प्रश्न सरकार के सामने है और क्या यह सही है कि इस निवास-स्थान के लिये नियत हुये सर्किट हाउस के बराबर एक अच्छी जमीन ६,७ साल से बराबर खाली पड़ी हुई है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--१९५५ में इसके सम्बन्ध में विचार किया गया था। १९५६ में भी सोचा गया कि हो सके और धन मिल सके तो स्वीकृति दो जाय निवास स्थान के लिये। किन्तु दोनों वर्षों में धन नहीं मिल सका और १९५७-५८ में धनाभाव के कारण विचार नहीं किया गया। जो माननीय सदस्य ने भूमि के सम्बन्ध में कहा, सम्भव है, हो सकती है। लेकिन धनाभाव के कारण अभी सम्भव नहीं है कि कोई भवन बनवाया जाय।

प्रदेशीय हाईकोर्ट में विचाराधीन मुकदमे

*२२---श्री शिवराज बहादुर (जिला बरेली)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ३० अप्रैल, १९५७ तक प्रदेशीय हाई कोर्ट (लखनऊ तथा इलाहाबाद) में कितने केसेज पेंडिंग हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---३९,२७९।

*२३---श्री शिवराज बहादुर---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पेंडिंग केसेज के शीघ्र समाप्त करने के लिये क्या प्रबंध किया गया है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--सरकार तथा हाईकोर्ट ने बकाया मुकदमों को शीघ्र निबटाने के लिये विभिन्न कार्यवाहियां की हैं। हाईकोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाई गई है और अतिरिक्त जजों की नियुक्तियां भी की जा रही हैं। १०,०००) तक की मालियत के मुकदमों की अपीलें अब हाईकोर्ट के बजाय जिला जज सुनेंगे। हाईकोर्ट में सेकेंड अपीलों और १०,०००) तक की फर्स्ट अपीलों को छपवाने की व्यवस्था का अन्त कर दिया गया है। हाईकोर्ट में सिंगिल जज अब २,०००) की जगह ५,०००) तक के मुकदमें सुनेंगे। इसके अतिरिक्त हाईकोर्ट में छुट्टियां कम कर दी गई हैं। अभी हाल में कानून में एक और संशोधन किया गया है जिससे खफीफा के मुकदमों में निगरानी हाईकोर्ट में न होकर डिस्ट्रिक्ट जज के यहां होगी। इस प्रकार हाईकोर्ट में नये मुकदमों का दायरा कम होगा और पुराने मुकदमों का निर्णय शीघ्र हो सकेगा।

श्री शिवराजबहादुर---क्या मंत्री जी बताने की जहमत करेंगे कि इनमें से कितनी क्रिमिनल अपीलें हैं, कितनी सिविल हैं और कितनी मिक्स्ड हैं।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---इसका तो ब्योरा मेरे पास नहीं है।

श्री शिवराजबहादुर---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इनमें से कितने ऐसे केसेज हैं जो सात साल से ज्यादा पुराने हैं और कितने ऐसे हैं जो तीन साल से ज्यादा पुराने हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---वैसे तो यह प्रश्न यहां सदन के सामने पहले आ चुका है और उसका उत्तर भी दिया जा चुका है। इस समय इसका ब्योरा मेरे पास नहीं है।

हरदोई जिले के बिलग्राम क्षेत्र में विधान सभा के उपचुनाव में बस का चालान

*२४---श्री मोहनलाल वर्मा (जिला हरदोई)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १५ अप्रैल, १९५६ को हरदोई में बिलग्राम क्षेत्र के विधान सभा के उपचुनाव में मतदाताओं को सवारियों पर लाने के अपराध में चुनाव कमीशन द्वारा जीप, पिकअप, लारी तथा ट्रक का चालान किया गया ? यदि हां, तो उस पर आगे क्या कार्यवाही हुई ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार इस सम्बन्ध में दो बस, एक जीप तथा एक पिकअप रोकी गयीं, परन्तु उनमें से केवल एक बस का चालान किया गया और शेष तीन गाड़ियां यथेष्ट प्रमाण न होने के कारण छोड़ दी गयीं।

उक्त बस से संबंधित मामला एस० डी० एम०, बिलग्राम के सम्मुख विचाराधीन है।

श्री मोहनलाल वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि यह शब्द रोकी गई, जो लिखा गया है तो क्या यह सही है कि यह दो बसें थाने में ले जायी गईं, वहां बाकायदा इनका चालान हुआ और दिन भर थाने के अन्दर वह बन्द रहीं ? शाम को जमानत पर छोड़ी गयीं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---रोकी गईं का आम अर्थ तो यही है कि उनको रोका गया, थाने में ले जाया गया लेकिन उसके विषय में चूंकि प्रमाण नहीं मिला इसलिये बाकायदा कोर्ट में चार्जशीट नहीं भेजी गई ?

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि जिस बस का मामला एस० डी० एम०, बिलग्राम के यहां चल रहा है उस बस का नम्बर क्या है और उसका ओनर कौन है ?

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य---बस का नम्बर है १०८ यू० एस० डी० और उसका ड्राइवर है वजीर अहमद और उसको लिया था गिरिजा शंकर ने।

श्री गौरीशंकर राय---क्या सरकार कृपा कर उन बसों और जीपों के नम्बर और उनके मालिकों के नाम बतायेगी जिनको छोड़ दिया गया ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---इसका ब्योरा तो मेरे पास नहीं है।

श्री सोहन लाल वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन बसों का जिक्र किया गया है उनको थाने के सामने सवारियां लाते हुये श्री शिवकुमार सेन एलेक्शन कमिश्नर और डी० आई० जी० सेंट्रल रेंज ने खुद देखा और चालान कराके बन्द कराया ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---अगर माननीय सदस्य का तात्पर्य उस बस केस से है जो न्यायालय के सामने है तो अध्यक्ष महोदय, मुझे आज्ञा देंगे कि मैं उसकी चर्चा अधिक नहीं कर सकता।

श्री अध्यक्ष---आगे इस पर प्रश्न पूछने की इजाजत मैं नहीं दूंगा।

*२५---श्री झारखंडेराय---[२० अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

ग्राम तहिरापुर, थाना दोहरीघाट, जिला आजमगढ़ के निवासियों का प्रार्थना-पत्र

*२६—श्री झारखंडेराय—क्या सरकार बतायेगी कि ग्राम तहिरापुर, थाना दोहरीघाट, जिला आजमगढ़ के निवासियों की ओर से कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है कि उक्त गांव को गौरीडीह गांव पंचायत से अलग करके नोबीपुर गांव पंचायत में शामिल कर दिया जाय ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां ।

*२७—श्री झारखंडे राय—क्या सरकार बतायेगी कि इस विषय में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री रामस्वरूप यादव—जिलास्तर पर जांच की जा रही है ।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि इसकी जांच कब से शुरू हुई और कब तक खत्म होने की आशा है ?

श्री रामस्वरूप यादव—दरख्वास्त संचालक, पंचायत राज के यहां १५-१-५७ को आई थी और जांच के खत्म होने में काफी समय लगने की आशा की जाती है । क्योंकि आजमगढ़ जिले में बहुत-सी ऐसी दरख्वास्तें गुजरी हैं ।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे इस बात को देखते हुए कि काफी टाइम हो चुका है इसको जल्दी कराने का कष्ट करेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव—जल्दी होने की बहुत संभावना नहीं है क्योंकि इस जिले में बहुत दरख्वास्तें आई हैं । साथ-साथ माल विभाग से परामर्श करना होगा । फिर सभी जगह ग्राम सभाओं और ग्राम पंचायतों का निर्वाचन करना पड़ेगा । इस सबमें समय काफी लगेगा ।

गोरखपुर जिले में सीमेंट वितरण की शिकायतें

*२८—श्री केशव पांडेय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर में सीमेंट वितरण की शिकायतें सरकार के पास आई हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जी हां, एक शिकायत प्राप्त हुई थी । "भारत" के दिनांक दिसम्बर ७, के प्रकाशन में यह शिकायत प्रकाशित हुई थी । शिकायत पर जांच की गई और सीमेंट के प्रार्थना-पत्रों पर ठीक तौर से न रखने की जो कमी थी उसे व्यवस्थित रूप से रखने के लिये प्रबंध किया गया ।

*२९—श्री केशव पांडेय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर D. S. O. आफिस में सन् १९५६-५७ में कुल कितनी दरख्वास्तें सीमेंट के लिये पड़ी हैं, उनमें कितनों को सीमेंट दिया गया है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—९,०७९ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये इनमें ६,८४५ प्रार्थना-पत्रों पर सीमेंट दिया गया ।

*३०—श्री केशव पांडेय—क्या सरकार गोरखपुर में सीमेंट का कोटा बढ़ाने पर विचार करेगी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—सभी जिलों के कोटे जनसंख्या और पूर्व खपत के आधार पर निर्धारित किये गये हैं । इस समय किसी विशेष जिले का कोटा औरों के अनुपात में बढ़ाना उपयुक्त नहीं समझा जाता ।

श्री केशव पांडेय---क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उस प्रकाशित समाचार के आधार पर गोरखपुर में सीमेंट वितरण के तरीके पर जांच की गई थी ?

श्री सैयद अली जहीर---जांच की गई थी और उससे यह मालूम हुआ कि दरख्वास्तें आई हैं कि वह कायदे से नहीं वितरित किया जा रहा था। जहां तक फेवरटिज्म का चार्ज था उसके मुताल्लिक यह मालूम हुआ कि इसमें कोई फेवरटिज्म की बात नहीं है। फिर भी उनको बदल दिया गया और दूसरा सप्लाई आफिसर भेज दिया गया और वहां के दफ्तर की हालत अब दुरुस्त हो गई है।

श्री केशव पांडेय---क्या सरकार को जानकारी है कि जिस समय यह शिकायत प्रकाशित हुई थी, कुछ चपरासियों ने आफिसर्स से इस वितरण के सम्बन्ध में शिकायत की कि पक्षपात हो रहा है ?

श्री सैयद अली जहीर---इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री मुरलीधर कुरील---क्या मंत्री महोदय बतलायेंगे कि प्रत्येक जिले में सीमेंट कम क्यों मिल रहा है ?

श्री सैयद अली जहीर---उसके कारण तो साफ हैं। हमारे यहां डेवलपमेन्ट के काम इतने ज्यादा बढ़े हुये हैं कि ज्यातातर सीमेंट सरकारी कामों में लग रहा है और प्राइवेट सेक्टर को देने के लिये सीमेंट की मिकदार कम है। इसका कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेन्ट से होता है, जितना वह एलाट करती है उतना हम बांटते हैं।

श्री केशव पांडेय---शिकायतें पुनः गोरखपुर में न हो सकें इसके लिये किस तरह से सीमेंट का वितरण गोरखपुर में किया जायगा ?

श्री सैयद अली जहीर---इसके लिये आम आदेश जा चुके हैं। गवर्नमेन्ट का जो कांस्ट्रक्शन प्रोग्राम है उसको तरजीह दी जायगी, जो बचेगा वह शहरों व देहातों में जिस हिसाब से पहले मिलता था मुख्तलिफ जिलों में उसी हिसाब से बांट दिया जायगा और उसी पर कारबन्द हैं।

श्री मोहनलाल वर्मा---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शहरों में जो मकान बनते हैं उनको एक एक दो दो वैगन्स के परमिट दिये जाते हैं ?

श्री सैयद अली जहीर---यह तो मुझे मालूम नहीं है अगर कोई खास केस हो तो आप मुझे बतलायें। लेकिन यह है कि जिनके नक्शे मंजूर हो जाते हैं उनको जहां तक हो सके सीमेंट पहुंचाये जाने की कोशिश की जाती है। मुझे मालूम नहीं है कि एक-एक, दो-दो, वैगन्स के परमिट दिये जाते हैं या नहीं।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि १९५६ की दरख्वास्तें अभी तक पेंडिंग हैं और १९५७ के आखिर वाली दरख्वास्तों पर सीमेंट मिल गई ?

श्री सैयद अली जहीर---जी नहीं, इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

बदायूं जिले में कोआपरेटिव फेडरेशन की बैलेन्स शीट न होना

*३१---**श्री टीकाराम** (जिला बदायूं)---क्या सरकार क ज्ञात है कि जिला बदायूं में कोआपरेटिव फेडरेशन द्वारा चलाये गये भट्ठे कितनी पूंजी से चलाये जा रहे हैं और कितने का लाभ हुआ है ?

सहकारिता मंत्री (श्री मोहन लाल गौतम)---५८,१६७ रुपये। बैलेन्सशीट अभी तक नहीं बनी है लेकिन १९५६-५७ में ७,००० रुपये के लाभ की आशा है।

*३२--श्री टीकाराम--क्या सरकार को मालूम है कि जिला बदायूं में कोग्रापरेटिव फेडरेशन की प्राथमिक सोसाइटियां कितनी हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम--तीन ।

श्री टीकाराम--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उनके यहां नियमों में बैलेंसशीट बनाने की कोई खास तिथि है ?

श्री मोहनलाल गौतम--जी हां, नियम तो है और कोशिश की जाती है लेकिन कभी-कभी उनके पालन में कोताही हो जाती है ।

श्री टीकाराम--यदि हिसाब के मामले में ऐसी कोताही हुई तो फिर क्या कहना है ?

श्री अध्यक्ष--(सहकारिता मंत्री से) इसका आप कुछ जवाब देंगे ?

श्री मोहनलाल गौतम--इसके लिये मैं धन्यवाद देता हूं ।

श्री मोहनलाल वर्मा--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो भट्ठे के लाभ के बारे में बतलाया गया है तो वह कितनी ईंटों के आउटपुट पर हुआ ?

श्री मोहन लाल गौतम--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

बांसी, मेंहदावल बाजार, बाघनगर तथा बस्ती को मिलाने वाली सड़कों को पक्की करने की प्रार्थना

*३३--श्रीमती गेंदा देवी (जिला बस्ती)--क्या सरकार को मालूम है कि जिला बस्ती के अन्तर्गत बांसी से साथी होते हुये मेंहदावल बाजार तथा मेंहदावल बाजार से बाघनगर होते हुये बस्ती जो सड़कें जाती हैं उनकी हालत बहुत खराब है ?

श्री गिरधारीलाल--यह दोनों कच्ची सड़कें हैं अतः उनकी दशा अच्छी नहीं है ।

*३४--श्रीमती गेंदा देवी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन सड़कों को पक्की करने के लिये सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कोई ध्यान दिया है ? यदि हां, तो लिस्ट आफ प्रायरिटी में इनका कौन-सा नम्बर है ?

श्री गिरधारी लाल--प्रथम भाग--बस्ती-मेंहदावल सड़क के १० मील के पक्का करने की योजना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित है । योजना का सीमित आकार होने के कारण शेष सड़क को उसमें सम्मिलित करना सम्भव न हो सका ।

द्वितीय भाग--योजना के अन्तर्गत ली गई सड़कों की कोई प्रायरटी निश्चित नहीं की गई है ।

*३५--श्रीमती गेंदा देवी--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इन सड़कों के पक्की होने की कब तक आशा की जाती है ?

श्री गिरधारीलाल--मेंहदावल बाजार से बाघनगर होते हुये बस्ती जाने वाली सड़क पर योजना की अवधि में ही कार्य आरम्भ कर दिया जायगा । कार्य का पूरा होना उसके लिये मिलने वाली धनराशि पर निर्भर करता है ।

श्रीमती गेंदा देवी--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जो बस्ती-मेंहदावल सड़क को १० मील पक्की करने की योजना है तो वह सी० सी० ट्रक्वेज से आगे बनेगी या बस्ती से ही बनेगी ?

श्री गिरधारी लाल--बस्ती से ही पक्की की जायगी ।

श्रीमती गेंदादेवी---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जिला कांग्रेस कमेटी ने कोई प्रायोरिटी लिस्ट बनाकर नहीं भेजी है ?

श्री गिरधारीलाल---प्रायोरिटी लिस्ट तो बहुत जगह से आयी है ।

श्री गेंदासिंह---क्या यह सही है कि मेंहदावल बाजार बस्ती जिले की अच्छी मंडी है और उसको बस्ती से जोड़ना बहुत जरूरी है इसलिये सरकार उस सड़क को जल्दी से जल्दी पक्की करा देने पर विचार करेगी ?

श्री गिरधारीलाल---सरकार विचार करेगी ।

शाहजहांपुर में वाटर वर्क्स बनाने की योजना

*३६---श्री देवनारायण भारतीय---क्या सरकार शाहजहांपुर में वाटरवर्क्स बनाने की कोई योजना बना रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव---जी हां ।

श्री देवनारायण भारतीय---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि वाटर वर्क्स बनाने की योजना कब से विचाराधीन है और वह कब तक पूरी हो जायगी ?

श्री रामस्वरूप यादव---जहां तक योजना के पूरा होने का सवाल है वह केन्द्रीय सहायता के ऊपर निर्भर है । द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जैसी सहायता मिलेगी वैसी ही काम की प्रगति हो सकती है इसलिये यह नहीं बताया जा सकता है कि कब पूरी हो जायगी ।

श्री देवनारायण भारतीय---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरकार उसमें कितने व्यय का अनुमान करती है । और प्रान्तीय सरकार कितना व्यय देने के लिये तैयार है ?

श्री रामस्वरूप यादव---सरकार का अनुमान २० लाख रुपये का है । प्रान्तीय सरकार ने तो अभी कोई रुपया देने का वादा नहीं किया है ।

*३७-३८---श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)---[२० अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किये गये ।]

फैजाबाद जिले की टांडा तहसील में राशनिंग की दुकानें खोलने के लिए आदेश

*३९---श्री सुखराम दास (जिला फैजाबाद) (अनुपस्थित)---क्या सरकार तहसील टांडा (फैजाबाद) में राशनिंग की व्यवस्था करने की कृपा करेगी ?

श्री सैयद अली जहीर---टांडा में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें खोलने के लिये आदेश जारी कर दिये गये हैं और गल्ला बिकना शुरू हो गया है ।

खाद्यान्नों की विधिवत् राशनिंग की व्यवस्था इस समय राज्य के किसी भी क्षेत्र में लागू नहीं है, और न इसे कहीं लागू करने का सरकार का विचार है ।

*४०---श्री नारायणदत्त तिवारी---[२० अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया ।]

गाजीपुर जिले के जंगीपुर बाजार में लगाये गये नल

*४१---श्री यमुनासिंह (जिला गाजीपुर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार को मालूम है कि गाजीपुर जिले के जंगीपुर बाजार में पानी के कितने नल लग चुके हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---दस नल लग चुके हैं ।

*४२--श्री यमुनासिंह (अनुपस्थित)--क्या सरकार बतलाने की दया करेगी कि उनको लगे कितने मास बीत चुके और वे पानी क्यों नहीं देते ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--ये पानी के नल फरवरी, १९५७ में लगे थे, परन्तु लगातार बिजली न मिलने के कारण दैनिक जल वितरण में बाधा पड़ रही थी, किन्तु अब बिजली लगातार मिलने लगी है और इससे इन नलों में पानी पहुंच रहा है।

*४३--श्री प्रताप सिंह--[१३ अगस्त, १९५७ के लिये प्रश्न संख्या ८३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*४४--श्री कल्याणचन्द मोहिले--[२७ अगस्त, १९५७ के लिये प्रश्न संख्या १८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*४५--श्री रामसुन्दर पांडेय--[इस प्रश्न का उत्तर २९ जुलाई, १९५७ को प्रश्न संख्या ६२ के अन्तर्गत दिया गया।]

सहारनपुर जिले में सीमेंट का कोटा

*४६--श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)--क्या सरकार बतलायेगी कि सन् १९५७ के पहले ६ महीनों में सहारनपुर जिले में कुल कितना सीमेंट आया और वह कोटे से कितना कम रहा ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--१९५७ के पहले ६ महीनों में सहारनपुर जिले में कुल २,१३९ टन सीमेंट प्राप्त हुआ जो वहां के निर्धारित कोटा २,००१ टन से १३८ टन अधिक था।

*४७--श्री दीनदयालु शास्त्री--क्या सरकार बतलायेगी कि ऊपर लिखी अवधि में हरद्वार में कितना सीमेंट आया और वह कोटे से कितना कम रहा ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--उपरोक्त समय में ९२ टन सीमेंट हरद्वार में प्राप्त हुआ। हरद्वार के लिये उस समय तक सीमेंट का कोई अलग से कोटा नहीं था, इसलिये वहां सीमेंट कोटे से कम या अधिक आने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री दीनदयालु शास्त्री--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अब हरद्वार को सीमेंट का कितना कोटा दिये जाने का निश्चय हुआ है ?

श्री सैयद अली जहीर--अध्यक्ष महोदय, इस मामले में अभी ८ मई, १९५७ को आदेश जारी हुये हैं कि तहसीलों के हिसाब से भी कोटे अलग-अलग कर दिये जायं। खयाल यह है कि हरद्वार के लिये भी इस सिलसिले में कोटा अलग कर दिया जायगा। कितना होगा यह अभी नहीं बतलाया जा सकता।

*४८-४९--श्री मिहरबानसिंह (जिला इटावा)--[२० अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

*५०--श्री इन्दुभूषण गुप्त (जिला आजमगढ़)--[२० अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

*५१--श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--[२० अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

नोट--तारांकित प्रश्न ४७ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

*५२--श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)--[२० अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

बिजनौर जिले में सड़कों की निर्माण योजना

*५३--श्रीमती चन्द्रावती (जिला बिजनौर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बिजनौर में दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कौन-कौन सी नई सड़कें बन रही हैं तथा बनेंगी ?

श्री गिरधारीलाल--

सड़कें जो बन रही हैं

सड़कें	लम्बाई	अनुमानित लागत
		रु०
चांदपुर-खानपुर-दतियाना मार्ग को पक्का करना	१० मील	५,७८,०००

सड़कें जो बनेंगी

(१) बिदुरकुटी फीडर रोड का पुनर्निर्माण	४ फर्लांग	१४,०००

*५४--श्रीमती चन्द्रावती--क्या सरकार जिला बिजनौर में कच्ची सड़क जो झालू होती हुई मुरादाबाद को जाती है, उसे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पक्की कराने को सोच रही है ?

श्री गिरधारीलाल--जी नहीं।

*५५-५६--श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)--[२० अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

*५७-५८--श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)--[इन प्रश्नों का उत्तर २ अगस्त, १९५७ को प्रश्न संख्या ८३-८४ के अन्तर्गत दिया गया।]

*५९--श्री रामस्वरूप वर्मा--[२० अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

*६०-६१--श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह (जिला गोंडा)--[२० अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

*६२-६४--श्री राजकुमार शर्मा (जिला मिर्जापुर)--[२० अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

*६५-६६--श्री नत्थूसिंह (जिला मैनपुरी)--[२० अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

खीरी जिले के बरबर घाट, गोमती नदी पर पुल निर्माण योजना

*६७--श्री मन्नालाल (जिला खीरी)--क्या सरकार बताने की कृपा करगी कि जिला खीरी के बरबर घाट गोमती नदी पर पुल कब तक बन जायेगा ?

श्री गिरधारीलाल--यह पुल आर० सी० सी० टी० बीम (R. C. C. T. Beam) का बनगा। इस कार्य के लिये टैंडर मांगे जा रहे हैं और वर्षा के बाद कार्य आरम्भ हो जायेगा।

खीरी जिले में बनने वाली सड़कें

*६८--श्री मन्नालाल--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला खीरी में दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कौन-कौन सी सड़कें बन रही हैं तथा बनेंगी ?

श्री गिरधारीलाल--जिला खीरी में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बनने वाली सड़कों की सूची सदस्य महोदय के मेज पर रखी है। इनमें से क्रमांक १--१२ तथा १५--१७ से १९ व २२ पर लिखित सड़कों का निर्माण स्वीकृत किया जा चुका है। शेष सड़कों का निर्माण योजना के आगामी वर्षों में आरम्भ किया जायगा।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ४१२-४१३ पर)

*६९--श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)--[१३ अगस्त, १९५७ के लिये प्रश्न संख्या ८४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

सिविल कोर्ट, फर्रुखाबाद के मातहत अमीनों की ग्रेडेशन लिस्ट की कथित शिकायत

*७०--श्री गौरीशंकर राय--क्या सरकार के पास सिविल कोर्ट, फर्रुखाबाद के मातहत अमीनों की ग्रेडेशन लिस्ट ठीक प्रकार न रखे जाने के सम्बन्ध में कोई शिकायत आई है? यदि हां, तो क्या?

श्री सैयद अली जहीर--जी नहीं।

*७१-७२--श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)--[२० अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

उच्च न्यायालय द्वारा घोषित अल्ट्रावायर्स कानून

*७३--श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १९५० से अप्रैल, १९५७ तक उत्तर प्रदेश के कितने कानूनों को उच्च न्यायालय ने 'Ultra vires' करार दिया है?

श्री सैयद अली जहीर--माननीय सदस्य कृपया सन् १९५० से सन् १९५७ तक की ला रिपोर्ट्स देख लें, जिसमें यह सूचना मिल जायेगी।

*७४-७५--श्री लक्ष्मणराव कदम--[२० अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

*७६--श्री अमरेशचन्द्र पांडेय (जिला मिर्जापुर)--[२६ अगस्त, १९५७ के लिये प्रश्न संख्या ४१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*७७--श्री अमरेशचन्द्र पांडेय--[१२ अगस्त, १९५७ के लिये प्रश्न संख्या ६७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

मुजफ्फरनगर जिले में सीमेंट का वितरण

*७८--श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मुजफ्फरनगर जिले में १९५५-५६ व १९५६-५७ में अलग-अलग कितना सीमेंट किस-किस सीमेंट फैक्ट्री से प्राप्त हुआ?

*७९--उक्त दोनों वर्षों में प्राप्त सीमेंट का वितरण अलग-अलग वर्ष में किस प्रकार हुआ अर्थात् कितने प्रतिशत नियोजन विभाग को, कितने प्रतिशत शहरों व कस्बों तथा कितने प्रतिशत ग्रामों को दिया गया?

श्री सैयद अली जहीर--मुजफ्फरनगर जिले में १९५५-५६ व १९५६-५७ में विभिन्न सीमेन्ट फैक्टरियों से प्राप्त तथा उसके १९५५-५६ व १९५६-५७ में वितरण सम्बन्धी सूचना मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ४१४ पर)

*८०-८१--श्री शिवराजबहादुर (जिला बरेली)--[स्थानान्तरित किये गये।]

बरेली जिले में नदियों पर बनने वाले पुल

*८२--श्री शिवराज बहादुर--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उसने द्वितीय पंचवर्षीय योजाना के अन्तर्गत जिला बरेली की किन-किन नदियों के किस-किस स्थान पर पुल बनवाने की योजना रखी है ?

श्री गिरधारीलाल--(१) बरेली-मथुरा प्रान्तीय मार्ग में रामगंगा नदी पर।
(२) बहेड़ी-बंजरिया सड़क में किच्छा नदी पर।

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में १९५४-५५ में दायर सिविल अपीलें

*८३--श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार बतायेगी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ बेंच में सन् १९५४-५५ में कितनी Regular First Civil Appeals दायर हुईं और उनमें से कितनी पर हाई कोर्ट ने निर्णय दे दिया ?

श्री सैयद अली जहीर--इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में सन् १९५४ में ७३ नियमित प्रथम सिविल अपीलें दायर हुईं और उनमें से ४ पर हाई कोर्ट ने निर्णय दे दिया है। सन् १९५५ में ८३ ऐसी अपीलें दायर हुईं जिनमें से ५ पर हाई कोर्ट ने निर्णय दे दिया है।

*८४--श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार बतायेगी कि उपर्युक्त अपीलों में से कितनी First Civil Appeals का Record प्रिंट हो चुका है ?

श्री सैयद अली जहीर--उपर्युक्त सन् १९५४ की अपीलों में से एक अपील का रेकार्ड प्रिंट और दो का टाइप हो चुका है। सन् १९५५ की अपीलों में से एक का रेकार्ड टाइप हुआ है।

*८५--श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)--[२० अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

जालौन जिले में देहाती क्षेत्र का सीमेंट कोटा अलग करने की प्रार्थना

*८६--राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)--क्या सरकार जिला जालौन में देहाती क्षेत्र का सीमेंट का कोटा अलग कर देगी और उसको तहसीलवार तथा अदालती क्षेत्र-वार बटवाने का प्रबन्ध करेगी ?

श्री सैयद अली जहीर--ग्रामीण क्षेत्रों में सीमेन्ट के वितरण के सम्बन्ध में गश्ती आदेश-पत्र जारी किये जा चुके हैं, जिनमें यह बताया गया है कि प्रत्येक तिमाही में जिला नियोजन समिति की स्वीकृति लेकर जिले के सीमेन्ट का कोटा तहसीलवार तथा राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंडवार बटवारा कर दिया जाय। इसलिये किसी विशेष जिले के लिये इस सम्बन्ध में किसी आदेश देने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती।

रायबरेली-फैजाबाद रोड पर गोमती नदी के आम घाट पुल की निर्माण योजना

*८७--श्री गुरुप्रसादसिंह (जिला सुल्तानपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रायबरेली-फैजाबाद रोड पर गोमती नदी के ऊपर आम घाट पुल के निर्माण-कार्य में कहां तक प्रगति हुई है ?

श्री गिरधारीलाल--अप्रैल, १९५६ में इस पुल का निर्माण स्वीकृत किया गया था। पुल की लागत में वृद्धि हो जाने के कारण विधान सभा की पुनः स्वीकृति लेना आवश्यक हो गया है। यह स्वीकृति १९५७-५८ की नई मांगों के द्वारा प्राप्त की जा रही है और कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

बाराबंकी जिले में नमक का आयात

*८८--श्री जंगबहादुर वर्मा--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बाराबंकी जिले में कौन-सा नमक आता है?

श्री सैयद अली जहीर--कांडला नमक।

बादा जिले की बबेरू-अतर्रा रोड के निर्माण की योजना

*८९--श्री रामसनेही भारतीय (जिला बांदा)--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला बांदा की बबेरू-अतर्रा रोड का निर्माण कार्य जो कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत लिया जा चुका है, कब से प्रारम्भ होगा?

श्री गिरधारीलाल--द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में ही इस सड़क पर कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

*९०--श्री रामसनेही भारतीय--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या उक्त सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में एस्टीमेट सरकार के समक्ष प्रस्तुत हो चुका है? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है?

श्री गिरधारीलाल--प्रथम भाग--जी नहीं। द्वितीय भाग--प्रश्न नहीं उठता।

इटावा जिले में भर्थना टाउन एरिया का गन्दा पानी निकालने की व्यवस्था के लिए प्रार्थना

*९१--श्री मिहरबानसिंह--क्या सरकार इटावा जिले के टाउन एरिया भर्थना की २० हजार जनता के स्वास्थ्य की रक्षा के लिये कस्बे के गंदले पानी को बाहर निकालने की कोई योजना बनाने पर विचार करेगी?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--उत्तर प्रदेश के स्वायत्त शासन विभाग ने भर्थना टाउन एरिया का गंदला पानी बाहर निकालने की एक योजना जिसकी कीमत लगभग १४,००० रुपये थी सन् १९४०-४१ में बनाई थी और इसको टाउन एरिया के पास स्वीकृति के लिये भेजा था। टाउन एरिया भर्थना ने अभी तक उसकी स्वीकृति नहीं भेजी है। शासन द्वारा ऐसी कोई परियोजना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं की गई है।

*९२--श्री मोहनलाल वर्मा--[२० अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

हरदोई जिले में डी० सी० डी० एफ० का सुपरसीड होना

*९३--श्री मोहनलाल वर्मा--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जिला हरदोई में डी० सी० डी० एफ० कब से सुपरसीडेड ((Superseded)) हैं?

श्री मोहनलाल गौतम--मार्च, १९५२ से।

पंचायत मंत्रियों को स्थायी न करना

*९४--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या स्वशासन मंत्री को ज्ञात है कि पंचायत मंत्रियों में से अब तक कोई स्थायी नहीं किया जा सका है? यदि हां तो क्यों?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---जी हां। यह ठीक है कि पंचायत मंत्रियों में से अब तक किसी को स्थायी नहीं किया जा सका है। इसके कारण निम्नलिखित हैं---

(क) पंचायत मंत्री ग्राम सभाओं के कर्मचारी हैं। अतः सरकार की ओर से इनके स्थायीकरण का प्रश्न नहीं उठता।

(ख) ग्राम सभाओं की आर्थिक दशा ठीक नहीं है और वे मंत्रियों के वेतन को भी देने में असमर्थ हैं। शासन इनके वेतन के लिये प्रति वर्ष सहायक अनुदान देता है। ऐसी दशा में ग्राम सभाओं को मंत्रियों के स्थायीकरण के लिए शासन कोई निर्देश देना उचित नहीं समझता।

(ग) ग्राम स्तर पर समस्त कर्मचारियों के एकीकरण का भी प्रश्न विचाराधीन है। पंचायत मंत्री ग्राम स्तर के कर्मचारी हैं। इसलिये एकीकरण के प्रश्न पर अन्तिम निर्णय तक मंत्रियों के स्थायीकरण पर कोई विचार करना उपयुक्त भी नहीं है।

खीरी जिले में शारदा नदी के ऐरा घाट पर पैन्टून ब्रिज की आवश्यकता

*९५---श्री जगन्नाथप्रसाद (जिला खीरी)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला खीरी में शारदा नदी में ऐरा घाट पर पैन्टून पुल बनाने की कोई योजना कार्यान्वित करने का उसका विचार है? यदि हां, तो इसका बनना कब प्रारम्भ हो जायगा?

श्री गिरधारीलाल---प्रथम भाग---जी नहीं। द्वितीय भाग---प्रश्न नहीं उठता।

पी० डब्ल्यू० डी० सम्बन्धी एस्टीमेट्स कमेटी की सिफारिशें

*९६---श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पी० डब्ल्यू० डी० से सम्बन्धित एस्टीमेट्स कमेटी की कौन-कौन सी सिफारिशें ऐसी हैं जिन्हें सरकार ने स्वीकार नहीं किया है और उसके क्या कारण हैं?

श्री गिरधारीलाल---सरकार ने एस्टीमेट्स कमेटी की किसी भी सिफारिश को अन्तिम रूप से अस्वीकृत नहीं किया है। कमेटी की सिफारिशों तथा विभागीय प्रतिवेदन के मध्य के मतभेदों का परीक्षण विभाग के एक सम्पर्क अधिकारी तथा एस्टीमेट्स कमेटी की एक परीक्षण समिति द्वारा किया जायगा। विभाग ने सम्पर्क अधिकारी की नियुक्ति कर दी है, किन्तु एस्टीमेट्स कमेटी ने परीक्षण समिति की नियुक्ति अभी तक नहीं की है। अतः अब तक सरकार ने संबंधित विषय में अंतिम रूप से कोई निर्णय नहीं लिया है।

*९७---श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी---[१२ अगस्त, १९५७ के लिये प्रश्न संख्या ६८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

झांसी जिले के बरवासागर सब्जी व्यापार को सहकारिता के आधार पर चलाने का विचार

*९८---श्री गज्जूराम (जिला झांसी)---क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला झांसी, तहसील झांसी का स्थान बरवासागर सब्जी की एक अच्छी व्यापारिक मंडी है, जहां से देश के अनेक प्रदेशों के मुख्य-मुख्य नगरों को सब्जी भेजी जाती है एवं वहां के निवासियों की जो कि अधिक तादाद में किसान ही हैं जीविका का यही सब्जी व्यापार मुख्य साधन है ?

श्री मोहन लाल गौतम---जी हां।

*९९--श्री गज्जूराम--क्या सरकार सब्जी के व्यापार से प्राप्त मुनाफे को किसानों के पास तक उचित रूप में पहुंचाने के लिये कोआपरेटिव आधार पर कोई योजना बनाने को कृपा करेगी ?

श्री मोहनलाल गौतम--यह मामला विचाराधीन है ।

*१००--श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)--[२२ अगस्त, १९५७ के लिये प्रश्न संख्या ५४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*१०१--श्री दीनदयालु शास्त्री--[२० अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया ।]

झांसी जिले की ललितपुर, महरौनी तहसील में ग्राम-सभाओं की भूमि

*१०२--श्री गज्जूराम--क्या सरकार कृपा कर के बतायेगी कि जिला झांसी, तहसील ललितपुर, महरौनी में सन् १९५१ से सन् १९५६ तक किन-किन ग्राम सभाओं की भूमि जंगल विभाग ने अपने अधिकार में ली है ?

श्री सैयद अली जहीर--वन विभाग ने ऐसी कोई भूमि नहीं ली है ।

पंचायतों के चुनाव में काम करने वाले जिला बोर्ड, आजमगढ़ के अध्यापकों को भत्ता न मिलना

*१०३--श्री मुक्तिनाथराय (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गत १९५६ ई० के ग्राम पंचायतों के चुनाव कराने में नियुक्त जिला बोर्ड, आजमगढ़ के अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों को भत्ता देने की व्यवस्था सरकार ने की थी ? यदि हां, तो क्या सरकार ने भत्ते की धनराशि उपर्युक्त कर्मचारियों को दे दी है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--(क) पंचायतों के चुनाव आरम्भ होने के पूर्व ही गत सितम्बर, १९५५ में संबंधित अधिकारियों को आदेशित किया गया था कि वे पंचायत कार्य पर लगाये गये अपने कर्मचारियों का दैनिक भत्ता आदि अपने बजट से दे दें तथा तदुपरान्त शासन से उक्त धन की प्राप्ति (re-imbursement) की व्यवस्था करें ।

(ख) जिलाधीश आजमगढ़ से प्राप्त हुई सूचना से पता चलता है कि जिला बोर्ड आजमगढ़ इस सम्बन्ध में शीघ्र ही भुगतान करने जा रहा है । शासन द्वारा re-imbursement का विषय भुगतान के पश्चात् ही उठेगा ।

कोसी नगरपालिका को अनुदान

*१०४--श्री रामहेर्तासिह (जिला मथुरा)--क्या स्वशासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कोसी नगरपालिका को सन् १९५२ से १९५६ तक कितना-कितना रुपया, किस-किस मद में दिया गया तथा किस-किस मद के लिये, कितना-कितना रुपया, कोसी नगरपालिका द्वारा मांगा गया था ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--कोसी, नगरपालिका को १९५२ से १९५६ तक जिस-जिस मद में, जितनी-जितनी धनराशि अनुदान अथवा ऋण के रूप में दी गई है उसके आंकड़े नीचे दिये गये हैं--

अनुदान का विवरण	वित्तीय वर्ष	अनुदान		
		रु०	आ०	पा०
१--चिकित्सा सम्बन्धी आवर्त्तक अनुदान	१९५२-५३	४५०	०	०
	१९५३-५४	४५०	०	०
	१९५४-५५	४५०	०	०
	१९५५-५६	४५०	०	०

अनुदान का विवरण		वित्तीय वर्ष	अनुदान		
२--शिक्षा सम्बन्धी . .	. . . .	१९५२-५३	५९४	०	०
आवर्त्तक अनुदान	. . . .	१९५३-५४	६१९	०	०
		१९५४-५५	६४४	०	०
		१९५५-५६	६६८	०	०
३--जुर्मानों से होने वाली आय को हानि हीन करने के लिये		१९५२-५३	१२१४	८	०
		१९५३-५४	१३०७	०	०
		१९५४-५५	२६०७	१३	०
		१९५५-५६	७७६	२	०
४--सड़क निर्माण हेतु	. . . .	१९५२-५३	३०,०००	०	०
अनावर्त्तक अनुदान	. . . .	१९५३-५४	३०,०००	०	०
		१९५४-५५	१०,४००	०	०
		१९५५-५६	८,७००	०	०
५--जल वितरण योजना हेतु ऋण (Loan for water supply scheme)	. . . .	१९५२-५३	५०,०००	०	०
	. .	१९५३-५४	५०,०००	०	०
		१९५४-५५	६५,०००	०	०

अध्यक्ष, नगरपालिका कोसी ने १९५५-५६ में "मलमूत्र उपयोग योजना" (sewage utilization scheme) के अन्तर्गत सरकार से १,०२,९०० रुपये की मांग की थी।

*१०५--**श्री इन्दुभूषण गुप्त**--[१३ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

सहारनपुर-बागपत सड़क के निर्माण में प्रगति

*१०६--**श्री वीरेन्द्र वर्मा**--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बतायेंगे कि सहारनपुर-बागपत सड़क के निर्माण की क्या प्रगति है और वह देहली तक कब तक तैयार हो जायेगी ?

श्री गिरधारीलाल--लगभग ४-५ मील को छोड़कर जो मुजफ्फरनगर जिले में शामली तथा ऐलम में पड़ते हैं, शेष सड़क बन चुकी है। शामली में मिट्टी तथा पुलिया का कार्य समाप्त हो चुका है। ऐलम में अभी हाल ही में कार्य आरम्भ किया गया है। शामली और ऐलम पर कार्य मार्च, १९५८ तक पूरा हो जायेगा। बागपत से देहली तक के भाग पर जो कार्य होना शेष है वह अगस्त, १९५७ तक पूरा हो जायेगा।

*१०७--**श्री वीरेन्द्र वर्मा**--क्या उक्त सड़क की चौड़ाई मेरठ, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर जिलों में भिन्न-भिन्न है ?

श्री गिरधारीलाल--मेरठ और सहारनपुर जिलों में सड़क की चौड़ाई १२ फुट है। मुजफ्फरनगर जिले में इसकी चौड़ाई जो अभी ९ फुट है बढ़ा कर १२ फुट की जा रही है।

सीतापुर जिले में ग्राम-पंचायत टंडई कलां में गबन की जांच

*१०८--**श्री ताराचन्द माहेश्वरी** (जिला सीतापुर)--क्या स्वशासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जुलाई, सन् १९५६ में जिला पंचायत राज कार्यालय सीतापुर द्वारा ग्राम पंचायत टंडई कलां में गबन के मामले की जांच हुई थी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--जी हां।

*१०९--**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**--यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--क्षेत्रीय विकास अधिकारी द्वारा जांच कराने पर कोई बात प्रमाणित नहीं हुआ ।

*११०--श्री ताराचन्द माहेश्वरी--यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--प्रश्न ही नहीं उठता ।

अतारांकित प्रश्न

१--श्री गज्जूराम--[१४ अगस्त, १९५७ के लिये प्रश्न संख्या १ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

कानपुर जिले में सड़कों की निर्माण योजना

२--श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)--क्या निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कितनी नई सड़कें कानपुर जिले में निर्मित होनी हैं और उनमें कितनी धनराशि व्यय होगी तथा उनकी क्या लम्बाई होगी और नई सड़कों के अलावा किन-किन पुरानी सड़कों का जीर्णोद्धार होना है तथा उन पर कितना व्यय होगा ?

श्री गिरधारीलाल--यह सूचना सदस्य महोदय की मेज पर रखी हुई सूची में दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ४१५ पर)

पूर्वी जिलों में, विशेषकर गोरखपुर जिले में घाघरा, राप्ती आदि नदियों की बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति पर विवाद करने के लिये कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना (क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष--श्री मदन पांडेय जी का कामरोको प्रस्ताव था कि पूर्वी जिलों और विशेषकर गोरखपुर जिले में घाघरा, राप्ती तथा दूसरी सहायक नदियों, आमी, कुआनों, राहिन, छोटी गंडक तथा बड़ी गंडक में भयानक बाढ़ के कारण इन नदियों के किनारे बसने वाले हजारों आदमियों का जीवन विपन्न हो उठा है । इस सिलसिले में मैंने माननीय माल मंत्री जी से कल पूछा था और उन्होंने आज इसके बारे में जानकारी देने के लिये कहा था ।

*माल मंत्री (श्री चरणसिंह)--अध्यक्ष महोदय, कलेक्टर से फोन के जरिये मालूम हुआ कि अभी वहां किसी नदी में बाढ़ आ गई हो ऐसा नहीं कहा जा सकता । नदियों में पानी चढ़ा है, लेकिन अपने बेड से बाहर नहीं निकली हैं । अभी वहां के कलेक्टर यहां तीसरी अगस्त को आये थे तो उस वक्त बातचीत के दौरान में उन्होंने बतलाया कि उन्होंने ऐसा इंतजाम कर दिया है कि इत्तला मिलने के ६ घंटे के अन्दर जहां कहीं भी बाढ़ आयेगी और लोगों के तकलीफ में होने की आशंका होगी तो इम्दाद पहुंचा सकेंगे । तीन सौ नावों का इंतजाम कर लिया गया है । अभी उनके काम करने की जरूरत नहीं आयी है मगर कुछ पेशगी दे दिया गया है और उनको इन्गेज कर लिया गया है कि अगर जरूरत होगी तो वह कलेक्टर के पास आ जायेंगी । हमने १० हजार रुपये पहले ही से हर कलेक्टर के पास दे दिये हैं जिससे वे तत्काल इम्दाद पहुंचा सकें । जो फ्लड पोस्ट्स हैं उनमें सामान जमा कर लिया गया है । फ्लड कमेटीज वगैरह की मीटिंग्स कर चुके हैं और सब इंतिजाम हो चुका है, कोई आशंका की बात नहीं है । बाराबंकी में जो घाघरा में बाढ़ है, वह मीडियम फ्लड है और देवरिया में माइल्ड फ्लड है, तो गोरखपुर में कैसे फ्लड होवेगा यह समझ में नहीं आता । हां, जिले में कुछ नालों ने परेशान किया था और २ आदमी जो उनको क्रास कर रहे थे वे डूबकर मर गये बाकी किसी आदमी की जान जाया नहीं हुई और किसी पशु के मरने की भी खबर नहीं है ।

(श्री मदन पांडेय के खड़े होने पर)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

†५ अगस्त, १९५७ की कार्यवाही से ।

श्री अध्यक्ष—मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं। अगर आपको कोई और जानकारी देनी थी तो पहले इसी के साथ-साथ देनी चाहिये थी। मैंने आपकी और सदन की मालूमात के लिये मंत्री जी से कहा था कि जानकारी हासिल करके सदन को दे दें।

आगरा जेल में सोशलिस्ट सत्याग्रही, श्री रामसिंह की मृत्यु के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष—दूसरा कामरोको प्रस्ताव श्री रामसिंह चौहान का था कि आगरा सेंट्रल जेल में इटावा जिले के सोशलिस्ट सत्याग्रही श्री राम सिंह की जेल अधिकारियों और डाक्टर की असावधानी से चिकित्सा न होने के कारण २ अगस्त को मृत्यु हो गयी। यह मैंने कल पढ़कर सुना दिया था। माननीय मंत्री जी ने कहा था कि आज वे इसके बारे में खबर देंगे।

समाज सुरक्षा राज्य मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)—अध्यक्ष महोदय, श्री रामसिंह आगरा सेंट्रल जेल में २४ मई, सन् १९५७ को फतेहगढ़ जिला जेल से तब्दील हो कर आये थे। उन्हें १४ मई, सन् १९५७ को ६ महीने की सजा हुई थी। उनकी सेहत पहले ही से अच्छी नहीं थी और वह एक महीने ६ दिन तक अस्पताल में रखे गये और २४ जूलाई को वहां से डिस्चार्ज हुये। वे बराबर अपनी कमजोरी की शिकायत करते रहे और उन्हें ऐनीमिया और जनरल डेबिलिटी तजवीज की गयी। ग्लूकोज इंजेक्शंस, लिवर एक्स्ट्रैक्ट और विटामिन बी के इंजेक्शन्स उनको इस्तेमाल कराये गये। २४ जुलाई, को जब वे डिस्चार्ज हुये थे तब उनका वजन २ पौंड बढ़ चुका था। दूसरी अगस्त को शाम को ८ बजे जब वह खाना खाकर और कैदियों के साथ टहल रहे थे, उनको एकाएक खांसी आयी और बड़ी मिकदार में खून आना शुरू हुआ। १५ मिनट के अन्दर जेल का कम्पाउन्डर मौके पर पहुंच गया और उन्हें कोलोजीन और कोरोमीन के इंजेक्शन्स दिये गये और फौरन ही जेल सुपरिन्टेन्डेन्ट और सिविल सर्जन को खबर की गई। यह दोनों साढ़े आठ बजे तक वहां पहुंचे, लेकिन इसी बीच में उनकी मृत्यु हो चुकी थी। बाद में जिलाधीश को भी खबर की गई और उसी रात को १२ बजे से २ बजे रात तक एडीशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के जरिये मैजिस्टीरियल इंक्वायरी हुई और यह मालूम हुआ कि उनके दोनों फेफड़े खराब थे, इसी वजह से यह खून आया और उनकी मृत्यु हुई। अफसोस की बात यह है कि उनका मर्ज पहले से तशखीस नहीं हो सका। इस बारे में यह बताया गया है कि चूंकि उनको किसी वक्त बुखार नहीं रहता था और उनका वजन बजाय घटने के बढ़ा था इस वजह से उस तरफ खयाल नहीं गया। फिर भी यह मामला सीरियस है। इस की तफसीली इंक्वायरी करा कर मुनासिब कार्यवाही करने का इरादा है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—मैं यह जानना चाहूंगा कि जब एक महीना ६ या ४ दिन वह अस्पताल में रहे और उनकी सेहत खराब थी पहले से ही तो सरकार ने उनको रिहा क्यों नहीं किया ?

श्री मुजफ्फर हसन—उन्होंने खुद भी किसी वक्त यह शिकायत नहीं की कि उनको यह मर्ज है और जेल में भी जनरल डेबिलिटी और एनीमिया ही तजवीज हुआ और उसी का इलाज हुआ।

श्री अध्यक्ष—इसकी जानकारी.....

श्री रामसिंह चौहान वैद्य (जिला आगरा)—मैं इस सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं, जो मुझे सूचनायें मिली हैं उनके आधार पर.....

---

† ५ अगस्त, १९५७ की कार्यवाही से।

श्री अध्यक्ष---इस विषय में मैं इस समय इजाजत नहीं दूंगा। जब इस विभाग के बजट पर बहस होगी उस समय आप इसकी बात को कह सकते हैं। जो जानकारी सरकार को थी वह मैंने आपको करवा दी है। आप तैयार हो कर आइयेगा बहस के लिये।

श्री रामसिंह चौहान वैद्य---श्रीमन्, यह तो माननीय मंत्री जी के बयान से ही स्पष्ट प्रतीत होता है कि किस लापरवाही से उनकी मृत्यु हुई.....

श्री अध्यक्ष---उस इंक्वायरी के वायदे के बाद कोई कारण नहीं रहता कि कोई प्रश्न इस समय उठाया जाय।

मैं इसकी भी इजाजत नहीं देता हूं, क्योंकि यह सरकार का स्टेटमेंट अभी हो चुका है कि उसकी जांच करा कर उस पर वह कार्यवाही करेंगे। दूसरे इस विषय पर अगर कोई बहस करनी है तो पुलिस और जेल के अनुदान पर बहस के समय हो सकती है। उस समय यह प्रश्न उठाया जा सकता है।

जिला बाराबंकी में घाघरा नदी की बाढ़ से हुई क्षति के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---अभी चार कामरोको प्रस्ताव मेरे पास आये हैं। एक श्री जंगबहादुर वर्मा का है, जो इस प्रकार है---

"जिला बाराबंकी के रामसनेही घाट व तहसील फतेहपुर के अन्तर्गत घाघरा नदी में बाढ़ आने के कारण लगभग ७८ गांव बह गये हैं और हजारों बीघा फसल डूब गई है और लाख के करीब सम्पत्ति बर्बाद हो गई है। सरकार की ओर से सहायता न पहुंचने और इस बर्बादी के कारण निकट के जिलों में असंतोष और क्षोभ का वातावरण फैल गया है तथा परिस्थिति विषम हो गई है।

इस आवश्यक परिस्थिति पर विचार करने के लिये सदन आज अपना कार्य स्थगित करता है।"

इसके साथ कोई तहकीकात करके कोई रिपोर्ट आई हो ऐसी बात नहीं है। सिर्फ एक कागज पर यह चीज लिख दी और जैसा अभी माल मंत्री जी ने घाघरा की बाढ़ के बारे में कहा था कि बाढ़ शायद बाराबंकी में मीडियम प्रकार का साधारण हो।

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)---अगर आप इजाजत दें तो मैं बता सकता हूं।

श्री अध्यक्ष---ठीक है, कुछ विवरण दे दें।

*श्री चरणसिंह---कई दिन हुये जब बाराबंकी में घाघरा चढ़ गयी थी यानी ३१ जुलाई, को। उसकी इत्तला हमारे यहां दफ्तर में आयी हुई है। ३४८.५८ फुट हाइयस्ट लेविल था जो वहां पहुंचा और बाराबंकी में रिकार्ड किया गया। जो इस नदी पर खतरे का निशान है वह ३५१.५ है उससे अभी यह बाढ़ ३ फुट नीचे है। इससे जो रकबा प्रभावित हुआ वह १ लाख २८ हजार एकड़ है। फतेहपुर और रामसनेही घाट में ९९ गांव में पानी आया। २,८७८ आदमी और ६,१५७ मवेशियों को निकाला गया है। ९ मकान गिर गये, २५ जानवर नदी को पार करते हुये खत्म हो गये। बहुत से राज्यकर्मचारी वहां पर काम कर रहे हैं, उन लोगों ने बहुत से जानवरों और आदमियों को पानी से निकाला है। लोगों को वे काफी राहत पहुंचा रहे हैं। इस वक्त आखिरी जो हमारे पास इत्तला आयी है उसके मुताबिक नदी घट रही है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--(श्री जंगबहादुर वर्मा से) क्या इस वक्तव्य देने के बाद भी आप चाहते हैं कि इसको प्रेस किया जाय ?

श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)-- जी हां, मैं चाहता हूं कि जो कहा जा रहा है वह उतनी सहायता नहीं है, इसलिये इस पर बहस होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष---यह तो आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। आप कहते हैं कि ७८ गांवों को नुक्सान पहुंचा और वे ९९ बतला रहे हैं।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)-- उनकी तरफ से मैं कह रहा हूं कि जो सहायता दी जा रही है, वह पर्याप्त नहीं है।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं, यह कोई वजह माननीय सदस्य स्वयं नहीं बतला रहे हैं जिसकी वजह से इसको वे प्रेस कर रहे हों। उसके लिये सरकार कहती है कि हम कार्यवाही कर रहे हैं और वह नदी घट भी रही है। इसलिये इसमें कोई अर्जेन्सी नहीं है। मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

गाजीपुर जिले में चन्द्रप्रभा नहर के टूटने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---एक कामरोको प्रस्ताव श्री पब्बर राम जी का है जिसमें वह कहते हैं कि चन्द्रप्रभा कैनाल, गाजीपुर जिले के भाग में गहमर और मदौरा स्टेशनों के बीच में टूट गई है। हजारों एकड़ खरीफ की फसल पानी में डूब जाने से चौपट हो गई है। इससे किसानों में घोर असन्तोष व्याप्त हो गया है। अभी तक नहर विभाग अथवा अन्य प्रकार से कोई रिलीफ नहीं पहुंचाई गई है। इस परिस्थिति पर विचार हेतु यह सदन अपना कार्य-स्थगित करता है।

इस सम्बन्ध में ग्राम प्रधान विश्वनाथसिंह सूबेदार का तार आया है जिसमें लिखा है कि---

"canal broken several points between gahamar and madaura crops damaged this year also thousand acres of land submerged canal deptt taking no action."

(श्री पब्बर राम से) क्या आपने इस कैनाल के टूटने की और उसके ऊपर काम जो नहीं हो रहा है उसकी शिकायत सरकार को भेजी ? आपने इसमें यह नहीं लिखा कि आपने यह सूचना सरकार को दी और उसने इस पर कुछ कार्यवाही की नहीं। नहर वगैरा टूटा ही करती हैं। यह एक साधारण सा विषय है। इसका गवर्नमेंट से सीधा सम्बन्ध नहीं है, इसलिये मैं इसकी इजाजत नहीं देता। आपको चाहिये था कि आप गवर्नमेंट के पास यह तार भेज देते और कहते कि जो कार्यवाही कैनाल वालों को करनी चाहिये थी, वह नहीं कर रहे हैं और उस पर गवर्नमेंट ऐक्शन न लेती तब आप कामरोको प्रस्ताव ला सकत थे।

श्री पब्बरराम (जिला गाजीपुर)---अध्यक्ष महोदय, मैं इस ओर आपका ध्यान इसलिये और खींचना चाहता हूं कि पारसाल भी इस किस्म की घटना हो चुकी है और करोड़ों रुपये का नुक्सान इस जमुहारी तहसील में हुआ था। अब वही घटना फिर हो रही है। इसी एक कस्बे में २० मिनट के अन्दर साढ़े छः फीट पानी हो गया था और उससे लाखों रुपये का नुकसान हुआ था।

श्री अध्यक्ष--आपको मैंने बतलाया कि आपको पहले गवर्नमेंट के पास जाना चाहिये था यह कह कर कि यह टेलीग्राम मेरे पास आया है। अगर मंत्री जी कार्यवाही न करते तो आप यहां आ सकते थे। अगर कोई शिकायत आये और आप मंत्री जी के पास न जायं तो उस शिकायत के ऊपर यहां कामरोको प्रस्ताव नहीं आ सकता है। ऐसी शिकायतों पर सदन का काम नहीं रोका जा सकता।

सहारनपुर नगरपालिका के भंगियों की हड़ताल के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--एक कामरोको प्रस्ताव श्री झारखंडे राय जी का सहारनपुर नगरपालिका के भंगियों की हड़ताल के सम्बन्ध में इस प्रकार से है--

"सहारनपुर नगरपालिका के ७०० भंगियों की गत ३१ जुलाई से प्रारम्भ, हड़ताल तथा अधिकारियों की इस विषय में हठधर्मी और दमनकारी नीति से उत्पन्न गम्भीर परिस्थिति पर विचार हेतु यह सदन अपना कार्य-स्थगित करता है।"

इसका गवर्नमेंट से सम्बन्ध नहीं है यह तो नगरपालिका और भंगियों का झगड़ा है। यह भी एक कामरोको प्रस्ताव का विषय नहीं बन सकता और क्योंकि यह ३१ जुलाई से है इसलिये कोई अर्जेन्सी भी इसमें दिखायी नहीं देती है।

प्रादेशिक कर्मचारियों को डाक व तार कार्यालयों में काम करने की आज्ञा देने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--श्री नारायणदत्त तिवारी का एक कामरोको प्रस्ताव इस प्रकार है--

"यह सदन प्रान्तीय सरकार द्वारा, अपने अधीन विभिन्न विभागों के सैकड़ों क्लर्कों एवं अन्य कर्मचारियों को प्रदेश भर में ९ अगस्त, १९५७ से केन्द्रीय सरकार के अधीन डाक व तार कार्यालयों में काम करने की आज्ञा देने के हेतु निकाले गये, अवैधानिक व अनियमित सर्क्युलर से उत्पन्न विशेष परिस्थिति पर बिचार करने के हेतु अपना आज का कार्य स्थगित करता है।"

(श्री नारायणदत्त तिवारी से) क्या यह सर्क्युलर आपके पास यहां मौजूद है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--यह सर्क्युलर मैंने स्वयं देखा है। वह माननीय नेता विरोधी दल के कमरे में है। मैं उसकी कापी प्रस्तुत कर सकता हूं।

श्री अध्यक्ष--वह आपने मेरे पास नहीं भेजा। लेकिन जब हड़ताल होगी तब वह काम में आयेगा। अब हड़ताल होगी या न होगी यह कैसे कहा जा सकता है? यह विषय निश्चित नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--यह निश्चित विषय यूं है कि वह सर्क्युलर मैंने स्वयं देखा है। चीफ इंजीनियर को जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा भेजा गया है कि ९ अगस्त से हड़ताल हो रही है अपने दफ्तर से कर्मचारियों को आन लोन भेज दो। मेरी यह शिकायत है कि प्रान्तीय सरकार के कर्मचारी केन्द्रीय सरकार या दूसरी प्रान्तीय सरकारों के यहां केवल एक कायदे से जा सकते हैं अर्थात् आन डेप्यूटेशन जा सकते हैं जिसका बाकायदा गजट होता है और उन्हें वहां जाने का २५ प्रतिशत डेप्यूटेशन एलाउन्स मिलता है। बाकायदा वहां से मांग आती है।

श्री अध्यक्ष--मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि सरकार किसी हड़ताल को मीट करने के लिये कोई तैयारी कर रही है, लेकिन स्ट्राइक होने ही वाला है यह निश्चित कहां से है ? और जो विषय निश्चित नहीं है उस पर कामरोको प्रस्ताव कैसे लाया जा सकता है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--इसमें निश्चितता यूं है कि जिले में एक सर्क्युलर निकला। स्ट्राइक से मेरा उतना मतलब नहीं है जितना कि इससे कि उस सर्क्युलर द्वारा ९ अगस्त से काम करने के लिये जो आज्ञा दी जा रही है। मेरा कहना यह है कि वह आज्ञा ग़लत है। अब यह आज्ञा दी जा चुकी है कि उसका पालन होना चाहिये। इसलिये यह निश्चित है।

श्री अध्यक्ष--माननीय मुख्य मंत्री जी को इसमें कुछ कहना है ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--अध्यक्ष महोदय, सरकारी सर्क्यूलर कांफिडेंशल कागज होता है। अगर किसी शख्स ने किसी कांफिडेंशल कागज को बाहर किया है तो आफिशियल सीक्रेट ऐक्ट के मातहत उसके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है। किसी किस्म का कोई सर्क्युलर निकला है या नहीं निकला है, इस पर मैं बहस करने के लिये तैयार नहीं हूं, लेकिन इतना मैं जरूर कह देना चाहता हूं कि हम जो काम करेंगे वह कभी अवैधानिक और गलत नहीं होगा। जहां तक स्ट्राइक की बात है, मैं नहीं जानता कि स्ट्राइक होगी या नहीं होगी, लेकिन अगर स्ट्राइक होगी, तो हम जरूर उसका मुकाबला करेंगे।

श्री अध्यक्ष--(श्री नारायणदत्त तिवारी से) यह तो मालूम हो ही गया। मैंने तो आपको बहस के लिये इजाजत दे दी थी, आप बोल चुके। क्या आप कोई बात जानना चाहते हैं ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--एक बात मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि स्ट्राइक का हम मुकाबला करेंगे, तो उस स्ट्राइक से प्राविंशिअल गवर्नमेंट का क्या सम्बन्ध है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अगर स्ट्राइक होगी तो प्रदेश के रहने वाले सब लोगों को, लाखों करोड़ों आदमियों को तकलीफ होगी, इसलिये हमारा उससे सम्बन्ध है।

श्री अध्यक्ष--तो यह प्रश्न भी सामने है कि इस तरह का कामरोको प्रस्ताव आ सकता है या नहीं। कोई सर्क्यूलर जो गवर्नमेंट की तरफ से निकला हो और वह कांफिडेंशल हो तो उसकी वैधानिकता के बेसिस पर काम रोको प्रस्ताव हो सकता है कि नहीं, यह प्रश्न भी है। अगर मान लिया जाय कि यह सर्क्युलर कांफिडेंशल है तो हम उसको नोटिस में नहीं ला सकते। दूसरे अगर यह भी मान लिया जाय कि सर्क्यूलर हमारे नोटिस में आ गया है तो उसके अवैधानिक या वैधानिक होने के प्रश्न पर कामरोको प्रस्ताव नहीं उठ सकता है, क्योंकि यह कानूनी प्रश्न हो जाता है जिसके ऊपर यहां डिबेट नहीं हो सकता। लीगल प्वायंट को डिबेट में नहीं ला सकते हैं। अगर अवैधानिक है तो उसको लोग अदालत में ले जा सकते हैं और वहीं पर उसकी अवैधानिकता के ऊपर बहस हो सकती है। तो इसलिये कामरोको प्रस्ताव का यह विषय नहीं हो सकता। यदि कोई वाकयात होते और उसी दिन वाकयात के आधार पर कोई घटना हो जाती तो वाकयात के सम्बन्ध में प्रश्न उठ सकता था। मैंने पहले ही बतला दिया है कि हड़ताल एक वाकया है, लेकिन उसमें कर्मचारी शामिल होंगे या नहीं होंगे, उस परिस्थिति को कोई नहीं बतला सकता है, इसलिये वह हाइपोथिटिकल है। हड़ताल होगी या नहीं होगी, इसको भी कोई नहीं कह सकता है। यह सर्क्यूलर की लीगेलिटी का क्वेश्चन भी है जिसके ऊपर बहस होती नहीं है। इसलिये मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं।

'नेशनल हेराल्ड' में कृषि मंत्री के भाषण को गलत ढंग से प्रकाशित करने पर कृषि मंत्री द्वारा आपत्ति

कृषि मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---अध्यक्ष महोदय, एग्रीकल्चर ग्रांट के सम्बन्ध में जो मैंने तकरीर की थी, आज मैंने नेशनल हेराल्ड में देखा कि वह रिपोर्ट गलत की गयी है। उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उसमें यह हेडिंग दी गयी है "प्लानिंग टु बी ब्राट अंडर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट" "हुकुम सिंह एश्योर्स इन दि यू० पी० असेम्बली"। मैंने कोई इस तरह का एश्योरेंस नहीं दिया था, न कोई ऐसी बात कही थी। यह हेडिंग मिसलीडिंग है।

श्री अध्यक्ष---जो आपने कहा था उसे भी कह दीजिये।

श्री हुकुम सिंह विसेन---जो मैंने कहा था वह अर्ज किये देता हूं। मैंने कहा था कि गवर्नमेंट प्लानिंग डिपार्टमेंट के पुनः संगठन के बारे में विचार कर रही है और उससे यह आशा होती है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जो अफसरान डिस्ट्रिक्ट लेविल प्लानिंग और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के मातहत कामन पूल (Common pool) हैं उन पर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का effective कंट्रोल होगा। मैंने यह बात कही थी। यह बात मैंने कभी नहीं कही थी कि प्लानिंग डिपार्टमेंट पर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का कंट्रोल होगा। जो हमारे अफसरान हैं उन पर कंट्रोल एफेक्टिव होगा, इससे गलतफहमी होने का अन्देशा है, इसलिये प्रार्थना है कि इसको ठीक करा दिया जावे।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि आप मुझे खत लिख देते तो मैं उनसे कह देता या उन्हें लिख कर भेज देता, लेकिन ठीक है आपने सदन में कह दिया, यहां पर उनके प्रतिनिधि मौजूद हैं, वह कृपा करके उसकी दुरुस्ती करा दें और मैं भी उनके पास जो ठीक कथन है वह भिजवा दूंगा।

१९५७-५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान---अनुदान संख्या १९---लेखा शीर्षक: ३८---चिकित्सा तथा अनुदान संख्या २०---लेखा शीर्षक: ३९---जन: स्वास्थ्य

श्री अध्यक्ष---अब वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के लिये आय-व्ययक में अनुदानों के लिये प्रस्ताव लिये जायंगे। अनुदान संख्या १९ और २०।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---अध्यक्ष महोदय, आज के कार्यक्रम के सम्बन्ध में समय तय हो जाता।

श्री अध्यक्ष---वह तो १९, २० एक साथ लेने की बात तय हो चुकी है और आज का सब समय इन्हीं दोनों में जायगा।

कृषि मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---अध्यक्ष महोदय, गवर्नर महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १९---चिकित्सा---लेखा शीर्षक: ३८---चिकित्सा के अन्तर्गत ४,१५,२२,७०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के लिये स्वीकार की जाय।

(कुछ ठहरकर)

अध्यक्ष महोदय, गवर्नर महोदय की सिफारिश से मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २०---जन-स्वास्थ्य---लेखा शीर्षक: ३९---जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत १,६७,७६,८०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के लिये स्वीकार की जाय।

(इस समय १२ बजकर २७ मिनट पर श्री अध्यक्ष के चले जाने पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुये।)

[श्री हुकुम सिंह विसेन]

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने कल अर्ज किया था उसी सिद्धान्त को मानते हुये आज भी मैं कोई लम्बो चौड़ी तकरीर करके इस सदन का समय नहीं लेना चाहता। मेरी यह दिली ख्वाहिश है कि माननीय सदस्यों को जो इधर के बैठने वाले हैं और उधर के बैठने वाले हैं उन सबको काफी समय मिले अपनी बात कहने के लिये, उससे हम लाभ उठाना चाहते हैं और उसूल बड़ा साफ है कि अपने दोष अपने को नहीं दिखाई पड़ते। इसलिये दूसरों को मौका देना चाहिये कि उनकी ज्यादा सुनें और उससे लाभ उठावें। इन चन्द शब्दों के साथ मैं सदन से आशा करता हूं कि वह इन दोनों धनराशियों को मंजूर करेगा।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)— उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से अनुदान संख्या १९—चिकित्सा में १ रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से अनुदान संख्या २०—जन-स्वास्थ्य में भी एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रदेश के पूर्वी और पर्वतीय क्षेत्रों के बहुत बड़े भाग में चाहे भुखमरी न हो, लेकिन जहां सर्वदा १२ महीने अन्न संकट व्याप्त रहता है, उस प्रदेश की बहुत बड़ी जनसंख्या के स्वास्थ्य की सहज कल्पना हम कर सकते हैं। जिस प्रकार से बुरजुआ एनारकी या पूंजीवादी अराजकता इस सरकार के सभी मौजूदा विभागों में व्याप्त है वही बात इस विभाग के विषय में भी लागू है। इस सरकार की कोई स्पष्ट योजनात्मक नीति जनस्वास्थ्य के विषय में जहां तक मैं इस बजट को देख चुका हूं, पूरे बजट को देखने के बाद नहीं दिखाई पड़ती, वही बात, वही राष्ट्रीय नीति का अभाव इस अनुदान के विषय में भी मुझे दिखाई पड़ता है। इस सम्बन्ध में मैं सदन का और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आजादी के बाद इस बात की कोई भी खोज राष्ट्रीय सरकार अथवा प्रदेशीय सरकार की ओर से नहीं हुई कि हमारे देश और प्रदेश के लिये किस प्रकार की चिकित्सा पद्धति सर्वथा उपयोगी होगी। जो स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक पुस्तिका "स्वास्थ्य सर्वेक्षण १९५६-५७" वितरित की गई है उसको देखने की मैंने कोशिश की। इस बात की भी खोज की कि इसमें कोई नीति वक्तव्य स्वास्थ्य के विषय में है अथवा नहीं। १८ पेज पर एक शीर्षक है "आयुर्वेदिक, यूनानी तथा होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धतियां" उसके विस्तार में लिखा हुआ है कि एलोपैथिक चिकित्सा के साथ-साथ **'के साथ-साथ'** पर मेरा विशेष जोर है, आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति में भी, **'भी'** पर **मेरा विशेष** जोर है, पर्याप्त विकास किया जा रहा है। होम्योपैथिक पद्धति को भी, **'भी'** पर मेरा जोर है, प्रोत्साहन दिया जा रहा है। उसी के साथ-साथ १९ पेज पर "अन्य आयुर्वेदिक तथा यूनानी महाविद्यालय" शीर्षक में लिखा है "आयुर्वेदिक तथा यूनानी पद्धति में एलोपैथिक पद्धति की पूर्ति, **'पूर्ति'** पर मेरा अधिक जोर है, के लिये विकास किया जा रहा है।" इन चन्द लाइनों से यह साफ होता है कि सरकार ने इस बात को बिना वैज्ञानिक अन्वेषण के ही मान लिया है कि हमारे प्रदेश के लिये एलोपैथिक सिस्टम ही सर्वोत्तम चिकित्सा पद्धति है। मुझे इसमें सन्देह है। हमारे प्राचीन काल से जिस प्रकार की पद्धति का विकास हमारे देश में हुआ और जिसको अपना करके हमारे देश के जनवासियों का स्वास्थ्य सर्वदा अच्छा रहा उसके विषय में अंग्रेजों ने कोई ध्यान नहीं दिया। उनके यहां एक पद्धति प्रचलित थी, उन्होंने अनेक चीजों की भांति इस चिकित्सा पद्धति को हमारे देश में लागू किया। इसके पहले न खोज करने की जरूरत थी और न छानबीन करने की। लेकिन हमको आशा थी कि मौजूदा राष्ट्रीय सरकार और प्रदेशीय सरकार इस विषय में खोज बीन करने के बाद ही किसी चिकित्सा पद्धति को मुख्य और प्रमुख चिकित्सा पद्धति घोषित करेगी।

जहां तक एलोपैथिक सिस्टम की बात है, आप श्रीमन्, जानते हैं अच्छी तरह से, सरकार भी जानती है और माननीय सदस्य भी जानते हैं कि इस पद्धति के विषय में अनेक प्रकार

के सन्देह दूसरी पद्धतियों के लोग प्रकट करते हैं। यह बात समझी जाती है कि एलोपैथिक सिस्टम और यह जाहिर भी है और सही है थोड़े समय के लिये रोग को अच्छा कर देता है, लेकिन रोग के मूल कारण का निदान और उसको जड़ से समाप्त करने की तरफ़ उसकी सफलता बहुत ही संदेहात्मक रही है। ऐसे विषय के ऊपर हमें आशा थी कि सरकार अन्वेषण के बाद ही कोई नीति निर्धारित करती। इसलिये मैंने कहा कि अन्य बहुत सी बातों की तरह अंग्रेजों का अंधानुसरण इस सरकार ने इस विषय में भी किया और इसमें कोई भी राष्ट्रीय नीति परिलक्षित नहीं होती है। इसके अलावा इस बात की भी कोई खोजबीन अब तक नहीं हुई कि किस रोग के लिये, प्रमुख रोगों से मेरा मतलब है, कौन सी चिकित्सा पद्धति सर्वोत्तम है? यह साधारण अनुभव की बात है कि बहुत सी बीमारियों में एलोपैथिक पद्धति अच्छी साबित हुई है, बहुत सी बीमारियां आयुर्वेदिक सिस्टम से अच्छी हो सकती हैं। उसी प्रकार यूनानी, होम्योपैथी और मैं तो कहूंगा कि प्राकृतिक चिकित्सा की तरफ भी सरकार का ध्यान जाना चाहिये। केवल श्री लक्ष्मीरमण आचार्य के प्राकृतिक चिकित्सा सम्मेलन में शिरकत करने से ही काम नहीं चलेगा। अतः मेरे विचार में जो विभिन्न प्रकार की पद्धतियां हैं उनमें कौन सी पद्धति किस रोग के लिये लाभकर होगी, हमारे देश और प्रदेश की जलवायु में, उसकी तरफ़ सरकार का ध्यान नहीं गया, जो जाना चाहिये था।

श्रीमन्, जब समाजवादी प्रकार के समाज की स्थापना का लक्ष्य घोषित नहीं हुआ था तब जिस प्रकार का बजट पेश होता था उसमें और इस साल के बजट में किसी प्रकार का कोई मौलिक अन्तर नहीं दिखाई देता। समाजवादी प्रकार के समाज की स्थापना की तरफ हम बढ़ रहे हैं अथवा नहीं इसकी कसौटी दो ही हो सकती हैं। जो समाज के निम्न वर्ग के लोग हैं जिनकी आय कम है या जो बहुत गरीब हैं, उनको चिकित्सा की सुविधा आसानी से उपलब्ध हो सके। उनका कम से कम दाम खर्च हो और उनको भी चिकित्सा उसी प्रकार उपलब्ध हो जिस प्रकार कि समाज के कुछ गण्यमान्य और प्रमुख लोगों को उपलब्ध हो जाया करती है। इस ओर सरकार द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है और न ही वित्त मंत्री जी के भाषण में या जो पुस्तिकायें हमको वितरित की गई हैं उनमें ही कोई ऐसी बात दिखाई पड़ती है। पूरे बजट को देखकर भी मैं किसी ऐसे परिणाम पर नहीं पहुंच सका हूं कि कोई भी विशेष प्रकार का उपाय समाज के गरीब वर्ग के लोगों के लिये जो कि अब तक नहीं हुआ है, वह उसमें दिखाई दिया हो। जहां तक इस विभाग के निम्न कर्मचारी हैं जो अस्पतालों में काम करने वाले हैं, उनकी आमदनी का सम्बन्ध है, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जब दोनों अनुदानों के ऊपर ६ करोड़ के लगभग रुपया दिया जा रहा है उस समय निम्न कर्मचारियों के बढ़ोत्तरी के ऊपर केवल ७ लाख ५० हजार रुपया उनकी तनख्वाह या महंगाई भत्ते में व्यय होता है जो कि कुल मिलाकर १.२ प्रतिशत से ऊपर नहीं पड़ता। तो रकम जो सरकार खर्च कर रही है उस में कितना किस का भाग है, उसमें भी कोई समाजवाद की झलक नहीं दिखाई देती और निम्न वर्ग के लिये सुविधायें प्रदान करने के सम्बन्ध में भी कोई कदम नहीं दिखाई देता। इसलिये हम कहना चाहते हैं कि समाजवाद का जो नारा है वह इसमें कहीं भी लागू होता नहीं दिखाई देता।

सरकार की जो पुस्तिकायें हमें मिली हैं उनके आंकड़ों से यह साफ मालूम पड़ता है कि ज्यों-ज्यों अस्पताल बढ़े हैं उनमें रोगियों की संख्या भी वैसे ही बढ़ी है। जो रोगी नये दाखिल हुये, जो डिस्चार्ज किये गये तथा जो अच्छे होकर के नहीं निकल सके, मर गये उन सब की संख्या बढ़ी है। ज्यों-ज्यों अस्पताल बढ़ते जा रहे हैं, रोगी भी बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन किन कारणों से रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है उसकी बुनियादी चीजों की तरफ सरकार का ध्यान आज

[श्री झारखंडेराय]

तक नहीं जा सका है, क्योंकि परम्परागत पद्धतियों का अनुसरण इस सरकार के जरिये भी हो रहा है। हम देखते हैं कि पूरे प्रदेश में पौष्टिक भोजन जो कि हमारे प्रदेश की बहुसंख्यक जनता को प्राप्त नहीं होता है उसका असर भी स्वास्थ्य पर पड़ता है। गरीबी और शहरों की बढ़ती हुई आबादी के बारे में भी सरकार ने कोई नीति निर्धारित नहीं की है कि इस सरकार का लक्ष्य बम्बई, कलकत्ता ऐसे बड़े-बड़े शहरों को निर्माण करने का है या कि छोटे छोटे मध्यम प्रकार के शहरों को बसाकर बड़े शहरों में जो भीड़-भाड़ होती है उसको रोकने का है। बड़े-बड़े शहरों में हम देख रहे हैं कि बीमारियां ज्यादा होती हैं। वहां अधिकतर संक्रामक रोग फैलते हैं। टी० बी० वगैरह ऐसे भयानक रोग जो हमारे देश में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं उनका भी प्रकोप बड़े-बड़े शहरों में ही होता है। तो घनी आबादी वाले शहरों के बारे में सरकार की नीति साफ नहीं हुई है। इन बुनियादी चीजों की तरफ सरकार का ध्यान जाय तभी हम रोगों के मूल कारण को दूर करने की कोशिश कर सकते हैं।

शहरों में उपाध्यक्ष महोदय, आपने देखा होगा, आपको इसका अनुभव है कि नाना प्रकार के संक्रामक रोगों के रोगी जिनमें कोढ़ी तक शामिल हैं, सड़कों पर घूमते हैं, खुले आम भीख मांगते हैं। उनका असर मनोवैज्ञानिक तौर पर और शारीरिक तौर पर भी हर एक आदमी पर होता है। उनको हटाकर किसी ऐसी जगह पर रखने का कोई सरकार की ओर से प्रबन्ध नहीं किया गया जहां पर उनसे उपयोगी काम लिये जा सकें और आम जनता को उन रोगों के प्रसार से बचाया जा सके।

वेश्यावृत्ति का असर हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य पर पड़ा है और बहुत व्यापक रूप से पड़ा है। १० वर्ष में भी सरकार ने उसे खत्म करने के लिये कोई ठोस कदम, कारगर कदम उठाने का प्रयत्न नहीं किया।

गन्दे, अश्लील, कामोत्तेजक चल चित्र की ओर सरकार का ध्यान नहीं गया। यद्यपि यह विषय इस सरकार से सम्बन्धित नहीं है, इसका बहुत कुछ सम्बन्ध केन्द्रीय सराकर से है, फिर भी मैं समझता हूं कि अगर सरकार इस ओर ध्यान दे तो इस पर रुकावट हो सकती है। ऐसे चल-चित्र जिन से नाना प्रकार की दिमाग में खुराफातें पैदा होती हों और जिनका असर नौजवानों, माताओं और बहनों पर बुरा पड़ता हो उन्हें रोका जा सकता है।

खाद्यान्नों और औषधियों में जो मिलावट होती है उसकी ओर सरकार ने कोई सफलता-पूर्वक कदम नहीं उठाया। इसका असर बहुत तेजी से आम जनता के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। हर तरह की खाने की चीजों में मिलावट होती है। मामूली से मामूली दैनिक इस्तेमाल की चीजों में भी मिलावट पाई जाती है, जो अखाद्य है, उसको मिलाया जाता है जिसका असर स्वास्थ्य पर बुरा पड़ता है।

औषधियों में भी मिलावट बड़े पैमाने पर हो रही है। उपाध्यक्ष महोदय, ये चीजें हैं जिन पर हमें ध्यान देना है।

ऐसे क्षेत्र हमारे प्रदेश में हैं, उपाध्यक्ष महोदय, जहां पीने के पानी की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। वहां पर कुयें नहीं मिलते और पाइप का कोई इन्तजाम नहीं है। स्वच्छ पानी उनको उपलब्ध नहीं होता। गढ़इयों से, पोखरों से जहां बहुत ही गन्दा पानी होता है, उसको वे इस्तेमाल करते हैं जिसका बहुत बुरा असर उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है। ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहां पर फीलपांव, घेंघा आदि ऐसी बीमारियां होती हैं जिन का सीधा सम्बन्ध पानी से होता है। उसकी रोकथाम के लिये कोई ठोस कदम सरकार की ओर से नहीं उठाया गया है। मैं समझता हूं कि इन चीजों की ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिये तभी हम स्वास्थ्य में तरक्की कर सकते हैं।

इस विभाग में अन्य विभागों की तरह से भ्रष्टाचार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। घूस ले कर लोगों को भर्ती किया जाता है। दवायें बेच दी जाती हैं। दवाओं में पानी मिलाकर

डाइल्यूटेड मिक्स्चर दिया जाता है। घूस देने वाले को अच्छी दवाइयां दी जाती हैं। बीमारों के साथ अमानवीय व्यवहार डाक्टरों व नर्सों द्वारा किया जाता है जिसका ज्वलन्त उदाहरण लखनऊ मेडिकल कालेज है। डाक्टरों व नर्सों के अनैतिक सम्बन्ध से डिसिप्लिन पर असर पड़ता है और भ्रष्टाचार बढ़ता है। इसी तरह से, उपाध्यक्ष महोदय, कानपुर मेडिकल कालेज की नियुक्तियां बजाय पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिये न कर विभागीय कमेटी के जरिये की गईं और यही कारण है भाई, भतीजे, जात-पांत, कौमपरस्ती को परवरिश देने का। एक मिसाल मैं पेश करना चाहता हूं। १९५६-५७ में मेडिकल कालेज, लखनऊ में एक होस्टल बनाने की स्कीम बनायी गई जिसमें २२,८०८ रुपये ४ आ० का ओरिजिनल एस्टिमेट था। यह ठेका दिया गया रामजस रामदयाल कम्पनी को। ये किशोरीलाल के रिश्तेदार हैं।

श्री उपाध्यक्ष---मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि वे किसी ऐसे आदमी का नाम न लें जो जवाब देने की स्थिति में न हो। मुमकिन है आप की बात गलत हो। आप बात कह दें लेकिन नाम किसी का न लें।

श्री झारखंडेराय---तो यह रामदयाल रामजस कम्पनी को दिया गया जिनका सम्बन्ध ऐसे व्यक्ति से है जो हास्पिटल बोर्ड आफ मैनेजमेंट वहां का मैनेजमेंट करता है, उसके एक मेम्बर हैं। साथ ही साथ आप देखें कि लेडीज होस्टल बनाने के लिये पहले ओरिजनल ग्रांट ६५,२७१ रुपये की थी वह रिवाइज एस्टीमेट में २०,०४,३९५ रुपये हो गई और यह भी ठेका रामदयाल रामजस कम्पनी को दिया गया। साथ ही साथ सर्जिकल आपरेशन थियेटर में ठेका श्रीराम कम्पनी को दिया गया है जिसकी ग्रांट ८५,६१५ रुपये की थी जो रिवाइज्ड एस्टीमेट में ६,२२,४७२ रुपये हो गये। इस तरह से बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार अन्य विभागों की तरह से यहां फैल रहा है जिसकी ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री (जिला मेरठ)---आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को बधाई देने के लिये तथा अनुदान संख्या १९ और २० का समर्थन करने के लिये खड़ी हुई हूं। श्रीमन्, इतिहास साक्षी है कि लम्बी परतंत्रता के बाद जो देश स्वतंत्र होता है उसमें स्वेच्छाचारिता और उच्छृंखलता आदि के कारणों से नैतिक पतन होता है जिसका प्रभाव सभी क्षेत्रों में पड़ता है।

श्रीमन्, मैं विश्वासपूर्वक कह सकती हूं कि गत वर्षों में चिकित्सा में हमारे यहां आश्चर्य-जनक प्रगति हुई है बल्कि हैजा, चेचक, प्लेग, कालाजार आदि संक्रामक रोगों को रोकने के लिये हमारी सरकार ने प्रशंसनीय कदम उठाया है। क्षय रोग के निवारण के लिये हमारी सरकार ने गत वर्षों में ५ से ९ क्षय आश्रम और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत २४ क्षय आश्रमों के खोलने की व्यवस्था की है। क्षय रोग के निवारण के लिये बी० सी० जी० के टीके सुदूरवर्ती गांवों में लगाये जा चुके हैं। इसके द्वारा इस प्रदेश की लगभग २३ लाख जनता को लाभान्वित किया गया है और ८२ लाख जनता का निदान किया जा चुका है। इस तरह से हमारे प्रदेश की सवा करोड़ जनता को लाभ पहुंचा है। यह हमारे लिये एक गौरव की बात है।

श्रीमन् शिशु चिकित्सालय, जच्चा बच्चा केन्द्र आदि भी सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में खोले गये हैं। श्रीमन्, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ५०० जच्चा-बच्चा केन्द्र खोलने का कदम प्रशंसनीय है। श्रीमन्, मैं यह कह सकती हूं कि मजदूरों में स्वास्थ्य बीमा योजना का प्रसार, हमारी सरकार का समाजवादी व्यवस्था की ओर एक प्रशंसनीय कदम है और श्रीमन्, मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि हमारे प्रदेश की जनता स्वास्थ्य बीमा योजना से लाभान्वित होगी। श्रीमन्, इसे हमारी गरीबी का अभिशाप या प्रदेश की जनता का दुर्भाग्य कहिये कि हमारे साढ़े छः करोड़ की आबादी वाले प्रदेश को केवल छः करोड़ की धनराशि राजकोष से उपलब्ध हुई है जो एक रुपया प्रति आदमी भी नहीं पड़ती है।

[कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री]

श्रीमन, जब हम संसार के समुन्नत देशों की ओर दृष्टिपात करते हैं तो हमें आश्चर्य होता है कि ६ करोड़ से कम आबादी वाले इंगलैंड की जनता अपने स्वास्थ्य पर ६ अरब रुपये प्रति वर्ष खर्च करती है। आज हमको अपने प्रदेश के साधनों को विकसित करना ही पड़ेगा ताकि हम आगामी २० वर्षों में महामारी आदि को अपने प्रदेश से समाप्त कर सकें। हमें तो अपने सीमित साधनों का ही अधिकाधिक उचित प्रयोग करना पड़ेगा। यह सत्य है कि आधुनिक प्रगति के स्रोतों से हम अपने प्रदेश को अलग नहीं रख सकते और मैं यह भी मानती हूं कि आधुनिक आविष्कारों और गवेषणाओं के द्वारा हम अपने प्रदेश की जनता को स्वास्थ्य लाभ से वंचित नहीं रख सकते, लेकिन फिर भी मैं यह कहने के लिये तैयार हूं कि हमको हमारे प्रदेश की परिस्थितियां यह आज्ञा नहीं देतीं कि हम केवल पाश्चात्य प्रणाली पर पूर्ण रूप से अवलम्बित हो सकें। हमारा प्रस्तुत चिकित्सा का बजट ४,१५,२२,७०० रुपये का है और १,६७,७६,८०० रुपये का जन-स्वास्थ्य का बजट है। इस बजट के अन्दर आयुर्वेदिक, यूनानी और देशी चिकित्सा पद्धतियों के सभी क्षेत्रों के लिये केवल ३३,८२,१०० रुपये की धनराशि रखी गयी है। हमारे सदन के सभी सम्मानित सदस्य जानते हैं कि आज भी हमारे प्रदेश में देशी चिकित्सा पद्धतियों द्वारा ९० प्रतिशत् जनता स्वास्थ्य लाभ करती है। फिर तुलनात्मक दृष्टि से हमारे प्रदेश के अन्दर देशी चिकित्सालय एलोपैथिक चिकित्सालयों से अधिक हैं। उस तुलनात्मक दृष्टि से भी यह धनराशि हमारे लिये बहुत हास्यास्पद ही हो सकती है, यह विडम्बना का विषय है।

मेरी क्षुद्र बुद्धि से तो चिकित्सा क्षेत्र में सेवाओं का समाजीकरण हमारी सरकार का सर्वप्रथम कर्तव्य होना चाहिय। रोगियों के लिये कष्ट निवारण और प्राण दान यज्ञ के इस पावन कार्य में पूंजीवादी प्रवृति के लिये कोई स्थान नहीं होना चाहिये। मेरा निवेदन है कि सरकार चिकित्सा के क्षेत्र में समाजीकरण का दृढ़ संकल्प करे और उसका श्रीगणेश लखनऊ के विश्व-विद्यालय, कानपुर और आगरा के मेडिकल कालेज से होना चाहिये। मौलिक अनुसन्धानों और गवेषणाओं के लिये प्राइवेट प्रैक्टिस बड़ी हानिप्रद सिद्ध हो रही है। अतः प्राइवेट प्रैक्टिस इन विद्यालयों के प्रोफेसर्स के लिये आज्ञाभित नहीं होनी चाहिये। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि इन विद्यालयों के जीवन काल में इन की गवेषणायें और अनुसन्धान नगण्य हैं। यह उनके लिये लज्जास्पद नहीं तो और क्या कहा जा सकता है ?

अन्त में मैं यह निवेदन करूंगी कि लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा संचालित क्वीन मेरी अस्पताल और गांधी स्मारक अस्पतालों पर राज्य कोष से २० लाख रुपये की धनराशि व्यय होती है। उन पर हमारे सदन और सरकार का नियंत्रण होना चाहिये और वहां के डाक्टर्स की सेवायें हमारे प्रदेशीय मेडिकल सर्विस का एक अंग बननी चाहिये, जिस से उन का स्थानान्तरण किया जा सके।

इस के अतिरिक्त हमारे प्रदेश में प्रचलित जितनी भी हमारी देशी शिक्षा पद्धतियां हैं और पाश्चात्य शिक्षा पद्धति में भी सामन्जस्य होना चाहिये। कितना अच्छा होता यदि स्वास्थ्य की सभी सुविधाओं से सुसज्जित अस्पताल पहले जिले के स्तर पर हों, तत्पश्चात् धीरे-धीरे तहसीलों के स्तर तक ले जाये जाते, बाकी स्थानों पर बी० ऐम० बी० एस० स्नातकों और देशी चिकित्सकों द्वारा चिकित्सा कराई जाती तो इसी धनराशि में अधिक व्यक्तियों को लाभान्वित किया जा सकता था।

श्रीमन्, मेरे पूर्व वक्ता ने प्राकृतिक चिकित्सा पर जोर दिया है। मैं कह सकती हूं कि जल वायु द्वारा चिकित्सा हमारे प्रदेश के नागरिकों और ग्रामीणों के लिये बहुत ही लाभप्रद सिद्ध हो सकती है। इस में धन भी कम व्यय होता है। अतः मेरा स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन है कि अपने प्रदेश में प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति को भी पूर्ण प्रोत्साहन दिया जाय, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने भी सभी राजनीतिक व धार्मिक आदि क्षेत्रों में क्रांति के नवीन मार्गों का प्रदर्शन किया था। अतः चिकित्सा जगत में भी हम प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली द्वारा विश्व को नवीनतम मार्ग प्रदर्शित कर सकेंगे। तो मैं उनसे निवेदन करूंगी कि यह प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति हमारे

प्रदेश की बहुत पुरानी पद्धतियों में से एक है। इस से हमारे प्रदेश की परिस्थितियों के अनुकूल हमारे प्रदेश की जनता अधिकाधिक लाभ प्राप्त कर सकती है।

अतः मैं स्वास्थ्य मंत्री जी को धन्यवाद देती हूं।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)--श्रीमन्, बाबू झारखंडेराय जी ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है उस का समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। उन्होंने सरकार की चिकित्सा और जनस्वास्थ्य की नीति के सम्बन्ध में जो अपने विचार व्यक्त किये हैं, उनसे अपनी पूरी सहमति प्रकट करता हुआ कहना चाहता हूं कि चिकित्सा की वास्तविक नीति इस पिछड़े हुए, गरीब प्रदेश में जहां तरह-तरह की पद्धतियां काफी आगे जा चुकी हैं, क्या होनी चाहिये उसकी तरफ मैं माननीय मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं। मेरा अपना विचार है कि इस क्षेत्र में हम को विदेशों की नकल नहीं करनी चाहिये। अपने देश में कुछ प्रयोग हुये हैं, उनसे हमें लाभ उठाने की चेष्टा करनी चाहिये। आपको ज्ञात होगा कि हिन्दू विश्वविद्यालय काशी और अलीगढ़ यूनीवर्सिटी में एक प्रयोग किया गया है। वहां पाश्चात्य और पौर्वात्य दोनों ज्ञानों में सामंजस्य स्थापित करने की चेष्ठा की गई है। यह जरूर है कि वहां के अध्यापकों में कुछ विभागीयता आ गई और कुछ और दोष आ गये और जो मूल उद्देश्य इस विद्यालय के स्थापना का था, वह बहुत हद तक पूरा नहीं हो सका, लेकिन मेरा अपना विचार है और चिकित्सा मनोविज्ञान के विद्यार्थी के नाते मैं दावे के साथ यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक देशी पद्धति का प्रश्न है बहुत से क्षेत्रों में वह यूरोपीय पद्धतियों से आगे गई है और आज भी बहुत से अच्छे-अच्छे डाक्टर्स ने हमारी देशी औषधियों से बड़ी अच्छी-अच्छी दवाइयां तैयार की हैं। मैं एक चिकित्सा मनोविज्ञान की विद्यार्थी की हैसियत से रांची मिटो अस्पताल में था और मैं बताऊं कि वहां मानसिक रोगियों को एक औषधि दी जाती है, जिसको सर्पाइन कहते हैं। वह औषधि कुछ नहीं है सर्पगन्धा है जो आर्युवेदिक औषधि है।

श्री हुकुमसिंह विसेन--मैं एक प्रश्न अपने मित्र से करना चाहता हूं। आप वहां डाक्टर थे या विद्यार्थी थे ?

श्री रामायणराय--मैं वहां मानसिक रोगों की चिकित्सा का एक विद्यार्थी था और इसी हैसियत से मैंने वहां अध्ययन किया है। मेरा समय नष्ट न करें। मेरा विशेष परिचय आपको बाद में मिल जायगा। समय कम है।

जहां तक नीति का प्रश्न है हम को एक ऐसी सामंजस्यपूर्ण नीति का आश्रय लेना चाहिये जिससे कि पौर्वात्य और पाश्चात्य दोनों ज्ञानों से हमारे देश के लोग लाभान्वित हो सकें।

श्रीमन्, यह पुस्तिका जो आज हमें दी गई है इसकी तरफ ध्यान दिलाता हूं। इसे देखकर मुझे बाबू झारखंडेराय जी के शब्दों को फिर से दोहराना पड़ता है कि इस में कहीं सोशलिस्टिक पैटर्न की कोई योजना चिकित्सा के सम्बन्ध में नहीं मिलती। इसमें कोई ऐसी योजना नहीं मिलती, जिससे यहां के गरीब लोग लाभ उठा सकें। चिकित्सकों को मालूम है कि नाना प्रकार के रोगों के पीछे कुछ मौलिक बीमारियां होती हैं। अगर उनका उन्मूलन कर दिया जाय तो शेष रोगों से हम गरीबों को मुक्त कर सकते हैं। रूस वगैरह देशों में जहां भी जनता को स्वस्थ्य रखने और लाभ पहुंचाने की चेष्टा की गई वहां सब से पहले आपको जानना चाहिये कि वी० डी० (वेनरल डीजीजेज) के खिलाफ कंपेन शुरू किया गया। कंसेंट्रेशन कैम्प्स खोले गये और जिन लोगों की छूत से दूसरों को नुकसान हो सकता है उनको कैदियों की तरह से एक स्थान पर इकट्ठा किया गया। उन को स्वस्थ बनाया गया। बरखिलाफ़ इसके अमरीका में अरबों रुपया खर्च किया गया, लेकिन आज तक वहां पर इस तरह के रोगों का उन्मूलन नहीं हो सका।

[श्री रामायणराय]

माननीय मंत्री जी को हंसी आती होगी वी० डी० के नाम पर, लेकिन यह एक तथ्य है और स्वास्थ्य विज्ञान के पंडित जानते हैं कि यह जहर ऐसा है कि जिस से तमाम बीमारियां फैलती हैं और इस बजट में ऐसे मौलिक रोगों को रोकने के लिये कोई विशेष योजना नहीं दी गई।

इसके अलावा आज सारा योरोप, अमरीका जिस नयी चिकित्सा पद्धति का अनुसरण कर रहे हैं---साइको सोमेटिक---उस का लाभ उठाने की चेष्टा नहीं की गई। यह कहा गया है कि साइकिक सेन्टर हम खोलेंगे, मानसिक रोगों की चिकित्सा की व्यवस्था करेंगे, लेकिन मनुष्य जो है वह मन और शरीर, अलग अलग से नहीं बना हुआ है। वह दोनों एक साथ रहते हैं। तो एक ऐसी पद्धति जो हमारे मन और शरीर दोनों को स्वस्थ रख सके उसकी व्यवस्था इसमें हो सकती थी, जिसकी ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा।

आज चारों तरफ अनारकी हो रही है। यह प्रवृति आज हम को हर जगह मिलती है जो आज हमारे जीवन और धन दोनों को बुरी तरह बरबाद कर रही है। अभी आप के सामने बाबू झारखंडेरायजी ने स्थानीय भ्रष्टाचार के बारे में जो कहा, बहुत से लोगों की समझ में वह नहीं आया होगा, लेकिन आ जायगा। स्वास्थ्य के बारे में व्यवस्था हो रही है और जो लोग व्यवस्थापक मंडल में हैं वही ठेके भी लेते हैं। हमी मंजूर करते हैं रुपया, हमी खजान्ची बन कर रुपया भी देते हैं और हमी मकान भी बनाते हैं। ठीक है, इस सदन में नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन लखनऊ के लोग जानते हैं कि जो यहां पर हुआ है। दो, तीन ऐसे कंट्रैक्टर्स हैं जिन को बराबर ठेके दिये जाते रहे हैं। वह भी कोई बाहरी लोग नहीं, बल्कि ऐसे लोग हैं कि जिन का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से यहां के व्यवस्थापक मंडल से सम्बन्ध रहा है। मैं जानता हूं कि श्री किशोरी लाल जी का नाम लेने से लोग बिगड़ उठेंगे . . . .

श्री उपाध्यक्ष---यह आपका नाम लेने का नया तरीका उचित नहीं है।

श्री रामायणराय---मैं उपाध्यक्ष महोदय, नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन मेरे पास भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में काफी शिकायतें हैं जिन को मैं आप के द्वारा माननीय मन्त्री जी की सेवा में भेजना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि उन की जांच करायी जाय। मैं जानता हूं कि उनमें से भी अधिकांश सदस्य ऐसे हैं कि जो भ्रष्टाचार का उन्मूलन करना चाहेंगे। तो मैं आप से कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार यूंही बन्द नहीं हो सकता। जो प्रमोशन दिये जाते हैं, उन में भी इस बात का ध्यान नहीं दिया जाता है कि कौन सीनियर है, कौन ज्ञानवृद्ध है, किस के पास अच्छी डिग्री है। किसी अन्य क्षेत्र में ऐसा करें तो ठीक भी है, लेकिन चिकित्सा ऐसे क्षेत्र में इस प्रकार की भेद की नीति बरती जाती है, तो बात कुछ समझ में नहीं आती। एक ही आदमी डिप्टी डाइरेक्टर है, वही सर्जन भी है, वही आदमी प्राइवेट प्रैक्टिस भी करता है, और किसी विभाग का हेड आफ दि डिपार्टमेंट भी वही है। तो इस तरह के जो काम चल रहे हैं, उस से चिकित्सा क्षेत्र में भयानक अशान्ति फैली हुई है। लोगों में इस भ्रष्टाचार की चर्चा होती है, कोई खास आलोचना के लिए नहीं, एक स्वस्थ रचनात्मक सुझाव के लिए इन बातों की चर्चा की जा रही है। कुछ बातें ऐसी जरूर हैं कि जिन के लिए मैं माननीय मन्त्री जी को और अपनी सरकार को धन्यवाद भी देना चाहता हूं।

श्री हुकुमसिंह विसेन---क्या कीजियेगा वक्त खराब करके, आप अपनी बात कहिये।

श्री रामायणराय---हमारे लखनऊ विश्वविद्यालय के अन्दर जो मेडिकल कालेज है, उस में कुछ ऐसे विभाग हैं, जिन विभागों का काम इतना अच्छा रहा है जो प्रशंसा करने योग्य है। हमारे यहां अनुसन्धान का कार्य और शिक्षा का स्तर इतना ऊंचा रहा है कि केन्द्रीय सरकार को ऊंची से ऊंची मान्यता देनी पड़ी है। मैं निवेदन करूंगा कि अभी तक करीब-करीब ४० मडिकल कालेज सारे देश में चल रहे हैं। इन ४० मेडिकल कालेजेज में मद्रास में ३ सब्जेक्ट

को केन्द्रीय सरकार ने प्राथमिकता दी । बिहार में एक को दी । विजगापट्टम में १ को दी और हमारे लखनऊ मेडिकल कालेज में दो विषयों को केन्द्रीय सरकार ने सहायता प्रदान की। केन्द्रीय सरकार के विशेषज्ञों ने यह कहा कि इन विषयों में पढ़ाई बहुत अच्छी होती है और वहां पर रिसर्च का काम भी बहुत अच्छा हो रहा है। इसलिए इन विषयों का स्टैण्डर्ड ऊंचा होना चाहिए और यहां की पढ़ाई केन्द्रीय सरकार के हिसाब से होनी चाहिए।

श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)--माननीय डिप्टी स्पीकर साहब, आज जिस ग्रांट पर बहस हो रही है, पब्लिक हेल्थ और मेडिकल वह ग्रांट है, जिस में तालीम को मिलाकर सही माने में नेशन कन्स्ट्रक्शन की ग्रान्ट कहा जा सकता है। मैंने यह देखा कि इस ग्रांट के ऊपर और पब्लिक हेल्थ की ग्रान्ट पर जितना रुपया मंजूर हुआ है, उस सब रुपये का अगर हिसाब लगाया जाय तो अन्दाजा यह होता है कि इस सूबे के अन्दर पब्लिक हेल्थ के ऊपर तकरीबन १५ आना फीकस खर्च किया जाता है। देखने में यह रकम बहुत कम है। हम चाहते हैं कि यह रकम ५ रुपया और १० रुपया हो तब हम मुकाबला कर सकते हैं अमेरिका, इंगिलिस्तान और फ्रांस का, लेकिन हम को इस बात को भी याद रखना है कि आज से १० वर्ष पहले जिस वक्त कि हम आजाद हुए तो उस वक्त इस डिपार्टमेंट की क्या हालत थी । अगर हम इस बात का जायजा लें, तो हमें यह मानना पड़ेगा कि पिछले हेल्थ मिनिस्टर के जमाने में इस सूबे में पब्लिक हेल्थ और मेडिकल में बहुत तरक्की हुई और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे मौजूदा मिनिस्टर भी इस तरक्की को जारी रख रहे हैं। और इस की तरफ आगे कदम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इस में शक नहीं है कि अभी हम को मेडिकल और पब्लिक हेल्थ में बहुत कुछ करना है। यह तरक्की उस वक्त और भी मुमकिन हो सकती है जब कि हम एक प्लाण्ड तरीके पर आयुर्वेदिक यूनानी होमियोपैथिक और एलोपैथिक जो पहले से जारी हैं इन को आगे चलायें।

पिछले जमाने में एलोपैथिक की तरफ ज्यादा ख्याल किया गया, क्योंकि वह साइन्स की निगाह से ज्यादा तरक्कीयाफ्ता है। शहरों में उस को ज्यादा लोग बरतते हैं और उसको ज्यादा पसन्द करते हैं, लेकिन जो लोग देहात में रहते हैं वे आयुर्वेदिक, यूनानी या होमियोपैथिक को ज्यादा पसन्द करते हैं, और वहां पर उन के ही ज्यादा मशहूर होने का इमकान है। अभी जिस वक्त जनरल बजट पर बहस हो रही थी तो हमारे एक बुजुर्ग दोस्त ने ऐवान के अन्दर यह फरमाया कि यह सही है कि इस सूबे के अन्दर और इस मुल्क के अन्दर मोरटेलिटी की तादाद कम हो गयी है, लेकिन इसका क्रेडिट गवर्नमेंट को नहीं है, बल्कि वह इस वजह से हुई है कि मैरिजेज लेट स्टेज में होने लगी हैं। हो सकता है कि मैरिजेज लेट स्टेज में होने लगीं, लेकिन इसका कुछ क्रेडिट अगर हुकूमत को दिया जाय तो सही होगा। उसकी वजह यह है कि हुकूमत ने भी इस सिलसिले में काफी कोशिश की है। इस मुल्क में एपेडेमिक के खिलाफ सरकार ने बहुत कोशिश की है।

१५, २० वर्ष पहले हम देखें तो हमारा मुल्क और सूबा प्लेग, चेचक, कालरा और दूसरी बीमारियों से भरा हुआ था। लेकिन आज न इन पर ही बल्कि टी० बी० जैसी बीमारी पर कन्ट्रोल कर लिया गया है। इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि मोरटैलिटी कम होने की वजह सिर्फ लेट मैरिजेज ही हैं।

मैं होमियोपैथी के लिए मिनिस्टर साहब को सुझाव देना चाहता हूं और मुझे इस के लिए शायद थोड़ा सा हक भी है, चूंकि मुझे ४॥ साल उस में काम करने का मौका मिला है। मुझे माफ किया जाय अगर मैं यह कहूं कि मुझे थोड़ी सी शिकायत है कि इसकी तरफ उतनी तवज्जह नहीं है जितनी होनी चाहिए या जितनी की वह मुस्तहक है। हमारे बजट में जो

[श्री सुल्तान आलम खां]

कुछ दिया हुआ है, उसे काफी बढ़ाने की जरूरत है। मसलन्, हमारे सामने जो किताब रखी गया है, उसमें एलापैथिक, यूनानी और आयुर्वेदिक डिसपेंसरीज का जिक्र है,लेकिन होमियोपैथी का जिक्र नहीं है। मिनिस्टर साहेब को इल्म होगा कि हमारे सूबे में इस समय २४ होमियोपैथी की डिस्पेंसराज काम कर रही हैं। मैं चाहता हूं कि जैसे कानपुर में मेडिकल कालेज तेजी से बन रहा है, यहां भी होमियोपैथी का कालेज वैसा ही बने।

यू० पी० मेडिकल और पब्लिक हेल्थ के एसिस्टेंट्स और प्रोविंशियल हाईजीन इन्स्टीटचूट की तरफ मैं मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। इन लोगों की एसोसिएशन का रिप्रेजेण्टेशन आया हुआ है, और उनका मामला भी गौर के काबिल है। इन के साथ जो दूसरी जगहों पर काम कर रहे हैं उनकी तनख्वाहों के इजाफे का सवाल है और उनकी तरफ भी कुछ तवज्जह होनी चाहिए।

अक्सर यहां सोशलिस्ट पैटर्न आफ सोसाइटी का जिक्र किया जाता है और इसके सिलसिले में डिसेण्ट्रलाइजेशन और प्रोविंशियलाइजेशन का भी सवाल उठता है। लेकिन यह ऐसी बात है कि इसके बारे में कोई दो रायें नहीं हो सकती। उधर के बैठे हुए लोग इसके लिए कमिटेड हैं, लेकिन हर मौके पर यह सवाल उठाना मुनासिब नहीं है। जिस शख्स को पब्लिक हेल्थ से जरा भी दिलचस्पी है वह डिसेन्ट्रलाइजेशन पसन्द नहीं करेगा। मेरी हमेशा यह ख्वाहिश रही है कि हमारे सूबे का हर अस्पताल, चाहे वह देहात में हो या शहरी रकबे में हो, प्रोविंशियलाइज कर दिया जाय। हमारे यहां यह सवाल भी दरपेश है कि हम डिस्ट्रिक्ट बोर्डस् को रखें या न रखें और रखें तो किस रूप में रखें। उन्होंने दिखा दिया है कि उन का १०, १५ साल का एडमिनिस्ट्रेशन का रेकार्ड इत्मीनानबख्श नहीं है। अगर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का स्ट्रक्चर ही खत्म किया जाय तो मैं चाहूंगा कि सब अस्पतालों को प्रोविंशियलाइज कर दिया जाय। यह भी देखना है कि वहां इक्विपमेंट, दवाइयां और सब चीजें काफी हैं या नहीं।

इस सूबे में ७, ८ साल पहले एक काउन्सिल आफ फिजिकल कल्चर थी। पहले वह एजुकेशन में थी, फिर पब्लिकहेल्थ में गयी और इसके बाद गायब हो गयी। अब एक स्पोर्टस् काउंसिल हमारे सूबे में है, जिसका इस्फेयर और काम महदूद है। मैं चाहता हूं कि काउन्सिल आफ फिजिकल कल्चर की तरफ सरकार की तवज्जह जाय। इंग्लिस्तान में और शायद दूसरे मुल्कों में भी ऐसे कानून हैं जिन से हर शख्स को मजबूर किया जाता है कि वह किसी न किसी किस्म की एक्सरसाइज करे, जिस से नेशनल हेल्थ ठीक हो सके। अगर हमारी गवर्नमेंट भी इस तरफ तवज्जह करे, तो यह पब्लिकहेल्थ के लिए बड़ा अच्छा होगा। इससे अस्पतालों का खर्चा कम होगा और आखिर में हमारा बहुत सा रुपया बच सकेगा। इस से हमारी सबकी सेहत बेहतर होगी, इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकती हैं। हम इस काबिल होंगे कि दुनिया में सबसे ज्यादा अच्छे और तन्दुरुस्त लोगों का मुकाबला कर सकेंगे।

(इस समय १ बज कर १७ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर १८ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री गयाबख्शसिंह, के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

*डाक्टर खमानीसिंह (जिला मुरादाबाद)---श्रीमन्, अधिष्ठाता महोदय, यह जो दो ग्राण्ट्स मेडिकल और हेल्थ की आप के सामने पेश हुई हैं उसका बजट ६ करोड़ कुछ रुपये का है। यह बजट हमारे सूबे की आबादी को देखते हुए बहुत कम है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जितने आदमी हमारे सूबे के हैं उतना ही रुपया इस बजट में है यानी फी कस एक रुपया आता है। इस रुपये के हिसाब से आप देख सकते हैं कि हमारी तन्दुरुस्ती का क्या हाल होगा। जहां तक इन्सान की जिन्दगी का ताल्लुक है, सब से पहली जरूरत इन्सान को अन्न की है और उस के बाद दूसरी जरूरत दवा की है। अगर इन्सान की तन्दुरुस्ती ठीक नहीं है, तो दुनिया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के अन्दर वह एक इन्सान नहीं कहलाया जा सकता। श्रीमन्, यही नहीं हमें एक बहुत बड़ा काम डिफेंस का भी करना पड़ता है। जिस वक्त किसी हमले का खतरा होता है हम मिलिटरी वालों की मदद करते हैं। उनको हर प्रकार की सुविधा पहुंचाते हैं, लेकिन अगर हमारे डाक्टर अच्छे नहीं हैं तो हमारे सिपाही अच्छी तरह से नहीं लड़ सकते। इन सब बातों को देखते हुए इस बात की जरूरत है कि हम जितनी हेल्प इस डिपार्टमेंट को दे सकें उतनी ही थोड़ी है।

श्रीमन्, एक सवाल के उत्तर में माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी ने यह बताया कि बहुत सी डिस्पेंसरियां इसलिए खाली हैं कि डाक्टर नहीं मिलते हैं। श्रीमन्, कल मैं एक मेडिकल आफिसर से मिला, तो उन्होंने बताया कि यहां डाक्टरों की कमी नहीं है। लेकिन बात यह है कि जिन डिस्पेंसरियों में वे भेजे जाते हैं वे डिस्पेंसरियां खराब हैं, वहां का मैनेजमेंट और इक्विपमेंट ठीक नहीं है, इस लिए वहां लोग जाना पसन्द नहीं करते हैं। इस कारण से देहात में गरीबों को जिन को मेडिकल हेल्प की ज्यादा जरूरत है, उन को वह नहीं मिलती। जो रुपया इस काम पर खर्च होता है उस से ज्यादातर शहर वाले ही फायदा उठाते हैं। मेडिकल अस्पतालों में जो गांव वाले आते हैं, उन को जगह नहीं मिलती। इसके लिए मैं स्वास्थ्य मन्त्री जी से यह निवेदन करना चाहता हू कि मेडिकल कालेज में गांव वाले लड़कों की भर्ती किया जाय जिस से पढ़ने के बाद वे गावों में रहें, क्योंकि शहर वाले लड़के शहर में रहना ही पसन्द करते हैं। इसके अतिरिक्त देहात में जो डिस्पेंसरीज हैं उन की इमारत नहीं है और अगर इमारत भी है तो मेडिकल आफिसर के लिए वहां पर क्वार्टर नहीं है। श्रीमन्, ये दो खास दिक्कतें हैं जिस से हमारी डिस्पेंसरीज में मेडिकल आफिसर नहीं पहुंचते। इस के बाद श्रीमन्, मैं आप से यह अर्ज करूंगा कि आजकल के जमाने में हम डाक्टरों के लिए बड़ी परेशानी यह है कि आजकल जिस को देखिये वही शाम को एक थर्मामीटर और एक स्टेथस्कोप खरीद कर ओवर नाइट सुबह में डाक्टर बना हुआ है। इसको एक किस्म का भ्रष्टाचार कहिये या जो कुछ कहिये, लेकिन यह डाक्टरों के लिए बड़ी परेशानी की बात है। मैं तो समझता हूं कि यह बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, जिस से लोग बहुत परेशान और मिसगाइडेड हो रहे हैं। तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इसके लिए कोई इस किस्म का कानून बनाना चाहिए, जिस से जो क्वालिफाइड हों, उन्हीं को डाक्टरी करने की इजाजत दी जाय और जो अनक्वालिफाइड हों उन को इस किस्म की इजाजत न दी जाय।

श्रीमन्, एक चीज और है। अभी हमारे दोस्त श्री झारखंडे राय जी ने यह कहा कि मेडिकल कालेज और अस्पतालों में बड़ा भ्रष्टाचार है। इस बात को सभी मानेंगे कि भ्रष्टाचार है और बड़ी बदइन्तजामी है। पैसा भी ज्यादा लगाया जाता है और उसको खर्च गलत तरीके से किया जाता है, लेकिन यह कहा जाय कि मेडिकल कालेज में ही भ्रष्टाचार है तथा और जगह नहीं है, ऐसी बात नहीं है। और जगह भी देखने से मालूम हुआ है कि सब जगह भ्रष्टाचार है। उसकी वजह जानने के लिए मैं अपने दोस्तों से अर्ज करूंगा कि आप को इस बात को देखना है कि फोकस आफ इन्फेक्शन कहां है, ताकि उसका इलाज ठीक तरह से किया जा सके।

श्रीमन्, जहां तक एलोपैथिक पद्धति का ताल्लुक है, सब लोगों का यह ख्याल है कि चिकित्सा की जितनी पद्धतियां हैं, उन में एलोपैथिक पद्धति औरों से आगे बढ़ी हुई है और इसका जो तरीका है वह साइन्टिफिक बेसिस पर निर्भर है। यह तरीका ऐसा नहीं है जो ऊहपटांग सा हो। श्रीमन्, मैं आप से अर्ज करूंगा कि जितने होमियोपैथिक डाक्टर हैं, उन में ९५ परसेंट ऐसे हैं जो साइनबोर्ड तो लगाये हुए हैं होमियोपैथी का, लेकिन इलाज एलोपैथिक का ही करते हैं। बहुत से वैद्य भी ऐसे हैं जो एलोपैथिक का ही इलाज करते हैं, जब कि उनका साइनबोर्ड वैद्य का ही है। श्रीमन्, यह तरीका बहुत गलत है। इस लिए कोई ऐसा कानून बनाना चाहिए, ताकि जो आदमी जिस चीज में क्वालिफाइड हो, वह उसी में प्रैक्टिस करे। उस को यह एलाऊ न हो कि वह कई किस्म की प्रैक्टिस कर सके।

[डाक्टर खमानी सिंह]

अभी तीन चार दिन हुए, मैंने अखबार में यह देखा कि एक लड़के की मौत हो गयी, उस पर तीन डाक्टरों को सजा दी गयी। बहुत ठीक, मैं बहुत खुश हुआ, कि इस किस्म की गलती पर जल्दी से जल्दी कार्यवाही हुई। जो लोग इस किस्म की हरकतें करें उन को इस तरह की सजा देनी ही चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हमारा यह भी खयाल है कि जब कोई आदमी बीमार होने की वजह से छुट्टी मांगता है और उस को छुट्टी नहीं दी जाती, जिसकी वजह से उस की मौत हो जाती है, तो ऐसे आदमी को भी सजा देनी चाहिए जो छुट्टी न देने का जिम्मेदार हो।

देहातों में जितनी डिस्पेंसरीज हैं उन में इण्डोर पेशेन्ट्स के रहने के लिए कोई इन्तजाम नहीं है, जिससे लोगों को बड़ी परेशानी होती है। वहां इण्डोर पेशेण्ट्स के रहने के लिए इन्तजाम करना बहुत जरूरी है। जब तक इण्डोर पेशण्ट्स के रहने का सही इन्तजाम नहीं होगा, तब तक ज्यादा अच्छी तरह से इलाज नहीं किया जा सकता है। इसलिए जरूरी है कि जितनी आउटडोर डिस्पेंसरीज हैं, उन में इण्डोर पेशेण्ट्स के रहने का भी इन्तजाम किया जाय।

मैं आप से केवल दो बातें और कह दूं। कल हमारे माननीय मन्त्री श्री अली जहीर साहब ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि एक बच्चा अपनी मौत से मर गया। मेरा खयाल है कि यहां इस तरह के जवाब देना, जब कि यहां एक दो क्वालिफाइड आदमी भी हैं उनके लिए शोभा नहीं देता। उन को भी जानना चाहिए कि मौत कोई बीमारी नहीं है, उससे कोई मर नहीं सकता, मौत तो एक रिजल्ट है वह कोई काज नहीं है, काज तो उस का कोई बीमारी ही हो सकती है, मौत कोई वजह नहीं है। इसी तरह से एक साहब की जेल में मौत का जिक्र आया तो मन्त्री जी की तरफसे कहा गया कि वह आदमी ऐनीमिया और जनरल डेबिलिटी से मर गया। यह तो उस की जनरल कण्डीशन थी, उसकी भी मौत का कारण कुछ और ही रहा होगा। जनरल डेबिलिटी का भी तो कोई काज होगा मैं चाहता हूं किजो डाक्टर ऐसी नेग्लिजेंस करते हैं और इस तरह के कारण बताते हैं, उनके खिलाफ ऐक्शन लेना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि सही वजूहात क्यों छिपाते हैं और ठीक बीमारी क्यों नहीं बताते हैं। इस लिए मैं आखिर में अर्ज करूंगा कि यह ग्रान्ट बहुत कम है और इस को बढ़ाया जाय।

कुमारी कमलकुमारी गोइन्दी (जिला इलाहाबाद)—माननीय अधिष्ठाता जी, सर्वप्रथम तो मैं आप को धन्यवाद देती हूं कि आप ने मुझे इस वाद विवाद में हिस्सा लेने को थोड़ा सा समय दिया। मैं माननीय मन्त्री जी को इस मांग के लिए जो उन्होंने अनुदान संख्या १९ और २० के अन्तर्गत मांगी है, समर्थन के लिए ही खड़ी हुई हूं, जहां तक इस विभाग के काम का सम्बन्ध है मैं अपने दस वर्षों के तजुर्बे से कह सकती हूं कि जिस तरह से इस विभाग ने इस काम को आगे बढ़ाया है, उसके लिए वे मुबारक बाद के पात्र हैं। हमारी जनता अभी इतनी गरीब और निस्सहाय है कि उसके अन्दर एक दो, तीन या चार वर्ष में कार्य होने वाला नहीं है। मैं अपने अनुभव से बता सकती हूं कि किस तरह से कर्मचारियों ने हमारे साथ मिलकर काम किया है और कैसे वह संकट को दूर करने में सहायक रहे हैं। मैंने स्वयं सैकड़ों की तादाद में रिकेट के केसेज ले जाकर डाक्टरों के साथ मिलकर ठीक कराये हैं और मैं तरह-तरह की बीमारियों के केस लेकर उन के पास पहुंची हूं और डाक्टर भी जनता के सच्चे हितैषी और सहायक के रूप में उनके साथ पेश आये हैं, दृष्टिकोण में काफी परिवर्तन आया है। उनकी इस सराहना के लिए मैं एक किताब लिख सकती हूं और उन की जितनी प्रशंसा की जाय वह कम है। मैं बताना चाहती हूं कि इलाहाबाद के कर्मचारी आजकल इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं कि कहीं से भी उन को बीमारी की इत्तिला होती है, तो वह वक्त कम होते हुए भी पूरे जोर से जाते हैं और इत्तला की बात ही नहीं वह इशारे पर ही जाते हैं। वहां पर नम्बर पर दवा मिलती है और जो भी सहायता जनता की हो सकती है, वह होती है।

यह जो ६ लाख रुपया गर्भवती स्त्रियों को दूध बांटने के लिए रखा गया है, मैं ने पिछले दस साल से स्वयं दूध बांटा है, और विमेन कान्फ्रेंस की ओर से भी बांटा है। मेरा अनुभव है कि यह दूध बहुत कम स्त्रियों को मिल पाता है, पहले यह धनराशि केवल ३ लाख ही थी, अब ६ लाख हो गयी है। करीब ५० लाख स्त्रियां इस प्रान्त में हर साल गर्भवती होती हैं। इस लिए यह रुपया बहुत कम है। मेरा अनुभव है कि लोअर मिडिल (lower middle) क्लास और मोहमडन क्लास की स्त्रियां बहुत कम दूध लेने आती हैं और घर पर जाने पर भी दूध मुश्किल से लेती हैं और किस तरह से उसका प्रयोग होता है उसका वर्णन करना कठिन है। गरीब जनता को सामने रखते हुए मेरा सुझाव है कि इस ६ लाख की धनराशि से अगर आप गाय और भैंस खरीद कर गरीब ग्रामीण जनता में बांट दें, तो इस से जरूरतमन्द लोगों के पास दूध भी पहुंच सकता है और दूध भी इतना होगा कि जितना आप इस धनराशि से नहीं खरीद सकते। इसके अलावा जो सोशल वर्कर्स हैं उनका ध्यान और कामों में लग सकेगा। इस से एक फायदा यह भी होगा कि काफी लोगों को इस से काम भी मिलेगा और अनएम्प्लायमेंट भी दूर होगा। अगर आप फ्री नहीं दे सकते तो तकावी के तौर पर दीजिये, इस से करोड़ों रुपये की गायें और भैंसें जनता में पहुंच जायेंगी।

मेरे पूर्व वक्ता ने यह कहा कि गांवों की तरफ ध्यान नहीं है। मेरे खयाल से ऐसा नहीं है लेकिन कठिनाई क्या है? वह यह है कि जितने डाक्टर, नर्सेज और मिड-वाइव्ज ट्रेन्ड होती हैं वे शहरों के अन्दर शहरों के वातावरण में होती हैं। वे देहात में जम कर काम नहीं करतीं। जहां मैं किसी नर्स को ले जाती हूं, तो वह वहां १०, १२ दिन से ज्यादा नहीं ठहरती और शहर में काम मिलते ही चली आती है। मेरी कास्टीट्युएन्सी में २ लाख की आबादी है, लेकिन एक भी मिडवाइफ वहां पर नहीं है, जब कि हेल्थ आफिसर चाहते हैं कि वहां पर एक तो रहे। मेरा सुझाव है कि जितना का पैसा खर्च करके मेडिकल कालेज खोले जाते हैं, नर्सेज और मिडवाइव्ज को ट्रेन्ड करने में जितना खर्च होता है, उन के केन्द्र देहातों में खोले जायं। भले ही वह सड़कों के किनारे हों। उससे लाभ यह होगा कि जो मरती हुई औरतें लायी जाती हैं, मैं आपको नहीं बता सकती कि उनकी क्या हालत होती है, आधा बच्चा बाहर और आधा भीतर, तो अगर गांव में ही यह सुविधा होगी, तो वहीं निकट ही इलाज हो सकता है। दूसरे यह कि गांवों में अस्पताल के लिए तथा और कामों के लिए इमारतें बनेंगी तो गांव की जनता को काम मिल सकेगा। इसके अलावा सब से अधिक लाभ यह होगा कि हमारा दृष्टिकोण बदलेगा जो अभी तक नहीं है। अगर गांव के वातावरण में हम ने ट्रेनिंग पायी होगी, वहां की सुविधाओं और असुविधाओं को समझते होंगे, तो शहर के सुनहलेपन की तरफ नहीं भागेंगे।

इसलिए हमें वहीं ट्रेनिंग दे दी जाय, जहां कि सेवा हम से करवानी हो। वहीं स्कूल हो जाय, वहीं कालेज हो जाय, ताकि काम अच्छी तरह से चल सकें। यह भी लाभ होगा कि जितनी आजकल ऊपर की जाति की स्त्रियां हैं, वह अब कुछ नर्सिग में आ रही हैं, बहुत अच्छी बात है। नर्सिंग में स्त्रियों की कमी है, उन को अवश्य आना चाहिए, लेकिन वह आती हैं तो हरिजन स्त्रियों का काम वह छीन रही हैं। अगर ट्रेनिंग गावों में होंगी तो वहीं की औरतें ट्रेण्ड होकर वहीं सेवा कर सकेंगी। इस लिए थोड़े से जो मैंने सुझाव दिये, वह इस लिए कि धन इतना कम है और बीमारी इतनी ज्यादा है कि उस को हम एक हिसाब से लगा सकें और गरीब जनता तक एक एक पैसे का हिसाब पहुंचा सकें। यह न हो कि १०० रुपया खर्च करें, दस रुपये का लाभ पहुंचे। श्रीमन्, मैं आपका धन्यबाद करती हूं कि आप ने मेरे सुझावों को ध्यान से सुना होगा।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज चिकित्सा और जनस्वास्थ्य की जो मांग है प्रायः ६ करोड़ रुपये की, उस पर हमारे साथी श्री झारखंडे राय जी ने जो कटौती के प्रस्ताव पेश किये हैं, मैं उनका समर्थन करने के लिए खड़ा हूं।

[श्री देवनारायण भारतीय]

श्रीमन्, मैं आप के द्वारा सब से पहले सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने आयुर्वेद की ओर जो उपेक्षा की दृष्टि रखी है उस से हमें सन्तोष नहीं है।

श्री हुकुमसिंह विसेन—और ज्यादा उपेक्षा करें ?

श्री देवनारायण भारतीय—मैं समझा नहीं आपने क्या कहा ? अच्छा ठीक है। तो यों कहिये कि आप आयुर्वेद को मिटा ही देना चाहते हैं। लक्षण तो ऐसे ही हैं आपके। छः करोड़ रुपये के बजट में ३२ लाख रुपये का प्राविजन आयुर्वेद के लिए करना यह इस बात का प्रमाण है कि आप उपेक्षा की ओर कितना आगे बढ़ रहे हैं। मैं बतलाना चाहता हूं और मेरे और साथियों ने भी इस बारे में कहा है कि देहात की जनता को हम अस्पतालों से जिन में एलोपैथी के द्वारा इलाज होता है उतना लाभ नहीं पहुंचता। देहात की जनता उन अस्पतालों तक इलाज कराने पहुंच नहीं पाती और अगर पहुंच भी जाती है, तो वहां के डाक्टर, वहां के कर्मचारी वैसी ही उपेक्षा का व्यवहार उन के साथ करते हैं जैसे हमारे मन्त्रिगण इस समय बजट का प्राविजन करते समय यहां अपना व्यवहार दिखला रहे हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि हमारे प्रान्त की आबादी प्रायः साढ़े छः करोड़ है और उस साढ़े छः करोड़ में एक करोड़ ऐसे लोग होंगे कि जो नगर अथवा उसके समीपवर्ती स्थानों में रहते होंगे। प्रायः साढ़े पांच करोड़ जनता ऐसी है कि जो देहात में रहती है। इसलिए मेरे विचार से इस एलोपैथी और आयुर्वेद में इस रकम का वितरण भी इसी रेशियो से होना चाहिए कि साढ़े पांच हिस्सा उसका देहात के लिए आयुर्वेद के द्वारा व्यय किया जाय और एक हिस्सा एलोपैथी के द्वारा नगरों में व्यय किया जाय और उससे नगर के लोग लाभ उठायें और जो आयुर्वेद पर व्यय किया जाय उस से देहात के लोग लाभ उठावें।

मैं सदन के सामने आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि आज एलोपैथी हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा दो सौ वर्षों से है। जब से योरपीय लोगों का हमारे देश में आगमन आरम्भ हुआ, तभी से एलोपैथी पद्धति भी हमारे देश में आयी। उससे पहले यहां केवल आयुर्वेदिक और यूनानी पद्धति द्वारा ही इलाज होता था। इन २०० वर्षों में एलोपैथी को जो इतनी प्रधानता मिली उसका कारण था अंग्रजों का राज्य। अंग्रेज लोगों को गये दस वर्ष बीत चुके हैं और इन दस वर्षों में हम को चाहिए था जिस प्रकार हम उन की और चीजों का तिरस्कार कर रहे हैं उसी प्रकार इस एलोपैथी के रोग को भी हम को छोड़ देना चाहिए था, लेकिन वह रोग बदस्तूर कायम है। मैं मन्त्री महोदय से प्रार्थना करना चाहता हूं कि वे इस बात का प्रयत्न करें कि अंग्रेजों के साथ साथ वे एलोपैथी प्रथा को भी इस देश में खत्म करें। मैं इस बात को मानता हूं कि कुछ रोगों में एलोपैथी में विशेष रूप से लाभ होता है, तो उसका हम उतना ही उपयोग करें और उन अच्छी बातों को हम उस में से ले लें और जो अधिकांश बुराइयां हैं जो हमारे देश में जलवायु के प्रतिकूल हैं, उन को हम छोड़ दें और उन के स्थान पर हम आयुर्वेद को ग्रहण करें।

आयुर्वेद एक परिपक्व इलाज व्यवस्था है और हजारों वर्ष से इस देश में चालू है। आयुर्वेद के ज्ञाता चरक, सुश्रुत और बागभट्ट जिनके नाम हमारे भारतवर्ष में ही नहीं संसार में प्रसिद्ध हैं आज से हजारों वर्ष पहले उन्होंने आयुर्वेद पद्धति को सम्पूर्ण कर दिया था, उस में किसी प्रकार की कमी नहीं रह गयी थी। एलोपैथी बावजूद सब प्रकार के समर्थन के भी आज उस पूर्णता को नहीं पहुंच सकी है, जिस पर आयुर्वेद आज से हजारों वर्ष पहले पहुंच चुका है। एलोपैथी के बहुत से इलाजों के बारे में नये नये विचार प्रकट होते हैं। बी० सी० जी० के बारे में हमारे देश के प्रमुख नेता राजगोपालाचारी ने अपना भिन्न मत प्रकट किया है। चेचक के टीके के बारे में बहुत से डाक्टरों का मत है कि चेचक का टीका शरीर के लिए भारतवर्ष के जलवायु में हानिकारक होता है। इस प्रकार मैं कह सकता हूं कि एलोपैथी आज भी, बावजूद इसके कि उस को सरकार की ओर से समर्थन प्राप्त है, परिपक्व नहीं है। इन बातों की ओर ध्यान देते हुए हमें आयुर्वेद की ओर ज्यादा ध्यान देना है।

दूसरी सब से महत्वपूर्ण बात, श्रीमन्, यह है कि आयुर्वेद इलाज हर बीमारी के लिए बड़ा सस्ता और सुगम है और एलोपैथी बड़ी कष्टसाध्य पद्धति है जिस में हमारे देश के गरीब लोग व्यय का भार नहीं उठा सकते। इस लिए भी हम आयुर्वेद का अधिक समर्थन करने के लिए मजबूर हैं। इस लिए मैं सरकार से यह चाहूंगा कि जितने व्यय में वे एक एलोपैथिक औषधालय खोलते हैं उतने ही व्यय में वे चार ऐसे आयुर्वेद के औषधालय खोल सकते हैं। देहात के जीवन में आयुर्वेद की पद्धति से इलाज किया जाय।

मैं श्रीमन् के द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां मेडिकल कालेजेज से पासशुदा डाक्टरों को प्रोत्साहन देते हैं वहां झांसी आयुर्वेद कालेज, पीलीभीत आयुर्वेद कालेज और काशी विश्वविद्यालय आयुर्वेद कालेज से पासशुदा वैद्यों को भी देहातों में एलोपैथी अस्पताल न खोल कर आयुर्वेद औषधालयों को खोल कर प्रोत्साहन दिया जाय। वे एलोपैथी का भी ज्ञान रखते हैं और जिन-जिन रोगों में एलोपैथी की आवश्यकता हो उस में वे एलोपैथी की भी सहायता ले सकते हैं और अधिकांश इलाज अपने आयुर्वेद द्वारा कर सकते हैं।

श्रीमन्, मैं आप के द्वारा सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि देहातों में आगे जितने औषधालय या अस्पताल खोले जायं, तो उन में आयुर्वेद कालेजेज के पासशुदा डाक्टरों को रखा जाय और आयुवद पद्धति को इलाज के लिए प्रधानता दी जाय। मैं इन शब्दों के साथ श्री झारखंडे राय जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री रामेश्वर प्रसाद (जिला राय बरेली)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मेरा यह निश्चित मत है कि यह मद मनुष्य के जीवन की पहली मद है अगर स्वास्थ्य और चिकित्सा का प्रबन्ध उचित नहीं हो तो संसार के काम के लिए मनुष्य बेकार हो जायंगें। उत्तर प्रदेश में जैसा कि झारखडे राय जी ने कहा कि गरीबी ने घर कर लिया है तो जहां गरीबी है, भुखमरी है और ९० प्रतिशतलोग गांवों में रहते हैं और उन में अज्ञानता है और यहां तक है कि चिकित्सा की ओर ध्यान न देकर देवी देवताओं में आस्था रखकर मरीज को अच्छा करने के फालोअर हों और गांवों में बड़ी गंदगी है कि घर से निकले और कूड़ा दरवाजे के सामने डाल दिया। इस तरह की उन लोगों की भावना है।

इसके साथ ही साथ यहां के लोग ऐसे हैं जिन को मिलावट करने में और रुपये के आगे दूसरे की जिन्दगी को लेने में जरा भी हिचक नहीं होती है। ऐसी जटिल समस्याएं इस प्रदेश में हैं। तो मैं समझता हूं कि इस विभाग के काम करने वालों की और मन्त्री जी की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। मैं समझता हूं कि इस विभाग के कर्मचारी और मन्त्री जी बड़े सौभाग्यशाली हैं, जिनको मनुष्यों की इस दिशा में सेवा करने का मौका मिला है, मैं उनको बधाई देता हूं। इस विभाग ने बड़ी भारी सेवा की है।

मैं मोटे तौर पर बताना चाहता हूं कि १९४६-४७ में १७४.३४ लाख रुपये इस विभाग पर खर्च होते थे जो १९५६-५७ में ५४२.०९ लाख रुपये हो गये। मेरे कहने का मतलब यह है कि पर कैपिटा एक्सपेंडीचर १९४६-४७ में ४ आने ११ पाई था वह १९५६-५७ में १४ आने ४ पाई हो गया। इतना ही कह देने से माननीय सदस्य समझ सकते हैं कि इस विभाग ने थोड़े से समय में कितनी तरक्की की है।

इसके साथ ही साथ मैं यह समझता हूं कि १९४६-४७ में यहां डेथ रेट १५.६ थी, जो अब ९.८ है यह इसकी तरक्की करने का प्रत्यक्ष और ज्वलन्त उदाहरण है। इसके साथ ही साथ आप देखें कि इस प्रदेश में तराई के हिस्से होने से मलेरिया फैलती है, छुआछूत की बीमारी होती है और कालरा फैलता है। कालरा के बीज नैपाल से आ जाते हैं। इन कारणों से यहां की समस्याएं बड़ी जटिल हैं, लेकिन आप देखें कि इस तरफ भी रोक थाम के लिए सरकार

[श्री रामेश्वरप्रसाद]

प्रयत्नशील रही है। मलेरिया से १९४७ में १०.७ प्रति हजार मृत्यु होती थीं जो अब .९४ प्रति हजार मृत्यु होती हैं। इस से साबित होता है कि छुआ छूत और मलेरिया को भयंकर बीमारियों पर काबू पाने के लिए सरकार ने किस प्रकार कोशिश की है।

इसके साथ ही साथ टी० बी० एक इतना भयंकर रोग है, जिस से इस सदन का प्रत्येक माननीय सदस्य वाकिफ है। गांवों से तमाम टी० बी० के मरीज हम लोगों के कमरों में शरण लते हैं और हम लोगों के पैरों पड़ते हैं कि उनका इन्तजाम किया जाय। आंसू निकल आते हैं जब टी० बी० के अस्पताल में जाते हैं। कुछ प्रकृति का भी प्रकोप है कि टी० बी० की बीमारी बढ़ रही है। लेकिन सन् १९४६ में जहां केवल ३१७ बेड्स टी० बी० के थे, वहां अब १,०५६ बेड्स का इन्तजाम है। इस प्रकार टी० बी० के रोग से लड़ने के लिए हमारी सरकार ने पूरी तैयारी कर रखी है।

अभी एक कट मोशन पेश करते हुए श्री झारखंडेराय जी ने कहा कि स्वास्थ्य के सम्बन्ध में सरकार की नीति का कोई पता हीं नहीं है। उन्होंने वहां समाजवाद ढूंढने की कोशिश की। यद्यपि झारखंडे राय जी के समाजवाद को सभी लोग जानते हैं, लेकिन मैं उन को बताना चाहता हूं कि चिकत्सा विभाग की ओर से जच्चा बच्चा कल्याण की योजना, श्रमिकों के स्वास्थ्य की योजना, कुष्ट रोगियों के लिए आश्रम, जो टी० बी० के रोगी लाचार और गरीब हैं उन को मुफ्त सहायता और मिनिस्टीरियल फंड से रुपया देने का इन्तजाम तथा नगरों में शिशुओं के खेलने के लिए पार्क वगैरह का इन्तजाम, आखिर इसको समाजवादी व्यवस्था नहीं कहेंगे तो क्या कैपिटलिज्म या डिक्टेटरशिप की व्यवस्था कहेंगे ? मैं नहीं समझता हूं कि क्रीड़ा स्थलों में डालमिया और टाटा के बच्चे कोई खास सुविधा पायेंगे और हमारे गरीब के बच्चे सुविधा नहीं पायेंगे। मैं समझता हूं कि उन में गरीब और अमीर सभी के बच्चे जा सकते हैं। साथ ही साथ टी० बी० के गरीब मरीजों के लिए और खास तौर से हरिजनों के लिए इस बजट में जो व्यवस्था माननीय मन्त्री जी ने की है वह समाजवाद की ओर एक क्रान्तिकारी कदम है। यह सम्भव है कि पैसे की तंगी की हालत में वह उतना न कर सके, लेकिन उनकी नीति की पिक्चर हमारे सामने है। झारखंडे राय जी न मालूम किस चश्मे से देखते हैं कि उन को कुछ दिखलायी ही नहीं पड़ता है। यह कोई अधिक बुद्धिमानी की बात नहीं है। वैसे वे मुझ से बुजुर्ग हैं, मैं उनका लिहाज करता हूं।

साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि मिलावट के लिये सरकार की ओर से उसे रोकने का कोई इन्तजाम नहीं है। मिलावट एक ऐसी चीज है जिससे हर एक माननीय सदस्य को तकलीफ है और वह सोचा करता है कि इस दिशा में क्या कदम उठाया जाय, जिससे इसको खत्म किया जा सके और सरकार भी इसके लिये चिन्तित है। जो पुस्तिका स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बंटी है उसके पेज १८ को अगर वे देखते तो उसमें उनको लिखा हुआ मिलता कि ४,४६६ मुकदमे एडल्ट्रेशन के सरकार ने चलाये। उनमें से २,०५६ अदालतों द्वारा कन्विक्ट हुए। इसके बाद मेरी समझ में नहीं आता कि बगैर इनको पढ़े हुए किस तरह से टीका कर दी जाती है।

उन्होंने यह भी कहा कि विभिन्न रोगों के अन्वेषण के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। हमारी सरकार केन्सर रोग के लिये, मस्तिष्क के रोगों के लिये और नेत्र रोगों के लिये और न जाने किन-किन के लिये अध्ययन कराने की कोशिश कर रही है और मेडिकल कालेज में अभी हाल ही में पैथोलाजी की बिल्डिग तैयार हुई है। इसके बाद भी किस तरह से कह दिया जाता है मेरी समझ में नहीं आया।

एक बात मैं प्राइवेट प्रैक्टिस के सिलसिले में कहना चाहता हूं। मेरी ही नहीं, जितनी कमेटीज और जितने एक्सपर्ट्स हैं सबकी यही राय है। भोर कमेटी, खेर कमेटी, और गुडएनफ कमेटी जो इंगलैण्ड में सन् १९४४ में बैठी थी और खुद कैबिनेट की कमेटी ने भी यही राय दी है।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---आन ए प्वाइंट आफ आर्डर, सर। मैं उनकी इत्तिला के लिये बतलाना चाहता हूं कि भोर कमेटी सन् ४४ में नहीं ४६ में बैठी थी।

श्री रामेश्वरप्रसाद--आप जब कहें तो सोच समझ कर कहें। मैं इंगलैण्ड की गुड एनफ कमेटी के लिए कह रहा था और उसी का रेफरेंस कर रहा हूं। मैं यह कह रहा था कि इन सब कमेटियों की राय है कि प्राइवेट प्रैक्टिस बन्द हो जानी चाहिये। इससे मेडिकल कालेजों में टीचिंग व रिसर्च को बहुत नुकसान पहुंचता है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस ओर सोचेंगे क्योंकि वे खुद इस ही दिशा में दिलचस्पी रखते हैं। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

*श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मंत्री महोदय के चिकित्सा अनुदान में राय साहब ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है मैं उसके समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, आप जानते हैं कि यह विभाग ऐसा है, जिसमें काम करने वाले समाजसेवा की दृष्टिकोण से काम करते हैं, लेकिन रामायणराय जी ने भी और राय साहब ने भी बताया है कि इसमें भी भ्रष्टाचार इतना अधिक हो गया है कि जिसका कोई ठिकाना नहीं है। एक तरफ टी० बी० का मरीज कर ह रहा हो और दूसरी तरफ उससे रिश्वतें ली जा रही हों। आज के युग में इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती और यह चीजें बन्द हो जानी चाहिये। मैं समझता हूं कि इस तरह की बातें मंत्री जी भी पसन्द नहीं करते। आज आजादी प्राप्त होने के १० स ल बाद भी अस्पतालों के कर्मचारियों में यह भावना नहीं है कि वे आजाद हिन्दुस्तान के नागरिक हैं और उन्हें एक आजाद नागरिक की तरह से यह अनुचित बातें नहीं करनी चाहिये। इसलिये मैं समझता हूं कि इस तरह की बुराइयों का अन्त होना बहुत जरूरी है।

दूसरी बात जो मुझे कहनी है आपसे वह यह कि अस्पताल तो बहुत ज्यादा खुल गये हैं यह तो सही है, लेकिन यह भी सही है कि मरीजों का इलाज नहीं हो पा रहा है। आप जानते हैं कि मरीज बहुत काफी बढ़ रहे हैं, हमारे जिले में एक पिंडरा अस्पताल है। वहां का मैंने निरीक्षण किया। वहां के लोग, कंपाउन्डर, नर्स, डाक्टर, सब काफी होशियार हैं, काफी अनुभवी हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि वहां जो गवर्नमेंट से मदद मिल रही है वह केवल १५० रुपये सालाना की है। आप सोचिये कि जिस अस्पताल में रोजाना १०० मरीज आता हो और उसकी सालाना मदद १५० रुपये की हो तो उससे उस इलाके के लोगों को कितना फायदा हो सकता है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि केवल इमारत बना देने या औजार दे देने से ही पूरा फायदा लोगों को नहीं हो सकता, दवाई का पूरा इन्तजाम भी होना चाहिये। वहां देहात के लोग गरीब हैं, खेतिहर मजदूर हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि कीमती दवायें खरीद कर अपना इलाज करायें। इसलिये मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे देहातों के अस्पताल की ओर अधिक ध्यान देने की कृपा करें।

(इस समय ३ बज कर ५ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

तीसरी बात जो मुझे कहनी है वह यह कि हमारी सरकार और हमारे मंत्री महोदय को देशी दवाइयों पर कुछ कम भरोसा है। उनको एलोपैथिक के साथ आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक तथा देहाती जड़ी बूटियों का फायदा उठाना चाहिये। हमारे मंत्री महोदय कहते हैं कि हम पीछे नहीं जाना चाहते हैं। उनकी यह बात सुनकर मुझे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

[श्री ऊदल]

बड़ा ताज्जुब होता है। आज विज्ञान का युग है यह हम मानते हैं, लेकिन इस युग में भी हम अपनी पुरानी दवाइयों का फायदा उठा सकते हैं। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि आज हमारा ध्यान देहाती दवाइयों की तरफ जाना चाहिये। मैं यह नहीं कहता कि आप इस विज्ञान के युग में आगे न जाकर पीछे जाइये, लेकिन साथ-साथ इसका भी फायदा आपको उठाना चाहिये।

एक बात और यह कि ट्रेजरी बेंचेज की तरफ से एक साहब ने फरमाया कि हमको समाजवादी समाज की बात रोजाना नहीं करनी चाहिये। उन्होंने कहा कि झारखंडे राय जी का जो समाजवाद है उसको सभी जानते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आज आप जिस समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहते हैं उसका मतलब क्या होता है। उसका मतलब यह नहीं होता कि एक तरफ मरीज मर रहा हो और दूसरी तरफ आपके कर्मचारी उसको रिश्वत देने को मजबूर करें। समाजवाद का मतलब यह होता है कि हर आदमी को अच्छी दवा मिले, अच्छा खाना मिले, अच्छा कपड़ा मिले, उसके पढ़ने-लिखने की व्यवस्था अच्छी हो, उसके रहने की उचित व्यवस्था हो, उसको पूरा रोजगार मिले और मैं कहना चाहता हूं कि इसका प्रयोग आज नहीं हो रहा है। महात्मा गांधी जी ने जैसा कहा था उसका प्रयोग आज केरल में हो रहा है। उसके लिये आज आपके महामंत्री परेशान हैं। वहां महात्मा गांधी के कहे अनुसार ही लोग चल रहे हैं। महात्मा गांधी का जो रामराज्य था उसका प्रयोग आज वहां हो रहा है और मैं समझता हूं कि अगर आप लोगों ने अपनी नीति और रंग को नहीं बदला और आप केवल कांग्रेस टिकट पा कर सरकारी तरफ बैठने भर को ही सब कुछ समझते रहे और इस तरह से असलियत पर पर्दा डालने की कोशिश करते रहे तो आज एक केरल है कल सारे देश में केरल ही केरल हो जायंगे और इसलिये मैं अन्त में कहना चाहता हूं कि आप महात्मा गांधी के बताये रास्ते पर चलने की कोशिश करें।

श्री धर्मदत्त वैद्य (जिला बरेली)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। इस सदन में काफी समय से जन स्वास्थ्य और चिकित्सा के अनुदानों पर विवाद चल रहा है। यह नितान्त सत्य है कि इस प्रदेश में स्वास्थ्य और चिकित्सा के सम्बन्ध में काफी प्रगति हुई। पिछले वर्षों में जो कार्य इस प्रदेश में हुआ है उससे हमारे प्रदेश के जिले संक्रामक रोग से बचे रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि इस प्रदेश में देवस्थान और तीर्थस्थानों की कमी नहीं है। उन तीर्थों पर मेलों के अवसर पर जो प्रबन्ध इस विभाग के द्वारा किया गया वह सराहनीय है। मैंने स्वयं हरिद्वार में कुम्भ के मेले पर देखा कि कहीं मक्खी देखने को नहीं थी। जिस प्रकार से हमारे समाज के लिये संक्रामक रोगों से दूर रखने का प्रयास स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग ने किया है सरकार उसके लिये प्रशंसा की पात्र है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में हमने इस ओर काफी प्रगति की है और दूसरी पंचवर्षीय योजना हमारे सामने है। उसके अन्तर्गत हमारे प्रदेश में मेडिकल कालेजों की स्थापना, नये अस्पतालों की स्थापना और क्षय रोग के अस्पतालों की स्थापना की जा रही है और हमारा विश्वास है कि हम शीघ्र ही अपने उस लक्ष्य पर, कि प्रत्येक ५ मील की दूरी पर हमारी चिकित्सा का प्रबन्ध हो और समाज के लोग रोग ग्रस्त होकर न मरें, हम पूरा कर सकेंगे।

किन्तु मान्यवर, मुझे आपके द्वारा सरकार से यह भी निवेदन करना है कि जिस प्रगति के साथ हमारे इस प्रदेश में चिकित्सा को व्यापक बनाने और चिकित्सा का लाभ समाज तक पहुंचाने की जो व्यवस्था की जा रही है उस पर हमें एक दृष्टि डालनी है कि हमारे प्रदेश की जनता की आर्थिक स्थिति क्या ऐसी है कि हम उस पर इतनी महंगी विदेशी चिकित्सा का भार डालें। हम जानते हैं कि रोग और मुकदमेबाजी मनुष्य

के जीवन में ऐसे हैं कि वह कर्ज लेकर भी उसका सामना करता है। हम भूल नहीं सकते कि हमारे प्रदेश में ऐसे साधारण परिवार हैं, जो रोग के समय में उनके घर की महिलाओं के जेवरों को बेंचकर रोगियों की सेवा और चिकित्सा करते हैं। जिस प्रगति के साथ इस चिकित्सा के द्वारा हम अपने लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं, उसमें मुझे इस बात का सन्देह है कि हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति उसके अनुकूल है। मैं यह भी नहीं चाहता कि इस विज्ञान के युग में हम विज्ञान का फायदा न उठायें। मैं इस बात पर विश्वास रखता हूं कि प्रत्येक ऐसा उपाय जिससे समाज का कल्याण हो उसको हमें प्रयोग में लाना चाहिये और इस वैज्ञानिक युग में जो नवीन साधन हों उनका प्रयोग करना चाहिये, किन्तु यदि कोई दूसरा उपाय भी ऐसा हो सकता है कि जिसके द्वारा हम इस कार्य को कर सकते हैं तो हमें उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये। इस देश में स्वतन्त्रता के बाद देश एवं प्रदेश के रहने वाले, बड़ी संख्या में, लोगों को यह आशा थी कि देश की स्वतन्त्रता के बाद जिस प्रकार से हमारे उद्योगों का , विज्ञान का, संस्कृति का उत्थान होगा उसी प्रकार भारतीय चिकित्सा का भी विकास किया जायगा। किन्तु मुझे दुःख है कि प्रदेशीय सरकार प्रयास करने के बाद भी आयुर्वेद की उपेक्षा को न बचा सकी।

पिछले वर्षों में प्रदेश की सरकार ने अनेक ऐसे प्रयास किये। हमने पत्रों में, मीटिंगों में और फाइलों में अनेक प्रकार की योजनाओं को देखा, किन्तु खेद है कि आज तक वे योजनाएं कार्यान्वित नहीं हो सकीं। मुझे कई बार मेडिकल की स्थायी समिति में भी बैठने का अवसर मिला, कितनी ही बार यह विचार सामने आया कि जिला स्तर पर देशी चिकित्सा पद्धति के लिये कोई उपाय किया जाय, क्षय रोग के लिये इस चिकित्सा पद्धति के अनुसार योजनाएं बनीं। लेकिन आज तक वे योजनायें कार्यान्वित नहीं हो सकीं। यहां पर स्टेट आयुर्वेदिक कालेज की स्थापना हुई, लेकिन आज तक भी इस कालेज की स्थिति बड़ी दयनीय है। वहां के कर्मचारियों को अपनी सर्विसेज पर विश्वास नहीं है, उनको आज तक भी स्थायी नहीं किया गया। कालेज अस्पताल में केवल ३६ रोगी शय्याएं हैं। मेडिकल कालेज में एक छात्र की जानकारी और प्रैक्टिकल के लिये १० रोगी शय्याओं का प्रबन्ध है, जब कि आयुर्वेदिक कालेज में ४० विद्यार्थियों के लिये केवल ३६ शय्याओं का ही प्रबन्ध है। हमारे प्रदेश में लगभग ६०० आयुर्वेदिक चिकित्सालय हैं, जो सरकार द्वारा संचालित होते हैं, लेकिन वहां पर न तो चिकित्सालय के लिए स्थान का प्रबन्ध है, न रोगियों के रहने का और न चिकित्सक के आवास का ही प्रबन्ध है। वहां के चिकित्सक ऐसे बीहड़ इलाकों में रहते हैं, जो अन्य शहरों और कस्बों से अलग है, दुर्गम मार्ग है, जंगली इलाके हैं दूसरे चिकित्सक वहां जाने में संकोच करते हैं। किसी-किसी स्थान पर तो छोटी सी कोठरी में ही औषधालय और रहने का स्थान है। इस प्रकार इसकी ओर सरकार की निरन्तर उपेक्षा की दृष्टि रही है।

मैं आपके द्वारा माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन की यह मांग है कि इस पद्धति के उत्थान के लिये पृथक से संचालक की नियुक्ति की जाय। मैं किसी पर आक्षेप नहीं करना चाहता और न किसी की मनोवृत्ति पर सन्देह ही करता हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि अलग-अलग विज्ञान भिन्न-भिन्न चिकित्सा पद्धति हैं। इसलिये दूसरे विज्ञान को न समझने के कारण कार्यों में अक्सर रुकावट होती है। जिला स्तर पर भी इसका प्रबन्ध उत्तम नहीं है, लेकिन आयुर्वेद निरीक्षक को कोई अधिकार नहीं है, उसके पास कार्यालय के लिए न अच्छे मकान हैं और न क्लर्क ही हैं। इस चिकित्सा पद्धति के साथ जो सरकार का व्यवहार है उस पर मुझे बड़ा खेद है। पिछले वर्षों से इस सदन की यह मांग रही है कि भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिये अलग से संचालक की नियुक्ति हो। जनतंत्र प्रणाली का यह तरीका है कि जनता के प्रतिनिधियों की मांग को महत्व दिया जाय। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में माननीय स्वास्थ्य मंत्री

[श्री धर्मदत्त वैद्य]

जो इस ओर अवश्य ध्यान देंगे। इसलिये नहीं कि इस चिकित्सा पद्धति को हम जबर्दस्ती लादना चाहते हैं, परन्तु मेरा तो अब भी यह विश्वास है कि करोड़ों रुपया जो हमारे देश से दवाइयों के नाम पर विदेश जाता है, न सिर्फ इसके द्वारा हम उसको रोक सकेंगे बल्कि जनता को एक सस्ती चिकित्सा भी दे सकेंगे। अगर यह देश इस देशी चिकित्सा विज्ञान का विकास नहीं कर सकता तो सर्वदा आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ ही रहेगा।

श्रीमती विद्यावती बाजपेयी (जिला हरदोई)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्वास्थ्य मंत्री जी को इस बजट पर बधाई देने के लिये खड़ी हुई हूं। इस प्रथम पंचवर्षीय योजना में हमारी सरकार ने इस ओर जो प्रगति की है, वह सराहनीय है। हमारी सरकार ने इस पंचवर्षीय योजना में १४१ नये एलोपैथिक अस्पताल और ५३ देशी अस्पतालों की स्थापना की है और ऐसी उनकी योजना है कि पांच-पांच मील पर एक अस्पताल कायम किया जाय, जिससे हमारे देश का कोई आदमी बिना दवा के न रह सके। उनकी यह योजना काफी सराहनीय है। इस थोड़े से काल में चिकित्सा सम्बन्धी जितनी उन्नति हुई है मेरी राय में वह बहुत भारी उन्नति है और सभी उसको मानने के लिये तैयार होंगे।

शिक्षा की ओर भी काफी प्रगति की गयी है। कई मेडिकल कालेज खोलने की व्यवस्था सरकार ने की है। कानपुर का मेडिकल कालेज तो बन कर तैयार भी हो गया है। अब लखनऊ, कानपुर और आगरा में मिला कर ३०० विद्यार्थी प्रति वर्ष एम० बी० बी० एस० कोर्स के लिये, लिये जायंगे। श्रीमन्, यह एक बहुत बड़ी चीज है। मैं समझती हूं कि इससे हमारे देश में जो डाक्टरों की कमी है वह पूरी होगी, परन्तु एक बात मुझे स्वास्थ्य मंत्री जी से जरूर कहनी है और वह यह कि अभी भी महिला डाक्टरों की संख्या बहुत कम है और उसको बढ़ाया जाय, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में स्त्रियों की संख्या भी पुरुषों की संख्या से ज्यादा ही है और बीमारी भी ज्यादातर स्त्रियों को ही होती है। मैं समझती हूं कि महिला डाक्टरों की संख्या ज्यादा बढ़ानी चाहिये, जिससे ज्यादा महिला डाक्टर तैयार हो सकें। इसके अलावा श्रीमन्, मेडिकल कालेज में बहुत से नये-नये डिपार्टमेंट्स खुले हैं जैसे दन्त चिकित्सा विभाग, वायलाजी डिपार्टमेंट, इस तरह के बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं, जिनसे आज कल जनता को काफी सुविधायें प्राप्त हो रही हैं। ज्यादा नर्सेज और हेल्थ विजिटर्स के लिये भी बहुत से मैटरनिटी सेंटर खोले गये हैं जिनसे काफी ट्रेन्ड दाइयां निकल रही हैं, परन्तु अभी भी वे हमारे देश के लिये बहुत कम हैं और मेरी स्वास्थ्य मंत्री जी से यह प्रार्थना है कि इस ओर और अधिक ध्यान देने की जरूरत है, ताकि ये दाइयां गांवों में जाकर वहां की जनता को अधिक लाभ पहुंचा सकें। मेटरनिटी सेंटर भी गांवों में ज्यादा खोलने चाहिये, क्योंकि शहरों में तो बहुत से अस्पताल हैं और उनके लिये बहुत सी फैसिलिटीज हैं, प्राइवेट डाक्टर्स भी हैं। लेकिन अभी भी देहात की स्त्रियों को बहुत अधिक कष्ट है, क्योंकि वहां ट्रेंड दाइयां नहीं मिलतीं और अस्पताल भी काफी दूरी पर हैं। इसलिये दाइयों को ट्रेंड करके गांवों में भेजने की व्यवस्था मेरी राय में ज्यादा होनी चाहिये।

इसके अलावा मैटर्निटी होम, मलेरिया निरोधक योजनाएं वगैरह की ओर भी हमारी सरकार ने काफी प्रगति की है। क्षय रोग से बचाव के लिये बी० सी० जी० का इन्जेक्शन अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मेरी राय में आज कल प्लेग, हैजा, चेचक की बीमारी पर भी काफी कंट्रोल कर लिया गया है, जिससे हमारे यहां की मत्यु संख्या भी पहले से बहुत कम हो गयी है। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को दूध देने की सरकारी योजना भी बहुत प्रशंसनीय है, परन्तु उससे भी हमारे गांव की गरीब महिलाओं को बहुत कम फायदा पहुंच रहा है, जैसा कि एक मेरी बहन ने कहा था कि गांवों की स्त्रियों को इन चीजों की ज्यादा फेसिलिटीज प्राप्त होनी चाहिये। श्रीमन्,

इसी के साथ-साथ बच्चों के स्वास्थ्य पर भी हमारी सरकार की ओर से काफी ध्यान दिया गया है। लखनऊ के मेडिकल कालेज में वेल बेबी सेन्टर, न्यूट्रीशन क्लीनिक भी खुले हैं, जहां छोटे-छोटे बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाता है और अब वहां पर अधिक से अधिक तादाद में बच्चे आने लगे हैं और अब बहुत सी गरीब माताएं भी अपने बच्चों को लाकर वहां से फायदा उठाती हैं। यूनीकेफ के द्वारा भी हमारे प्रान्त में बहुत काम हुआ है। इससे हमारे यहां की जनता को और हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट को बहुत ज्यादा मदद मिलती है। मैं चाहती हूं कि इन सेटर्स के लिये स्थायी डाक्टरों की नियुक्ति की जाय और उनको एक नियंत्रित रूप से चलाया जाय। इस समय वहां डाक्टर घंटे दो घंटे के लिये जाते हैं और इतने से ज्यादा काम नहीं हो पाता और उनको भी कठिनाई है कि वे थोड़ा ही समय वहां दे पाते हैं। अगर वे स्थायी और नियंत्रित रूप से वहां काम कर सकें तो बहुत लाभ हो सकता है।

इसके अतिरिक्त हमारी सरकार ने फेमिली प्लानिंग की ओर भी थोड़ा सा कदम उठाया है, लेकिन वह अभी काफी नहीं है। हमारे देश में अभी फेमिली प्लानिंग की बहुत सख्त जरूरत है। बड़े-बड़े बोर्ड तो हमें सड़कों के किनारे दिखाई देते हैं, जिनमें लिखा होता है कि फेमिली प्लानिंग अच्छी चीज है, उसमें हिदायतें भी दी हुई हैं और लिखा रहता है कि डाक्टरों की सलाह ली जाय, लेकिन वह डाक्टर कहां मिलेंगे, किस समय मिलेंगे इसका कोई निर्देश उसमें नहीं रहता। मैं समझती हूं कि अगर इन बोर्ड्स के ऊपर क्लीनिक का पता और कन्सल्टेशन का समय भी दे दिया जाया करे तो जनता को काफी लाभ और सुविधा हो सकती है, क्योंकि हमारे देश की जनता बहुत अनभिज्ञ है और अशिक्षित क्या, पढ़े-लिखे आदमियों को भी जब तक पता न हो वे भी क्लीनिक तक नहीं पहुंच सकते।

ऐसा सुना जाता है कि डाक्टर लोग गांवों में या पहाड़ी क्षेत्रों में जाने को तैयार नहीं होते हैं। कारण इसका यह है कि वहां उनके रहने की उचित सुविधा नहीं होती और उनके बच्चों की शिक्षा आदि का कोई उचित प्रबन्ध वहां नहीं होता। मेरा सुझाव है कि ऐसे स्थानों के डाक्टरों को कुछ कन्वेयन्स अलाउन्स या विलेज अलाउन्स दिया जाय तो अच्छा फल हो सकता है, इससे डाक्टरों का उत्साह गांव में जाने के लिये बढ़ेगा और उनकी वहां की तकलीफें कम हो जायंगी और जनता की भी परेशानी घट जायगी।

अन्त में मैं एक विषय पर माननीय मंत्री जी का ध्यान और आकर्षित करूंगी और वह यह है कि हमारे देश में बहुत से ऐसे बच्चे देखने में आते हैं कि जो अपनी मेण्टल और फिजिकल कमजोरी के कारण पढ़ने में असमर्थ होते हैं। ऐसे बच्चों के लिये सरकार को ऐसे सेन्टर्स खोलने चाहिये कि जिनमें इन बच्चों की जांच हो और उनको दस्तकारी या कोई हाथ के काम सिखाये जायं। इस तरह से हम ऐसे बच्चों को अपने माता-पिता के ऊपर जिन्दगी भर भार बने रहने से बचा सकते हैं। ऐसे केन्द्र दिल्ली में भी हैं और मैं आशा करती हूं कि यहां भी इस ओर मंत्री जी विशेष ध्यान देंगे और ऐसे केन्द्र यहां भी खुलवायेंगे। अन्त में मैं अपनी ओर से और जनता की ओर से माननीय मंत्री जी को बधाई देती हूं।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)—उपाध्यक्ष महोदय, जनसाधारण को भोजन, वस्त्र और आवास की सुविधा मिलने के बाद यही चिन्ता पैदा होती है कि उसके वह कष्ट, उस की वह विपदायें जो किसी रोग के कारण उत्पन्न होती हैं, कैसे दूर हों। इसलिये यह जो अनुदान प्रस्तुत किया गया है उसका हमारे जनजीवन से और सर्वसाधारण के जीवन से बड़ा गहरा सम्बन्ध है और इसलिये इन अनुदानों का हर माननीय सदस्य को समर्थन करना चाहिये, लेकिन हमारे सामने रुपयों का प्रश्न नहीं रहता और न इस बात

[श्री भगवतीसिंह विशारद]

का प्रश्न रहता है कि हमने पिछले साल कितना रुपया खर्च किया था और इस साल कितना खर्च करने जा रहे हैं, बल्कि हमारे सामने प्रश्न यह रहता है कि कौन सी वह नीति है जिसको बनाकर हम इस सार्वजनिक धन को व्यय करने जा रहे हैं और उसके साथ-साथ यह भी ध्यान में रखना पड़ता है कि हम जो कुछ पैसा इस अनुदान की मद में खर्च करने जा रहे हैं उसके खर्च करने से क्या हमें उतना ही लाभ प्राप्त होगा ? जब मैं इस कसौटी पर मंत्री जी के अनुदानों को रखता हूं तो मैं अपने को असमर्थ पाता हूं उनके प्रस्ताव का समर्थन करने में और फिर विवश होकर माननीय झारखंडेराय जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करना पड़ता है और समर्थन कर रहा हूं ।

श्रीमन्, हमारे इस प्रदेश में ४ तरह की पद्धतियां हैं, जिनके अनुसार यहां चिकित्सा होती है--आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति , यूनानी, ऐलोपैथी और होम्योपैथी पद्धति। इनमें से दो का सम्बन्ध विदेशों से और दो का सम्बन्ध हमारे देश से है । हमारे देश से जिन पद्धतियों का सम्बन्ध है, आयुर्वेदिक और यूनानी, वे ऐसी हैं जिनके चलाने में हमें किसी तरह का विशेष खर्च करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती । वे हमारे लिये सरल हैं, सस्ती हैं, लेकिन खेद है कि हमारी सरकार का ध्यान इन दोनों पद्धतियों की ओर कम रहता है और विदेशी पद्धतियों की ओर ज्यादा रहता है । आप देखें कि जो ४ करोड़ १५ लाख की मांग की गई है इसमें अपनी देशी पद्धति के लिये सिर्फ २७ लाख रुपये की मांग की गई है और यह मुश्किल से ६ प्रतिशत है । तो मैं चाहता हूं कि इस देश में और खासतौर पर प्रदेश में अपनी देशी पद्धति को उन्नत करने के लिये, उसका प्रचार करने के लिये, विकास के लिये ज्यादा व्यय किया जाय और उसका अच्छी तरह से प्रचार किया जाय, उसके लिये अच्छे कालेजेज खोले जायं, जिनमें विद्यार्थी वैद्य आकर शिक्षा प्राप्त कर सकें और इन चिकित्सा पद्धतियों को और भी ज्यादा विकसित करने में सफलता प्राप्त कर सकें । आवश्यकता इस बात की भी है कि इस तरह के आयुर्वेदिक औषधालय और अधिक खोले जायं ।

श्रीमन्, यहां पर जो प्रोमोशन होता है, उसमें कितना पक्षपात होता है इसके मैं आपके सामने एक-दो उदाहरण रखना चाहता हूं । न तो किसी तरह की योग्यता का खयाल रखा जाता है, न प्रवीणता का खयाल किया जाता है, सीनियारिटी जूनियारिटी का भी ख़याल नहीं रखा जाता । श्रीमन्, एक आदमी बहुत नीचे से ऊपर उठ जाता है और उसका परिणाम यह होता है कि जितने डाक्टर और जितने लोग इस क्षेत्र में हैं उनमें उत्साह नहीं रह जाता है कि वे रुचि से इस क्षेत्र में काम कर सकें । आपके लखनऊ में एक नया तजुर्बा किया गया । एक छोटे सिविल सर्जन साहब हैं वे नुस्खा भी लिखते हैं और डायरेक्टर के दफ्तर में डिप्टी डायरेक्टरी भी करते हैं । यहां पर अजीब तरह का प्रयोग चल रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष---यह बात माननीय सदस्य कह चुके हैं । दोहराने की कोई जरूरत नहीं । श्री रामायणराय जी कह चुके हैं ।

श्री भगवतीसिंह विशारद---श्रीमन्, जरा आप अस्पतालों का हाल देखिये । मैं उन्नाव के अस्पताल का हाल देखता हूं कि उस की स्थिति धर्मशाला से घटिया नहीं है । अस्पतालों में मरीज आते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है और किसी तरह से अगर उनको पर्चा मिल भी गया तो यही मालूम होता है कि जैसे जेल में २६,२८ नम्बर की दवाइयां मिलती हैं, वही इन अस्पतालों में मिल रही हैं । किसी तरह का कोई सुधार नहीं है । आंकड़े दिये जाते हैं कि इतने करोड़ आदमियों ने अस्पताल आकर दवाई ली, लेकिन मेहरबानी करके मंत्री जी ने यह भी आंकड़े दिये होते कि इतने करोड़ आदमियों ने बाहर से दवाई ली और तब उनकी तकलीफ दूर हुई है । तो प्रदेश की जनता को पता चल जाता कि असली

हालत क्या है। अस्पताल से दवाई मिलती नहीं, बाहर से इंजेक्शन लाना पड़ता है और तब कहीं अपने इलाज को दुरुस्त करा पाते हैं। और उसका यश लूटती है यह सरकार कि इतने करोड़ लोगों ने हमारी दवा से फायदा उठाया है। श्रीमन्, लखनऊ मेडिकल कालेज की हालत देखिये, इसमें टी० बी० के मरीज और जिन लोगों की हड्डियां टूटती हैं वह लोग आते हैं। दो-दो तीन-तीन महीने उनको वेटिंग लिस्ट में रहना पड़ता है और जब बेड खाली होते हैं तब उनका इलाज हो पाता है। जरा कल्पना कीजिए कि जो आदमी विकलांग है, जिसको इतना कष्ट हो रहा है, जिसको दर्द है, उसकी हड्डी अगर दूसरी जगह जुड़ गई या कोई दूसरी बीमारी उसको पैदा हो गई तो उसका उत्तरदायित्व किस पर है? डाक्टर पर है, इस सरकार पर है, माननीय मंत्री जी पर है या किस पर है? मैं यह समझता हूं कि यह सब लोग अपनी जिम्मेदारियों से अलग होकर यह कहेंगे कि इसकी जिम्मेदारी भगवान् पर है। ये लोग इसकी जिम्मेदारी भगवान् पर छोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन भगवान् पर जिम्मेदारी छोड़ने से यह लोग अपने उत्तरदायित्व से बरी नहीं हो सकते। मैंयालाजिकल डिपार्टमेंट तथा फार्मेकोलाजिकल डिपार्टमेन्ट के बारे में माननीय रामायणराय जी ने अपने भाषण में बतलाया कि वह डाइरेक्टरेट में आ गया है। खुशी की बात है। जिन डाक्टरों की कृपा से और जिनकी मेहनत से ऐसा हुआ है उनको हमें और भी सुख-सुविधाएं प्रदान करना चाहिये। लेकिन इसी तरह और भी विभागों को उनका अनुकरण करना चाहिए। अन्त में एक बात अपने माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जब हमारे प्रदेश में हैजा फैलता है, महामारी फैलती है, तब वह तपाक से उत्तर देते हैं कि साहब यह बनारस का प्रसाद है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इस प्रदेश में कुछ ऐसे रोग हैं कि जिनका सम्बन्ध वंशपरम्परागत होता है। उन रोगों के फैलाने के केन्द्र खुले हुए हैं। वह वृत्ति जारी है जिसके कारण रोगों की वृद्धि हो रही है। उनको रोकने के लिये यह सरकार क्या कर रही है? आज हम चाहे कुछ नहीं कहें। लेकिन वंशपरम्परागत रोग वह जिन लोगों के बच्चों को लगेंगे वह इस सरकार को और माननीय मंत्री की नीति को, जिसके कारण आज वह रोग फैल रहे हैं, दोषी ठहरायेंगे।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रस्ताव करना चाहता हूं कि इन दोनों अनुदानों पर बोलने वाले बहुत ज्यादा हैं इस वजह से सदन का समय आधा घंटा और बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय मंत्री जी को कोई एतराज है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—हमें तो इसमें कभी ऐतराज न हुआ न है।

श्री उपाध्यक्ष—तो अब हम साढ़े पांच बजे तक बैठेंगे।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में जो चिकित्सा और जनस्वास्थ्य के बारे में अनुदान श्री स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है और उसके लिये जो कटौती का प्रस्ताव श्री झारखंडेराय जी ने प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, किसी भी देश के लिये स्वस्थ मनुष्यों की आवश्यकता होती है। यदि मनुष्य स्वस्थ है तो उसका मस्तिष्क भी स्वस्थ होता है और जब स्वस्थ मस्तिष्क होता है तभी वह ठीक प्रकार से सब कार्य भी कर सकता है। परन्तु यह स्वास्थ्य सम्बन्धी धनराशि जो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत की गई है वह अपने उत्तर प्रदेश की आबादी को देखते हुए बिलकुल ही थोड़ी है। श्रीमन्, कुल ४,१५,२२,७०० रुपया चिकित्सा के लिए और

[श्री भुवनेशभूषण शर्मा]

१, ६७,७६,८०० सौ रुपया का जनस्वास्थ्य के लिए मांगा गया है । जब कि उत्तर प्रदेश की आबादी करीब ७ करोड़ के हैं । तो इतनी थोड़ी धनराशि और इसी में सारी चीजें शामिल हैं । हास्पिटल बनाना, औजार, दवाई अन्यान्य डाक्टरों की तनख्वाह सभी चीजें इसी में शामिल है । तो मेरी समझ में नहीं आया । एक व्यक्ति पर औषधि की दृष्टि से मैं समझता हूं कि ४ आने से ज्यादा एक साल में खर्च नहीं आता ।

फिर उसमें भी देशी औषधियां हैं, उनके लिये बहुत कम धनराशि रक्खी गई है । श्रीमन्, अधिकतर रुपया औषधियों के रूप में विदेशों में चला जाता है । आज हम अपने स्वास्थ्य के लिये विदेशों की कृपा पर निर्भर हैं । यह विचार करने की बात है कि अगर विदेशों से किसी वक्त हमको दवाए न प्राप्त हो सकें तो उस वक्त हमारी क्या हालत होगी । कई बार मौके आये हैं जब पेनिसिलीन के एक-एक इंजेक्शन के लिये जो १ रुपये में आज मिलता ह, २०,२० रुपये देने पड़ते थे और वह भी बड़ी मुश्किल से मिल सकता था । यदि हमारी सरकार भारतीय औषधियों पर अनुसंधान करे और उस पर निर्भर करे तो ज्यादा मुनासिब होगा । जब ये विदेशी औषधियां नहीं थीं तब हमारे देश में यहां की औषधियों से काम होता था । आज एक अस्पताल खोलने व विदेशी दवाइयों को मंगाने में पर्याप्त मात्रा में धन व्यय होता ह, जबकि आयुर्वेदिक औषधालय खोलने में थोड़ा ही धन व्यय होता है । गांव में तो आयुर्वेदिक औषधालय खोलकर देहाती जड़ी बूटियों में ही काम चलाया जा सकता है, लेकिन हमारी सरकार उनको प्रोत्साहन देने में बिलकुल उदासीन है । देशी औषधियों के लिये जो धनराशि इस अनुदान में मांगी गई है उसी से साफ जाहिर हो जाता है ।

दूसरी बात यह है कि मेडिसिन बोर्ड ने वैद्यों को सर्टिफिकेट देने के लिए कोई मापदंड नियुक्त नहीं किया । अक्सर देखा जाता है कि सरकार की ओर से ऐसे सर्टिफिकेट ईश्यू कर दिये जाते हैं, जो असल में वैद्य नहीं होते, कुछ प्रतिष्ठित आदमियों ने हस्ताक्षर कर दिये कि ४-६ साल से फलां साहब इलाज कर रहे हैं और उन्हें वैद्यक का सार्टिफिकेट मिल जाता है । ऐसे वैद्य उल्टा सीधा इलाज करते हैं । यदि सरकार सख्ती बरते तो जो बिला पढ़े लिखे आदमी सर्टिफिकेट पा लेते हैं, जिन्हें वैद्यक का कोई ज्ञान नहीं होता और जो उल्टे सीधे इलाज करते हैं और देहात के लोगों की जानों के साथ खिलवाड़ करते हैं, ऐसे आदमियों को रोका जा सकता है जो गुरुकुल के स्नातक वैद्यक पढ़ कर आते हैं, उनके प्रोत्साहन के लिये सरकार को अधिक जागरूक होना चाहिये ।

श्रीमन्, तीसरी बात मैं टी० बी० के अस्पतालों के बारे में कहना चाहता हूं गिनती के लिये सरकार ने ये अस्पताल खोल दिये हैं, लेकिन टी० बी० के मरीजों की लाइन इन अस्पतालों के दरवाजे पर भरती होने के लिये खड़ी रहती है जब कि अस्पताल में चारपाइयां मरीजों के वास्ते केवल २० या २५ ही होती हैं । उनमें भी स्टूडेन्ट्स, टीचर्स और लेडीज के लिये कुछ रिजर्व रहती हैं और दूसरों के लिये बहुत कम रह जाती हैं जबकि यह मर्ज भारतवर्ष में घर कर गया है । ऐसा कोई गांव न होगा जहां काफी तादाद में टी० बी० के मरीज न हों । मैं मंत्री महोदय को यह सुझाव दूंगा कि अधिक से अधिक टी० बी० के अस्पतालों की ओर उनको ध्यान देना चाहिये । इटावे में टी०बी० अस्पताल कायम किया गया है, जिसमें २८ चारपाइयां हैं, जिनमें १० स्टूडेन्ट्स के लिये रिजर्व हैं, कुछ लेडीज के लिये । इस तरह से ८-१० चारपाइयां रह जाती हैं ।

किसी को भी अगर महीना डेढ़ महीना बुखार आ गया तो वह टी० बी० का मरीज डिक्लेयर हो जाता है और टी० बी० हास्पिटल में नाम लिखाने के बाद भर्ती होने के लिये उसे साल भर तक इन्तजार करना होता है और साल भर बाद भी कभी-कभी नम्बर नहीं आता । जिसको टी० बी० हो गई हो और साल भर तक प्रवेश पाने के लिये इन्तजार करना पड़े तब जा कर कहीं चारपाई मिले । परिणाम यह होता है कि कितने ही आदमी इलाज होने के बजाय भगवान् के यहां पहुंच जाते हैं । सरकार को इधर ध्यान देना चाहिये, क्योंकि

यह छुआछूत की बीमारी है। यह ऐसी बीमारी है कि अगर एक व्यक्ति को हो गई है और उसको अस्पताल में जगह न मिले तो बहुत से लोगों को टी० बी० हो जाती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहूंगा कि सरकार को चाहिये कि टी० बी० के अस्पतालों में ज्यादा बेड्स बढ़ाये। इटावा के टी० बी० हास्पिटल में आपरेशन थियेटर के लिये ८९,००० रुपये मंजूर किये गये थे। उनको वापस लेकर किसी और निर्माण कार्य में लगा दिया गया और वहां आपरेशन थियेटर कायम न हो सका। हर साल कई हजार रुपये के औजार आपरेशन थियेटर के लिये वहां भेजे जाते हैं, जिनको जंग लगती है। इसको भेजने से क्या फायदा है जब कि वहां पर आपरेशन थियेटर नहीं बनाया गया है। इटावा में टी० बी० के अस्पतालों में पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। वहां न कोई कुआं खोदा गया है और न नल है और मरीजों को पानी के लिये आधा फर्लांग जाना पड़ता है। सड़क से अस्पताल जाने के लिये रास्ते में न तो म्युनिसिपैलिटी की ही तरफ से और न सरकार की ही तरफ से रोशनी का कोई इंतजाम है। श्रीमन्, मैं मंत्री जी से आपके द्वारा कहूंगा कि जिन बीमारियों से ज्यादा अहित हो सकता है उन पर ध्यान देने की कृपा करें।

सिविल अस्पतालों में पहले जितनी चारपाइयां थीं उनसे ज्यादा नहीं बढ़ाई गई हैं, जब कि बीमारियां बढ़ गई हैं और मरीज परेशान होते हैं, ऐडमिट नहीं हो पाते हैं, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिये। क्यों कि जब तक आदमी स्वस्थ नहीं रहेगा वह आगे की चीज क्या सोच सकता है, क्या विचार सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, अंत में मैं कहूंगा कि सरकार का जो देशी औषधालयों की तरफ उदासीनता का व्यवहार है, उसको छोड़कर ज्यादा ध्यान दिया जाय, ताकि जो व्यक्ति वैद्यक पास कर के पांच साल बाद आते हैं उनको अधिक स्थान मिल सकें और देश की सेवा हो सके क्योंकि इससे सस्ते में इलाज होता है। देहातों में देशी औषधालय खोले जायं तो लोगों को ज्यादा लाभ होगा।

श्रीमती राजेन्द्र किशोरी (जिला बस्ती)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान इधर दिलाना चाहती हूं कि जिला बस्ती में डुमरियागंज में कोई जनाना अस्पताल नहीं है, जिसके कारण अनेक बहिनों की बच्चा होते समय मृत्यु हो जाती है। इसलिये इस क्षेत्र में जनाना अस्पताल खोले जाने की व्यवस्था की जाय। वहां जो मरदाना अस्पताल है, उसको मैं देखने गई थी। वहां बड़ी गंदगी थी। डाक्टर साहब ने बताया कि पांच साल से इसकी सफाई इत्यादि कुछ भी नहीं हुई है। वहां जो सामान है वह सब डेड स्टाक का है। मरीजों को आराम पहुंचाने के वहां कोई साधन नहीं हैं और मरीजों को बड़ा कष्ट होता है। डाक्टर साहब ने यह बताया कि मैंने रिपोर्ट की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। मैं प्रार्थना करूंगी कि इसकी ओर ध्यान देने की कृपा करें। यह तराई का इलाका है, इसलिये यहां अनेक बीमारियां होती हैं। वहां कोढ़ की बीमारी बहुत ज्यादा फैलती जा रही है। इसलिये इस विषय में भी समुचित व्यवस्था होनी चाहिये।

एक अस्पताल इस पार है और उस पार कोई नहीं है, जिससे हमारी बहिनों को बड़ी तकलीफ है। स्त्रियों की तरफ जरा ध्यान देने की कृपा मंत्री जी करें। पुरुषों की तरफ तो बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है, लेकिन बहिनों की तरफ नहीं दिया जाता है। मैं अपने टूटे फूटे अल्फाज में कहती हूं। हमारी बहिनें जब बोलने के लिये यहां खड़ी होती हैं तो बहुत से हमारे भाई ऐसे हैं जो उस पर मजाक उड़ाते हैं, हंसी उड़ाते हैं। मैं उन भाइयों से यह पूछना चाहती हूं कि या आप सदन में आते ही आते सब चीजें सीख

[श्रीमती राजेन्द्र किशोरी]

गये थे । हर चीज के लिये आदमी का अनुभव होता है । सीखते ही सीखते सीखता है । इसीलिये हम लोगों को आग बढ़ाया गया है । आप लोग अपनी जरूरतों को तो सदन में रखते हैं, लेकिन बहनों की जरूरतों को जब तक बहनें नहीं कहेंगी, तब तक आपको कैसे मालूम होगा । इसलिये मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगी कि जिस ओर अभी हमारी एक बहन ने उनका ध्यान दिलाया है उस ओर वे ध्यान देंगे और जनाने अस्पताल के विषय में जरूर ख्याल करेंगे और डुमरियागंज के अस्पताल की व्यवस्था को खासतौर से देखेंगे । मैं तो यही कहूंगी कि उस अस्पताल का जितना सामान है वह सब डेड स्टाक है और डाक्टर के लिये मैं क्या कहूं, मरीज जाते हैं लेकिन वे कोई तवज्जह नहीं देते फलतः साल में कम से कम ५-६ औरतों की मृत्यु होती है । इसका कारण यह है कि बस्ती से ३१ मील की दूरी पर डुमरियागंज है जहां पर आने जाने के कोई साधन नहीं हैं । इस पार वाली औरतें तो मरदाने अस्पताल में जाकर इलाज करा भी सकती हैं । लेकिन उस पार वालों के लिये कोई साधन नहीं है । जिस वक्त बच्चे के होने में दर्द होती है, आप स्वयं सोचिये कि उस वक्त ३१ मील किस तरह से कोई आ सकता है । इसलिये मंत्री जी से पुनः प्रार्थना है कि जरा हमारे कष्टों की ओर भी ध्यान दें ।

श्री गोविन्द सहाय (जिला बिजनौर)---उपाध्यक्ष महोदय, जो अनुदान आज सदन के सामने पेश है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मेरा ऐसा विश्वास है कि इस विभाग के मंत्री बड़े सौभाग्यशाली आदमी हैं कि जिन्हें जानवरों और आदमियों, दोनों के स्वास्थ्य को ठीक रखने की जिम्मेदारी सौंपी गयी है और इसलिये ऐसे काम में सब को सहयोग देना चाहिये । जहां तक रुपये का ताल्लुक है अगर इससे ज्यादा रुपया भी वे मांगते तो उसको देने के लिये सदन को गुरेज नहीं होना चाहिये था । सवाल सिर्फ इस बात का है कि जो रुपया दिया जाता है उसका ठीक इस्तेमाल और एलोकेशन किस तरीके से हो ।

मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता जो इस सदन में काफी कही गयी हैं । मोटे तरीके पर मेरा ख्याल है कि सरकार इस रुपये को दो भागों में बांट दे, एक प्रिवेन्टिव और दूसरा इलाज करने के सिलसिले में । जो रुपया बीमारियों को रोकने में, इंसानों की सेहत को ठीक रखने में खर्च किया जायगा उसका नतीजा ज्यादा प्रोडक्टिव होता है, बनिस्बत उसके जो रुपया बीमारियों का इलाज करने में खर्च होता है । और उसके लिये मेरा सुझाव है कि आज हमारे देश में लोगों को अपने स्वास्थ्य के बारे में, डायटिक्स के बारे में बहुत कम जानकारी है कि क्या खाना चाहिये । पढ़े लिखे लोगों तक का खाने के बारे में यह ख्याल है कि अगर वे शाम को पराठे और पूरी खाते हैं तो वे हल्का खाना खाते हैं । खोंचा खाना, चाट, पकौड़ी खाना, यह समझा जाता है कि सेहत के लिये मूजिर नहीं है । जब डायटिक्स का ज्ञान लोगों को नहीं है तो हमारे डिपार्टमेन्ट का यह काम होना चाहिये कि वह बताये कि सौ रुपये वालोंके लिये क्या खाना होना चाहिये, दो सौ रुपये पाने वालों के लिय क्या खाना होना चाहिये । एक ऐसी स्टैंडर्डाइज्ड डायट हो कि थोड़ी आमदनी के अन्दर भी अगर वह खाना लोग खायें तो अच्छी हो । इसी तरीके से सेहत की तरक्की के लिये जरूरत है एक्सरसाइजेज की । लोगों के दांत साफ रहें । कोई कैम्पेन आज हमारे देश में हेल्थ कांशस बनाने का नहीं है । महज अस्पताल खोलने से किसी सोसायटी की सेहत ठीक नहीं हुआ करती । सेहत ठीक हुआ करती है जब उसका हर इंसान अपने जिस्म के बारे में जाने कि क्या उसे खाना चाहिये, कैसे मशीन को ठीक रखना चाहिये, उसे इसका ज्ञान हो । इसके बारे में मैं इतना कह सकता हूं कि आज गांवों के लोगों के अन्दर दतून करने की बात भी हटती जा रही है । दांतों की सफाई वगैरह के बारे में स्कूलों में और दूसरी जगह कोई आंदोलन नहीं है ।

तो हेल्थ कांशेंस बनाने का जो काम है, जिस के बारे में जानकारी कराना कि कैसे उसको ठीक रखा जाय, हमारी मशीन कैसे बनी है, यह प्रोग्राम भी इस डिपार्टमेंट का होना चाहिये । अगर आधा रुपया भी इस काम पर खर्च किया जाय तो बहुत ज्यादा यूजफुल एक्सपेंडीचर होगा ऐसा मैं समझता हूं ।

खेलों के बारे में, मेरा ऐसा विश्वास है कि स्कूलों में और कालेजेज में और सोसाइटी के लोगों में आसन asans की एक्सरसाइजेज को पापुलराइज किया जाय तो बहुत लाभ होगा, क्योंकि आसन बहुत साइंटिफिक एक्सरसाइजेज हैं और इसमें कोई पैसा भी नहीं खर्च होता, वह नर्वस सिस्टम को भी ठीक करते हैं और ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करता है। उसे मास स्केल पर पापुलराइज करना चाहिये और यह काम इस डिपार्टमेंट की तरफ से होना चाहिये ।

दूसरी बात जो मुझे कहनी है वह यह है कि ज्यादा तर रुपया जो खर्च होता है वह एक खास किस्म की प्रणाली पर खर्च होता है और वह प्रणाली एलोपैथिक प्रणाली कहलाती है। एलोपैथिक प्रणाली के लोगों का ख्याल है और ईमानदाराना ख्याल है कि वह बहुत अच्छी है और अगर सदन में एलोपैथिक प्रणाली के डाक्टर्स सदस्य होते तो वह कहते कि आयुर्वेदिक सिस्टम बेकार है, अनसाइंटिफिक है और उस पर पैसा खर्च करना बेकार है। गो कि मैं डाक्टर इस माने में नहीं हूं, मेडिसिन का डाक्टर नहीं हूं, मगर सोसाइटी का डाक्टर हर पब्लिकमैन को होने की ख्वाहिश होनी चाहिये, उस हैसियत से कहता हूं कि एलोपैथिक सिस्टम जो है वह बहुत अनसाइंटिफिक है। मैं एक बहुत ऐसा स्टेटमेंट आज कर रहा हूं, जिसमें डाक्टर्स बिलबिला सकते हैं और यह समझकर कर रहा हूं कि थोड़ा बहुत साइंस को समझता हूं । जिस्म के बारे में थोड़ा बहुत समझता हूं । जैसा कि एक लैमेन डाक्टर होता है उस तरह से कहता हूं कि एलोपैथिक परिपाटी बहुत अनसाइंटिफिक है और उसमें इन डाक्टर्स का कसूर नहीं है। इन पिछले सौ सालों में जितनी सोशल साइंसेज पैदा हुई हैं वे एकांगी हैं, जीवन ऐज ए होल (as a whole) के बारे में उनका ऐप्रोच नहीं होता । जैसे एकनामिक यानी अर्थशास्त्र की साइंस है। वह यह तो कहती है कि गरीबी है, मगर यह नहीं बताती कि गरीबी क्यों है। इसी तरह से एलोपैथिक यह तो बताता है कि दर्द है, लेकिन दर्द क्यों है उसके काजेज में वह नहीं जाती। इसीलिये मैं इसको अनसाइंटिफिक कहता हूं। एक तो यह खर्चीली भी बहुत है। एक खास किस्म का ताम-झाम इसके लिये इकट्ठा करना पड़ता है । यह जरूर सच है कि इस इलाज से अधिक इसके औजारों का असर होता है। एक आला होता है उसको इधर लगाते हैं, उधर लगाते हैं, लोग समझते हैं कि बड़ा इलाज हो रहा है, लेकिन मैं काफी तजुर्बे के साथ कह सकता हूं कि बड़े जितने डाक्टर्स हैं, जितने बड़े एक्सपर्ट्स हैं, इनके पल्ले अगर आप पड़ जायं तो पता चल जाय कि कितना साइंटिफिक ट्रीटमेंट है। डेन्टिस्ट है। उसका एक ही इलाज है। आप अपना दांत दिखाइये। दांतों को थोड़ी देर देखने के बाद कहेगा कि आपके दांतों को निकालना चाहिये। डेन्टिस्ट दांत निकालने की बात कहेगा। आपरेशन सर्जन के पास चले जाइये, वह उस चीज का आपरेशन करने की कहेगा। यह उनका एक तरीका सा हो गया है । तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप खुद भी उनसे बचिये और सोसाइटी को भी बचाइए। इनको कोई बेसिक अंडरस्टैंडिंग लोगों के रोगों के बारें मे नहीं होती। मुझे खुद कुछ बातों का तजुर्बा है।

इसके अतिरिक्त आप देखिये कि जितने अस्पताल खुलते जा रहे हैं, इंजेक्शन्स बढ़ते जाते हैं, उतनी ही लोगों में रोगों से लड़ने की ताकत रेजिस्टेंस की पावर कमी होती जाती है, लोगों में रोगों से लड़ने की ताक़त बढ़नी चाहिये ।

इस समय मैं दूसरे सिस्टम्स की बहस में नहीं पड़ना चाहता लेकिन इतना जरूर खयाल है कि जहां सरकार ने लाखों रुपया खर्च किया है एलोपैथिक पर और-और प्रणालियों पर वहां कुछ थोड़ा सा रिसर्च नेचुरलोपैथी पर भी कर डालिये। वह सब से कम खर्चे की चीज है। उसका कहना है कि "डिजीजेज आर इनडिवीजिबिल" उसको न काटा जा सकता है और न

[श्री गोविन्द सहाय]

तोड़ा जा सकता है। एक जगह पर सिस्टम खराब होता है तो उसके सारे सिस्टम में बीमारियां पैदा होती हैं। आप इस नेचुरलोपैथी को गांव-गांव में पहुंचा सकते हैं। नेचुरलोपैथी को डाए-टिक्स के साथ, प्रिवेंटिव ट्रीटमेन्ट के साथ और आसन एक्सरसाइजेज के साथ तथा फिजिकल फिटनेस के साथ-साथ चलाया जा सकता है। इन तमाम चीजों को अगर आप मिला कर करेंगे तो मेरा खयाल है कि पैसे का ज्यादा अच्छा इस्तेमाल होगा और कम पैसे से लोगों को अच्छा इलाज मिल सकेगा।

एक मिनट में एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं। यह सही है कि शिफाखाने बहुत हैं, अगर मैं यह कहूं कि उनमें दवाइयों की कुछ गड़बड़ है तो मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे आनरेबिल मिनिस्टर साहब जो काफी कुशल हैं, वह हम सब को मुतमईन कर देंगे कि ऐसा नहीं है। लेकिन मैं एक बात बहुत अदब के साथ कहना चाहूंगा...

श्री हुकुम सिंह विसेन--कुछ गड़बड़ जरूर है।

श्री गोविन्द सहाय--बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरा दूसरा सुझाव यह है कि जब कभी मेम्बर्स आफ दि गवर्नमेंट वहां अस्पतालों में विजिट किया करें तो बजाय नोटिस दे कर जाने के वह बिना नोटिस दिये जाया करें। इस तरह से विजिट करने से जो एक सवाल समाजवादी समाज की स्थापना का यहां बार-बार उठाया जाता है, उसकी कुछ झलक उनको अवश्य देखने को मिलेगी। उसका एक मयार होता है और वह यह कि आया गरीब को, जिसकी कोई सिफारिश नहीं है उसको दवा मिल जाती है या नहीं। अगर किसी गरीब पर बिना किसी सिफारिश के ध्यान दिया जाता है अस्पतालों में तो हम कहें या न कहें, यह मानना पड़ेगा कि हम सोशलिज्म की तरफ जा रहे हैं। अगर हम अपनी विजीलेंस को बढ़ा दें तो यह हो सकता है। अपने जिले की बात मैं कह सकता हूं। मेरी दावत है मिनिस्टर साहब को। उन्हें वहां के अस्पतालों से कुछ नाउम्मीदी होगी। हमारे यहां का एडमिनिस्ट्रेशन भी इस तरह का हो गया है कि कुछ कहा नहीं जाता। एक डाक्टर तबादला हो कर जाता है और दूसरा आ कर पांच छः दिन पड़ा रहता है, फिर उसका तबादला कैंसिल हो जाता है। इस तरह की बातों से मैं समझता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन की एफीशियेन्सी खराब होती है, आपकी भी शान कम होती है और लोगों में बुरा असर पड़ता है। इसलिये मेरी आनरेबिल मिनिस्टर साहब को दावत है कि वे एक बार जिला बिजनौर आयें। यह कहा जा सकता है कि वहां और मिनिस्टर भी जाने वाले हैं, लेकिन उनके बावजूद भी चूंकि मामला कब्जे में नहीं आया है, इसलिये मैं दावत देता हूं इस तरह की और आशा करता हूं कि सरकार ऐसा करके विजीलेंस बढ़ायेगी।

श्री उदय शंकर दुबे (जिला बस्ती)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप का बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे यह अवसर दिया कि इस ग्रान्ट की मदों पर मैं अपनी राय जाहिर कर सकूं।

इधर पिछले १० सालों में जो चिकित्सा की मद में और जन-स्वास्थ्य की मद में धन खर्च हुआ है वह लगभग तिगुने के बढ़ गया है और इससे इस सूबे में चिकित्सा की और अस्पतालों आदि की काफी उन्नति हुई है, जिसके लिये यह सूबा सरकार का आभारी है। परन्तु केवल मदों में पैसा डाल देने से ही कुछ विशेष काम नहीं होता है। जो चीज देखने की है वह यह कि रुपये का सदुपयोग होता है ठीक-ठीक अथवा नहीं। मुझे अफसोस है कि बावजूद हमारे मंत्रियों की तमाम अक्लमन्दी और मेहनत के भी रुपये का पूरा-पूरा सदुपयोग नहीं हो पाता है और जो साधारण जनता है उसको जो लाभ मिलना चाहिये वह न मिल कर वह लाभ कुछ थोड़े से उन लोगों को ही मिल पाता है कि जो खुशकिस्मती से कुछ अच्छी पोजीशन में हैं। इस सिल-सिले में मेरा पहला एतराज तो यह है कि जो आयुर्वेद सिस्टम है वह एक नेशनल सिस्टम आफ मेडिसिन डिक्लेयर होना चाहिये। जो एक पुस्तिका अभी सरकार की ओर से बांटी गयी है उसमें

बजाय इसके कि आयुर्वेद को नेशनल सिस्टम माना जाय उसे एलोपैथी पूरक सिस्टम आफ मेडिसिन माना गया है। मैं यह अर्ज करूंगा कि इसकी दलील में जाने का यह अवसर नहीं है, लेकिन मैं समझता हुं कि यह आयुर्वेद के साथ और देश की पुरानी दवा की पद्धति के प्रति एक बहुत बड़ा अन्याय है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इसके ऊपर पूरा ध्यान देंगे और इसकी उन्नति की ओर विशेष ध्यान देकर आयुर्वेद को नेशनल सिस्टम आफ मेडिसिन बनाने की पूरी कोशिश करेंगे।

दूसरी चीज मुझे यह अर्ज करनी है कि इस डिपार्टमेंट में जो स्वास्थ्य का है उसमें बहुत ओवरलैपिंग है। अभी गवर्नमेंट ने तय किया है कि हम ५५ वर्ष से ५८ वर्ष तक सुपरऐनुयेशन को रक्खेंगे, लेकिन जब इस डिपार्टमेंट की तरफ हम देखते हैं तो देशी चिकित्सा के डिप्टी डाइरेक्टर महोदय हैं वह ५८ के बाद भी चल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष--आप किसी व्यक्ति विशेष के प्रति यहां पर बहस नहीं कर सकते।

श्री उदय शंकर दुबे--मैं एक डिपार्टमेंट की बात कह रहा हूं कि गवर्नमेंट की पालिसी होते हुए भी गवर्नमेंट इस तरफ देखती नहीं है कि जो एक पालिसी बन गयी उसको पूरी तरीके से अमल में ले आवे।

तीसरी चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि आप के जो असिस्टेंट डाइरेक्टर मैटरनिटी हैं। उनका जो स्थान है, मैं सजेस्ट करूंगा कि मिड वाइफ़ हेल्थविज़िटर जो उनके यहां रखी गयी हैं इनके दोनों स्थानों को एक स्थान कर देना चाहिये। एक आदमी इन दोनों कामों को अच्छी तरह से चला सकता है और ट्रान्सफर वगैरह का जो काम है उसको भी कर सकता है। उनके यहां एक गजटेड असिस्टेंट है वह लेडी डाक्टर है और जो आपका यहां पर हेल्थ स्कूल हैं उसमें भी इन्चार्ज एक लेडी डाक्टर है। वह लेक्चरार है। इन दोनों के लिये पूरा काम नहीं है। यह काम एक आदमी से हो सकता है। तो मैं अर्ज करूंगा कि यह जो ओवर-लैपिंग है उससे पैसा अधिक खर्च होता है। जो पैसा अच्छे काम लग सकता है वह बजाय इसके कि इसमें लगाया जाय कुछ जगहें बनाकर उनके कामों को देखने के लिये खर्च किया जाता है।

आपके नर्सिंग स्कूल हैं। वे इस सूबे में १२ हैं। कहीं ४, ५ लड़कियां हैं और कहीं मुश्किल से लड़कियां आती हैं। अगर उनको जाकर देखा जाय तो मालूम हो कि उनकी क्या पोज़ीशन है। यह भी बहस की जाती है कि लड़कियां घरों से बाहर दूर नहीं जाना चाहती हैं। इसलिये उनकी अलग-अलग जगहें बनाना पड़ता है। मैंने देखा है कि नैनीताल के नर्सिंग स्कूल में लड़कियां यहां प्लेन्स से भेजी जाती है...

श्री हुकुमसिंह विसेन--नैनीताल में प्लेन्स से कितनी लड़कियां भेजी गई हैं?

श्री उदय शंकर दुबे--वहां के स्कूल में प्लेन्स की लड़कियां हैं, ठीक तादाद में तो मैं इस समय नहीं बता सकता हूं। बजाय इसके कि आप २० जगह स्कूल खोलें और स्टाफ बढ़ाते जावें, यह बेहतर होगा कि एक या दो जगह में कनसंट्रेट कीजिये और वहां प्रशिक्षण का काम कीजिये। अगर आप को पढ़ने वालों की तादाद काफी मिलती है तो आप चाहे जितने स्कूल खोल दें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन छोटी-छोटी जगहों पर बिला वजह स्कूल खोल कर पैसा बरबाद नहीं होना चाहिये।

एक बात यह है कि मुझे ऐसा मालूम होता है कि सरविसेज़ हमारी मिनिस्ट्री पर चढ़ी हुई हैं, न कि मिनिस्ट्री सरविसेज़ के ऊपर। यह गवर्नमेंट के सारे डिपार्टमेण्ट्स के लिये लागू है। मेरी गुजारिश है कि वह अपनी सरविसेज़ पर ग्रिप ज़रा कड़ा रखें। उनकी लियाक़त और मेहनत में हमें कोई शिकायत नहीं है। लेकिन जाने या अनजाने उन्होंने सरविसेज़ को यह एलाउ कर दिया है कि उनके सामने मूक से रहते हैं।

श्री रघुरनतेजबहादुर सिंह (जिला गोंडा)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, देहातों में अस्पताल खोलने के लिये हमारी सरकार बिलकुल उदासीन है और जो कुछ बजट में रखा है वह महासागर में एक बिन्दु के समान है। मेडिकल कालेज ज्यादातर शहरों में ही खोले जाते हैं। डाक्टर लोग देहातों में जाने के लिये तैयार नहीं होते हैं। उनके ऊपर कुछ ऐसी मजबूरी होनी चाहिये कि वे देहात में जावें। जो कोई देहात में चला भी जाता है वह थोड़े दिन बाद फिर शहर में कोशिश कर के आ जाता है। शहरों में एक अस्पताल खोलने में लाखों रुपया खर्च किया जाता है, जिसमें देहातों में कितने ही छोटे-छोटे अस्पताल खोले जा सकते हैं। देहात के लोगों को शहरों के अस्पतालों में घुसने नहीं दिया जाता है। वहां पर एक पब्लिक शिकायत की किताब होनी चाहिये, जिसमें नान-आफ़ीशल्स या पब्लिक के लोग नोट कर सकें। इससे भ्रष्टाचार और देहाती लोगों की ओर कम ध्यान देने वालों के ऊपर रोकथाम हो सकेगी। अव्वल तो देहात के लोग शहरों में इलाज के लिये पहुंच ही नहीं पाते हैं और अगर जाते भी हैं तो उनके साथ जाने वाले संबंधियों के लिये कोई ठहरने के लिये शेड आदि का कोई प्रबन्ध नहीं है। ज्यादातर उनको इनडोर पेशेण्ट रखने का मौक़ा ही नहीं आता है, तो उनके साथियों के लिये क्या कहा जाय।

इस किताब में गोंडा जिले का नक्शा जरा आप देखें कि इसके लिये कितने कम अस्पताल हैं। परगना बूढ़ापार में कोई अस्पताल नहीं है--न यूनानी, न एलोपैथी और न किसी दूसरी तरह का है। बरसात में रास्ते बन्द होने के कारण वहां के लोग शहर में भी नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिये जहां मीन्स आफ कम्यूनिकेशन्स इतने पुअर हैं वहां सरकारी अस्पताल होना चाहिये। बड़े-बड़े शहरों में या सड़क के किनारे जो व्यय होता है उसका आंशिक रूप भी देहातों में नहीं खर्च होता। राजस्व का ६० प्रतिशत ग्रामीण जनता से आता है मगर उनके ऊपर बहुत कम खर्च होता है। जितने मेडिकल कालेज खोले गये वे पश्चिमी जिलों में खोले जा रहे हैं। पूर्वी जिले बाढ़ग्रस्त हैं और वहां की जनता रोगों से ज्यादा पीड़ित रहती है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह रूरल मेडिकल कालेज पूरब में खोले, जिससे वहां की जनता को लखनऊ जैसे मंहगें शहरों में न जाना पड़े। अगर देहात में कालेज होंगे तो डाक्टरों को शहरों के सिनेमा या तफरीह की जगहों की आदत नहीं रहेगी और वे देहात में रहना पसन्द करने लगेंगे।

हमारे यहां कोई मैटरनिटी सेण्टर नहीं है। मैं तो कहूंगा कि समस्त उतरौला तहसील में ही शायद एक या दो ही होंगे। एक अस्पताल सादुल्लानगर में है, जिसमें भी मैटरनिटी का कोई इन्तजाम नहीं है। स्त्रियों की दशा वहां शोचनीय है। अभी गत वर्ष एक अच्छे परिवार की जिसे तमाम साधन भी उपलब्ध थे, जच्चा और बच्चा दोनों मर गये। उनको ठीक मेडिकल सहायता नहीं मिल सकी। ग़रीब जनता बैलगाड़ियों और डोलियों में अपने मरीजों को शहरों में नहीं ले जा सकती हैं। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि मेरे क्षेत्र में मैटरनिटी सेण्टर होना चाहिये। सादुल्लानगर में एक सरकारी अस्पताल है, जो बहुत पुराना है। उसके अन्दर सर्जरी का कोई विशेष प्रबन्ध नहीं है। वहां पर एक आपरेशन थियेटर की जरूरत है, चाहे वह छोटा ही हो। दो, चार हजार रुपये में यह काम हो सकता है, ताकि उस क्षेत्र के लोग जो वहां से २५ ५० मील के फासले पर जाते हैं वहां जा सकें और इमरजेंसी केसेज को भी वहां पर ट्रीट किया जा सके।

श्रीमन्, मैं एक बात और अर्ज कर देना चाहता हूं कि इन क्षेत्रों में मोबाइल डिस्पेंसरियों का भी प्रबन्ध कर दिया जाय तो संक्रामक रोगों के इलाज के सिलसिले में उनसे बहुत मदद मिल सकती है और उनसे ग्रामीण जनता का बहुत भला हो सकता है। यह जो शहर और देहात का कम्पटीशन है और सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो शीघ्र ही वह एक उग्र क्रान्ति का रूप धारण कर लेगा। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस ओर ध्यान देंगे और उन ८५ प्रतिशत लोगों का, जो देहात में हैं, कोई प्रबन्ध अवश्य करेंगे।

श्री रामकुमार वैद्य (जिला मुरादाबाद)--आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन के सामने जो चिकित्सा और जनस्वास्थ्य का अनुदान है और उस पर माननीय झारखंडे राय जी का जो कटौती का प्रस्ताव है मैं उसका अनुमोदन करता हूं। श्रीमन्, जब से इस सदन में आज बहस शुरू हुई है मैंने यह अनुभव किया कि सब के सब सदस्य प्रायः इस संबंध में एक-मत हैं कि चिकित्सा का अनुदान बढ़ाया जाना चाहिये। कुछ भाइयों ने किसी विशिष्ट औषधालय की मांग की, किसी ने आपरेशन थियेटर की मांग की और किसी बहन ने महिला चिकित्सा के साधनों को बढ़ाने की मांग की किन्तु श्रीमन्, मैं यह न समझ सका कि यदि इस बजट के सारे साधनों का भी प्रयोग किया जाय तो किस प्रकार से उन सारी मांगों को पूरा किया जा सकता है। लेकिन हो सकता था यदि हमारी सरकार की नीति इस संबंध में जागरूकता की रही होती, कुछ स्वदेश के प्रति भक्ति से ओतप्रोत वे रहे होते। श्रीमन्, पूज्य गांधी जी ने, जिनके अनुकरण करने का सरकार बराबर दावा करती रहती है, कहा था कि एक उन्नत राष्ट्र का जो अत्यन्त विपन्न अवस्था में हो, यह कर्त्तव्य है कि वह अपने साधनों का अधिक से अधिक उपयोग करे।

हमारी सरकार के जो भी कार्य हैं, वे सब पंचवर्षीय योजनाओं के अधीन चल रहे हैं, लेकिन आयोजन का क्या अर्थ है? आयोजन का अर्थ है कि देश के सामूहिक साधनों का जो भी वे हों, जो भी हमें उपलब्ध हों, चाहे वे बहुत हों, चाहे थोड़े हों, जैसे भी हों, उनका इस प्रकार आयोजन किया जाय, इस प्रकार प्रयोग किया जाय जिससे देश की जनता का अधिक से अधिक भला हो। मैं नहीं समझता कि इस चिकित्सा संबंधी अनुदान में अपना लक्ष्य विदेशी औषधियों के इस्तेमाल से पा सकते हैं, जिसमें कि बहुत कुछ खर्च करने के बाद बहुत थोड़ा ही हमें मिल पाता है। मैं समझता हूं कि हमारे मंत्री महोदय और इससे पूर्व हमारे भूतपूर्व मंत्री महोदय ने बार-बार यह घोषणा की थी कि आयुर्वेद को हम फिर से वही पुराना गौरव देने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, जो आयुर्वेद संबंधी अनुदान इस वर्ष मंजूरी के लिये सदन में आया है और जो गतवर्ष इस सदन के सामने आया था, उनमें किसी प्रकार से इसका एक भी उदाहरण हमें न मिल सकेगा। हमारे प्रान्त में बहुविज्ञप्ति और सालों साल प्रचार करने के पश्चात् स्टेट आयुर्वेदिक कालेज की स्थापना की गयी थी, लेकिन आपको यह जानकर दुःख होगा कि उस कालेज की स्थिति आज तक डांवाडोल है। यह भी आज नहीं कहा जा सकता कि वह कालेज रहेगा भी या समाप्त हो जायगा। कालेज में जितने प्राध्यापक और वहां के मुख्याध्यापक हैं उनको आज तक इस बात का कोई एश्योरेंस नहीं दिया गया है कि उनकी सर्विस स्थायी है या अस्थायी है।

आपको यह जानकर और भी आश्चर्य होगा कि हमारा आयुर्वेदिक विभाग केवल एक ही पद के अधीन काम कर रहा है। डिप्टी डाइरेक्टर का एक महत्वपूर्ण पद है लेकिन इसके विपरीत इनको सेक्रेटरी के अधीन काम करना पड़ता है और उनको जनता का सम्पूर्ण दायित्व निर्वाहन करना पड़ता है। जिला स्तर पर जहां-जहां आयुर्वेद के इंस्पेक्टर नियुक्त किये गये हैं, उनको जिले के अधिकारी जो डी० एम० ओ० एच० होते हैं उनके अधीन कर दिया गया है। उनको कार्य करने की सुविधा नहीं है। एक तरफ तो आयुर्वेद की तरक्की करने की बात है, दूसरी तरफ साधनों की कमी है, भवनों की कमी है, औषधियों की कमी है। फिर मैं नहीं जानता कि सरकार आयुर्वेद के सम्बन्ध में जो कार्य कर रही है वह क्या है। इसके साथ-साथ श्रीमन्, मैं यह भी चाहता हूं कि आयुर्वेदिक फार्मेसी की स्थापना भी की जानी चाहिये। अगर हमारी सरकार आयुर्वेदिक फार्मेसी की स्थापना करे और बढ़ावे तो हमारा बहुत सा धन जो विदेशी दवाइयों के लिये बाहर चला जाता है वह न जाये। लेकिन सरकार ने अभी तक इस तरफ भी कोई कदम नहीं उठाया है।

[श्री रामकुमार वैद्य]

इसके अलावा श्रीमन्, एक ही विभाग चिकित्सा के अन्दर इसको भी रखा गया है। आयुर्वेदिक, यूनानी, होमियोपैथिक, एलोपैथिक, जितनी भी पद्धतियां हैं, उनमें एक कंट्रोवर्सी है। हर प्रकार से स्तर-स्तर पर, स्थल-स्थल पर आयुर्वेद के सम्बन्ध में रुकावटें डालने की चेष्टा की जाती है। इसलिये माननीय मंत्री जी अपनी स्थिति को स्पष्ट करें और यदि ऐसा समझा जाय कि आयुर्वेद वास्तव में हमारे प्रान्त की जनता के लिये आवश्यक नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है कि आयुर्वेद पर एक पैसा भी खर्च किया जाय, लेकिन श्रीमन्, जो चिकित्सा पद्धति सात हजार वर्षों से, जब कि एलोपैथिक तथा और पद्धतियों का पता तक भी नहीं था, मानव समाज की सेवा कर रही है उसको एक दम से तिरस्कृत कर देना आसान नहीं है। मैं समझता हूं कि ऐसा करना राष्ट्र, समाज व सबके साथ विश्वासघात होगा। मुझे आशा है कि मेरे इन शब्दों पर माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ध्यान देंगे और अभी तक आयुर्वेद के सम्बन्ध में जो गलतफहमी व गड़बड़ी है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—(श्री प्रताप सिंह से) आप के लिये ५ मिनट का समय है।

श्री प्रतापसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे ५ मिनट का समय तो दिया। जो कटौती का प्रस्ताव पेश है, उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। इस सदन में बहस करते हुये बहुत सी बातें कही गयीं, लेकिन बजट को देखने से पता चला कि जिन लोगों के स्वास्थ्य के विषय में हम बातें कर रहे हैं उनकी औसत उम्र हमारे प्रदेश में क्या है, उस पर माननीय मंत्री जी ने कहीं भी प्रकाश नहीं डाला। गवर्नमेंट की पिछले १० साल की जो रिपोर्ट है उसमें भी कहीं आयु नहीं दी गयी है। पंचवर्षीय योजना में एक जगह ३२ साल लिखा है। दूसरे मुल्कों जैसे अमेरिका, इंगलैंड आदि में औसत आयु ५९ और ५५ है। सामान्यतः देहातों में अधिक डिस्पेंसरीज डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की हैं जहां मेडिसिन के लिये सन् १९३९ के अनुसार ही, अनुदान दिया जाता है। सन् ३९ के अनुसार अनुदान देना न्यायसंगत नहीं है, जब कि मंहगाई छैः गुनी बढ़ चुकी है।

दूसरे कई बीमारियों का हवाला यहां दिया गया लेकिन गेस्ट्रोइन्टाइटीज जो इस समय की खास बीमारी है उसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया है। कुछ जिलों के सरकारी आंकड़े उसके मेरे पास हैं जो यह हैं कि मिर्जापुर में १४७, प्रतापगढ़ में १५४, रायबरेली में २५०, सुल्तानपुर में १२५, बनारस में २२२, फैजाबाद ९४, गाजीपुर १७०, जौनपुर ४९२, देवरिया ५६ और बांदा में ३१५। इस लिये इस ओर मंत्री जी विशेष ध्यान दें। इसके अतिरिक्त आपके द्वारा मैं माननीय मंत्री जी की तवज्जह एक तरफ और दिलाना चाहता हूं कि हमें यह सोचना चाहिये कि हमारे देश और प्रदेश के लोगों का स्वास्थ्य क्यों गिर रहा है। मेरे पास समय बहुत कम है, मैं आपको बंगाल फ़ेमिन कमीशन रिपोर्ट पेश करके बताना चाहता हूं कि मंत्री जी इसको सुनें कि " life is held by a slender thread which the least untoward circumstance is sufficient to snap." एक डाक्टर १८७० में हुआ है उसने बताया है कि मनुष्य का जीवन एक डोरी में लटका हुआ है, अगर उसको अनुकूल वातावरण नहीं मिला तो जिन्दगी नहीं रह सकती। दूसरे उन्होंने बताया है कि फेमीन क्षेत्र में बीमारी फैलने का कारण है कि " a famine-stricken population is a siek population. Famine means not only lack of food in the quantitative sense but also lack of essential food constituents which are needed for bodily health". यानी यह जरूरी नहीं है कि भरपेट खाना मिले और घास, पत्तियां या मोटा अनाज खाकर पेट भर लिया जाय, बल्कि यह जरूरी है कि हमारा स्वास्थ्य खाने के बाद ऐसा हो कि जिससे हम आने वाली सन्तानों को स्वस्थ जीवन और जिन्दगी प्रदान कर सकें। चिकित्सा के विषय में बहुत सी बातें कही गईं लेकिन जो हमारे प्रिवेण्टिव मेजर्स हैं उनकी ओर कम ध्यान

दिया जाता है । हमारी जिन्दगी के लिये साफ हवा और साफ पानी बहुत जरूरी है । हमारे यहां के ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिये । हमारे यहां १ लाख ६० हजार गांव हैं और उनमें पीने के पानी के कुयें केवल २० लाख हैं । मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या कभी इन २० लाख कुओं में लाल दवा भी डलवाने का प्रबन्ध मंत्री जी ने किया है ?

श्री मदनगोपाल वैद्य (जिला फैजाबाद)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव मंत्री जी ने पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूं । इस विभाग ने जिस तरह से नाना रूपों में जनता की सेवा की है उससे यह विभाग सदा ही लोक कल्याणकारी साबित हुआ है । हमारा वैद्य समाज हर मेले में चाहे वह कुम्भ का मेला हो या अयोध्या का मेला हो, जनता की सेवा करता है और इस इंफ्लुएंजा के जमाने में भी स्टेट आयुर्वेदिक कालेज की ओर से जो प्रबन्ध चिकित्सा का हुआ है वह सफल तथा लोकप्रिय रहा है । मैं कहना चाहता हूं कि जितनी चिकित्सा पद्धतियां आजकल चल रही हैं उनमें आयुर्वेद के उत्थान के लिये केवल हिन्दुस्तान ही जिम्मेदार है, एलोपैथिक और होम्योपैथिक का विकास तो दूसरे सभी देशों में होता है और सब जगह उन की उन्नति हो सकती है, लेकिन आयुर्वेद के लिये केवल भारत जिम्मेदार है । इसलिये हमें विशेष रूप से इस ओर अपना ध्यान आकर्षित करना चाहिये ।

एक बात की ओर मैं अपने थोड़े समय में मंत्री जी का तथा सदन का ध्यान दिलाऊंगा कि केन्द्रीय सरकार की ओर से जो कमेटी नियुक्त हुई थी उसकी सिफारिश है कि जितनी भी चिकित्सा पद्धतियां हैं सबको समान सुविधायें यहां मिलनी चाहियें, लेकिन इस सम्बन्ध में हमारी पुरानी शिकायत रही है और यह शिकायत अब काफी बढ़ भी गई है कि वह सुविधायें आयुर्वेदिक पद्धति वालों को नहीं मिलतीं । हमारे कानून में कुछ सुविधाएं ऐसी हैं जिन पर सरकार का एक पैसा भी व्यय नहीं होता, वह सुविधायें तक हमें नहीं मिलतीं । जिन पर पैसा व्यय होता है उनकी बात तो दूसरी है । जिन पर सरकार का पैसा व्यय नहीं होता वह ऐसी है कि जैसे कोई वैद्य चाहे कि वह किसी ५१ रुपया पाने वाले सरकारी कर्मचारी को फिटनेस सर्टिफिकेट दे दे तो वह नहीं दे सकता, नियमों में उसके लिये यह सुविधा नहीं है । उसके पास योग्यता है, लेकिन वह ऐसा कर नहीं सकता । इसमें सरकार का कौन सा पैसा व्यय होता है ? तो जब इतना प्रोत्साहन इस चिकित्सा पद्धति को नहीं है तो कोई क्यों चाहगा इसको पढ़ना, जबकि वह ५१ रु० वेतन पाने वाले को प्रमाण-पत्र भी न दे सके। इस तरह की बहुत सी प्रीविलेजेज हैं जो उनको नहीं दी गई हैं ।

अब स्कोप की जहां तक बात है हम देखते हैं कि यहां पर और लोगों के वेतन बढ़ाये जा रहे हैं । जिनकी तनख्वाह एक हजार से ऊपर है उनकी तनख्वाह बढ़ गई, लेकिन आयुर्वेदिक विभाग में दो वर्ष से काम कर रहे हैं एक सज्जन, यू० पी० सरकार के ही कर्मचारी हैं, पहले ६५० रु० पा रहे थे, लेकिन जब लखनऊ में बुलाये गये तो उनको ५०० रु० दिया जा रहा है और अभी तक डायरेक्टर साहब तय नहीं कर पा रहे हैं कि इनको भी कुछ प्रोत्साहन दिया जाय । आयुर्वेद विभाग में काम करना ही क्या पाप है ? इस तरह से जलील किया जाता है । इसी तरीके से और भी प्रीविलेजेज की बातें हैं हम आशा करते हैं कि मंत्री जी समान प्रीविलेजेज देने की बात करेंगे। चिकित्सा विभाग का शासन डायरेक्टर महोदय करते हैं, उसी में आयुर्वेद विभाग भी शामिल है, लेकिन हमने जब भी प्रीविलेजेज के बारे में लिखा, जो इस विभाग के और लोगों को मिलती है तो आज तक उसका कोई निर्णय नहीं हुआ । हमने कई बार लिखा लेकिन कोई निश्चय नहीं हुआ । इस सदन में कई बार ऐसा कहा गया कि आयुर्वेद विभाग के सम्बन्ध में डिप्टी डायरेक्टर आयुर्वेद को पूर्ण अधिकार हैं, परन्तु यह व्यवहार में नहीं आता। सारे कागजात डायरेक्टर के पास जाते हैं और लटके रहते हैं । हम साधारणतया मानते हैं कि सरकार इसकी उन्नति चाहती है, लेकिन यहां लखनऊ में दो वर्ष पहले मेडिकल कांफ्रेंस हुई आल इंडिया की और उसके प्रेसिडेंट ने कहा कि हम

[श्री मदन गोपाल वैद्य]

इस सिस्टम की प्रगति नहीं होने देना चाहते, देहात में डिस्पेंसरी नहीं खोलनी चाहिये और इसी आशय का प्रस्ताव इंडियन मेडिकल एसोशियेशन ने पास किया है। उसका रिजोल्यूशन है कि आयुर्वेदिक संस्थाओं, होम्योपैथिक संस्थाओं, यूनानी संस्थाओं के अन्दर डाक्टरों को सहयोग नहीं करना चाहिये। उन्होंने यह भी कहा है कि जो प्राइवेट प्रेक्टिस करने वाले वैद्य, हकीम हैं उनके साथ उनको सहयोग नहीं करना चाहिये।

श्रीमती चन्द्रावती (जिला बिजनौर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी समय ५ मिनट होगा।

श्री उपाध्यक्ष—विधान के अनुसार स्त्री और पुरुष बराबर हैं, इसलिये मैं मजबूर हूं। आपका भी ५ मिनट समय रहेगा।

*श्रीमती चन्द्रावती—मैं आपकी आभारी हूं कि सुबह की उठक बैठक के बाद अब समय मिला। यहां पर बहुत से भाइयों ने अच्छे-अच्छे सुझाव भी दिये हैं और यदि स्वास्थ्य मंत्री जी उन पर ध्यान देंगे तो इस विभाग के कार्य के संचालन में काफी मदद मिलेगी। जो प्रस्तावित अनुदान है उसका समर्थन हृदय से करती हूं, लेकिन उनके सामने एक बात को रखना पसन्द करूंगी। आज का स्वास्थ्य विभाग और अंग्रेजी के जमाने का स्वास्थ्य विभाग में, इसमें कहने में संकोच नहीं, कोई परिवर्तन नहीं किया गया। स्वतंत्रता के बाद चाहिये तो यह था कि अपने देश की समस्याओं को समझ कर ही विभाग के कार्य को चलाया जाता। इसमें स्वास्थ्य विभाग ही नहीं और विभाग भी शामिल हो सकते हैं। आज हमारे सामने रुपया देना हाउस में एक प्रथा सी हो गई है, किन्तु इस पर दृष्टिपात करना विभाग के कर्मचारी और मंत्री महोदय अपना फर्ज नहीं समझते कि जो रुपया यहां से ग्रान्ट हो कर जाता है उसका कितना भाग जनता के सदुपयोग के लिये आता है। यहां पर एक सुझाव मैं आपके सामने तथा माननीय मंत्री जी के समक्ष रखना चाहूंगी।

हमारे जो चिकित्सा और जन-स्वास्थ्य विभाग हैं यह एक दूसरे से बहुत सम्बन्धित हैं। चिकित्सा की प्रणाली हमेशा उस देश के रहने वालों के अनुकूल होनी चाहिए। हमारे देश में इसकी आबोहवा और रहन सहन को देखते हुए देशी चिकित्सा की प्रणाली अपनायी जानी चाहिये। आज की एलोपैथिक प्रणाली को अगर एलोपैथिक प्रणाली न कह कर इंजेक्शन वाली प्रणाली कहें तो कोई अत्युक्ति न होगी। इस इंजेक्शन प्रणाली से एक तरफ अगर थोड़ी देर के लिये रोग में आराम पहुंचता है तो दूसरी तरफ हम यह भूल जाते हैं कि दूसरे न जाने कितने रोग उस इंजेक्शन से उस मनुष्य के शरीर में पहुंच जाते हैं।

मैं इस पर अधिक न कह कर जो मेरी बहनों द्वारा एक और समस्या उठाई गई और कुछ भाइयों ने भी महिला चिकित्सालय के बारे में अपने विचार प्रकट किये, उसके बारे में मैं माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करती हूं कि वे जरा अपनी जनसंख्या की ओर दृष्टिपात करें। आपके प्रदेश के नर और नारी का स्वास्थ्य एक स्त्रियों के ऊपर निर्भर है। वह यदि अच्छी सन्तान उत्पन्न करेंगी, उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा तो अच्छी सन्तान द्वारा बहुत सी आपकी समस्या का हल हो जाती है।

दूसरी चीज मैं यह कहना चाहती हूं कि जैसा कि अभी हमारे एक भाई ने सुझाव दिया कि एक तो प्रिवेंटिव चेक होना चाहिये और दूसरा पाजिटिव चेक भी होना चाहिये। इसमें मैं फेमिली प्लानिंग को अधिक उपयोगी समझती हूं। आप इसकी तरफ बिलकुल उदासीन हो रहे हैं और आपकी जन संख्या के जो आंकड़े १९६१ में आयेंगे उसके लिए अभी से सोच कर कोई उपाय नहीं किया जा रहा है। फेमिली प्लानिंग की ओर अगर आपने सुचारु रूप से ध्यान दिया तो बहुत सी स्वास्थ्य सम्बन्धी आपकी समस्याएं बिना बहुत सा रुपया पैसा खर्च किये ही

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हल हो जायेंगी। इसके लिए आप यदि देहात में अच्छा प्रचार करवायें तो अधिक लाभ हो सकता है। जब बच्चा देहात में पैदा होता है और थाने में उसकी रिपोर्ट लिखाई जाती है तो यदि थाने द्वारा वह रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग में भेजे और स्वास्थ्य विभाग अपने यहां के यूनिट में जो अस्पताल वहां के लिए आता हो उस अस्पताल से अपने लोगों को उस बहन के पास भेजे कि वह जाकर देखे कि कितने उस फेमिली में बच्चे हैं और कितने अपने नियोजन के मातहत और बच्चे पैदा करना उसके लिए आवश्यक है, उसके लिए उचित उपाय करे, इस तरह से अगर इस ओर ध्यान दिया जाय तो बहुत लाभ हो सकता है। इस ओर अगर ज्यादा ध्यान दिया जाय और उनके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखा जाय जैसा कि हमारी सरकार ने छः लाख रुपया गर्भवती स्त्रियों के लिए दिया है, अगर इस रुपये से दूध उन्हें पिला कर अच्छा स्वास्थ्य उनका डेलीवरी के समय रखा जाय तो बहुत सी समस्या आपकी यहीं से हल हो जाती है।

श्री उपाध्यक्ष--आपका समय समाप्त हो गया।

आज दो माननीया सदस्याओं ने फेमिली प्लानिंग के बारे में कहा। माननीय मन्त्री जी पर चाहे उसका असर न पड़ा हो, लेकिन मुझ पर उसका असर जरूर पड़ा।

श्रीमती सज्जनदेवी महनोत (जिला वाराणसी)--मेरे पहले बहुत सी बहनों ने माननीय मन्त्री जी का ध्यान महिलाओं की तरफ दिलाया है और मैं भी इस अनुदान के लिये उनको बधाई देती हुई अपनी महिलाओं की तरफ से ध्यान दिलाने के लिए खड़ी हुई हूं। देहातों में डिस्पेंसरीज खोली गई हैं। यह सराहनीय बात है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन वहां दाइयों और मिडवाइफों की व्यवस्था नहीं है। तो मैंने जनरल विवाद में भी इस ओर माननीय मन्त्री जी का ध्यान दिलाया था और आज फिर उनका ध्यान उन अनट्रेंड दाइयों की तरफ दिलाना चाहती हूं। जो गंदे औजारों से नाल काटती हैं, उनके लिये ट्रेनिंग की व्यवस्था करनी चाहिये तीन महीने की और उनको कैंची व टिंचर आयडीन का इस्तेमाल सिखाया जाय तो नवजात शिशुओं को मरने से बचाया जा सकता है। मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि मिडवाइफ ट्रेनिंग सेंटर्स और बढ़ाये जायं, क्योंकि मिडवाइव्ज हमको मिलती नहीं। शहरों की तरफ की हमारी बहिनों की ओर पहले भी ध्यान दिया गया है और वे सेंटर्स शहरों में तो अधिक हैं, लेकिन देहातों में भी ट्रेनिंग सेंटर्स बनाने की व्यवस्था की जाय। देहातों में ट्रेनिंग की व्यवस्था जरूर है, लेकिन बहुत कम है।

आयुर्वेद पद्धति से जो हमारी बहिनें काम सीखी हुई हों उनको प्रमाणित किया जाय। आयुर्वेद पद्धति से सीखी हुई बहनें नर्सेज बनना चाहें या मिडवाइव्ज बनना चाहें तो उनको मौका दिया जाय और उनको मान्यता प्रदान की जाय। यह मैं मानती हूं कि एलोपैथिक डाक्टरों ने साइंस में बहुत तरक्की की है, इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं। हमारे आयुर्वेद ने इतनी उन्नति साइंस में नहीं की है। इसके लिये हमारी सरकार की तरफ से एक आयुर्वेद अनुसंधानशाला खोली जाय, जिसमें आयुर्वेद पद्धति की दवाइयों का अनुसंधान किया जाय। इससे हमारे देश का काफी पैसा बच सकता है।

हमारे यहां वाराणसी के जो अर्जुन और दर्शनआयुर्वेद विद्यालय ट्रेनिंग का काम करते हैं और प्रिन्स होम्योपेथ कालेज होम्योपैथीक ट्रेनिंग देता है, उनको सरकार ने मान्यता तो दे रक्खी है, लेकिन वहां से निकले हुए स्नातकों को कहीं काम नहीं मिलता। सरकार को अपनी डिस्पेंसरीज में आयुर्वेद व होम्योपैथी पद्धति भी खोलनी चाहिये, ताकि सस्ती से सस्ती दवा हमारे प्रान्त के गरीबों को मिल सके और गरीब बहिनों को मरने से बचाया जा सके।

श्री झारखंडेराय--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन का बहुत आभारी हूं। इस सदन में पिछले ५ वर्ष में ऐसे बहुत कम मौके आये हैं जब एक राय से कटौती के प्रस्ताव में

[श्री झारखंडे राय]

व्यक्त किये गये विचारों और भावों को समर्थन प्राप्त हुआ हो। चाहे माननीय सदस्य इधर के हों या उधर के सबने कटौती के प्रस्ताव के मूल भाव का समर्थन किया और सबने इसे माना कि सरकार की चिकित्सा सम्बन्धी नीति राष्ट्रीय पद्धति पर अवलम्बित नहीं है और आयुर्वेद को हमारी चिकित्सा पद्धति का मूल आधार मान लेना चाहिये।

अब मैं दो एक आजमगढ़ जिले की स्थानीय समस्याओं की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आजमगढ़ जिले में एक तहसील के सदर मुकाम पर घोसी में एक अस्पताल है जिसकी ख्याति काफी बढ़ रही है। वह अस्पताल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के हाथ में है। मैं चाहूंगा कि सरकार उसका प्रान्तीयकरण जितनी जल्दी कर सके उतना ही अच्छा है।

दोहरीघाट एक दूसरा स्थान है जो गोरखपुर आजमगढ़ के सरहद पर घाघरा नदी के किनारे बसा हुआ है और फिर घाघरा पर पुल भी बनने वाला है, जिससे कि उसका महत्व और भी बढ़ जायगा। फिर रेलवे के विस्तार की भी स्कीम चल रही है तो फिर जब वहां अस्पताल बनाने का निर्णय हो चुका है तो अनावश्यक विलम्ब नहीं होना चाहिये।

तीसरा स्थान अमिला है। वहां के लिये भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्री माननीय गुप्ता जी को दो साल पहले दरख्वास्त भी दी जा चुकी है, वहां के निवासियों द्वारा आवाज भी उठाई जा चुकी है कि वहां ७ मील के अन्दर कोई अस्पताल नहीं है और वह एक केन्द्रीय स्थान है। मैं चाहूंगा कि वहां पर एक अस्पताल की स्थापना सरकार की ओर से फौरन होनी चाहिये। उसके लिये जमीन भी प्राप्त की जा चुकी है, अन्य आवश्यक कार्य भी हो चुके हैं, जिससे सरकार को काफी सहायता प्राप्त होगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो तीन बातों की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैं माननीय मंत्री जी से एक बात जानना चाहूंगा कि यहीं सरकार की आंख के सामने तीन अस्पताल हैं। एक छुतहा अस्पताल, दूसरा बलरामपुर और तीसरा मेडिकल कालेज। क्या वजह है कि छुतहा अस्पताल में बड़ी गंदगी रहती है और रोगियों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं होता है? बलरामपुर अस्पताल में आदमियों के साथ मानवोचित व्यवहार होता है और गरीबों के साथ भी मानवोचित व्यवहार होता है। मेडिकल कालेज में टी० बी० वार्ड में जहां अच्छे व्यवहार की ज्यादा जरूरत है वहां एक आतंक का राज्य दिखाई पड़ता है। मैंने स्वयं वहां जाकर अनुभव किया है। १९३८ में जेल में पहली बार जाकर जो आतंक का भाव वहां मुझे महसूस होता था वही आतंक टी० बी० वार्ड में हर रोगी महसूस करता है। टी० बी० वार्ड में जो सरकारी नौकर हैं, अधिकारी हैं, वार्ड ब्याव और चपरासी आदि हैं उन सबका व्यवहार रोगियों के साथ ऐसा ही होता है जैसा कि पुराने जमाने में वार्डर जेलखाने में साहब के सामने पेशी कराते वक्त कैदी से करते थे। मैं चाहता हूं कि टी० बी० वार्ड में जो आजकल आतंक का राज्य है वह खत्म होना चाहिये। जब सरकार की ओर से लाखों रुपया मेडिकल कालेज के लिये सदन से मंजूर किये जाते हैं तो मैं चाहूंगा कि सदन की एक कमेटी बनाई जाय जो वहां के संबंध में जांच करे और अपने सुझाव दे जिससे ठोस आधार पर सुधार किये जा सकें।

श्री उपाध्यक्ष—आपका समय समाप्त हो गया।

श्री हुकुमसिंह विसेन—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कत्ल इसके कि मैं तमाम अपने मित्रों की बातों के संबंध में कुछ कहूं मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूं कि मैं अपने मित्र श्री झारखंडे राय तथा अपने अन्य साथियों के प्रति जिन्होंने इस ग्रान्ट के संबंध में अपने विचार प्रगट किये हैं, अपना आभार प्रगट करूं। लोगों ने बड़ी सावधानी और ऐतदाल के साथ अपनी बात कही।

अब सब से पहले मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यहां पर आयुर्वेदिक, यूनानी, ऐलोपैथी और होम्योपैथी के संबंध में बहुत बातें कही गईं, लेकिन जहां तक राज्य सरकार की नीति का संबंध है, स्पष्ट है कि हम आयुर्वेदिक और होम्योपैथी सबको प्रोत्साहन देना चाहते हैं और तरक्की करना चाहते हैं, इसका विकास देखना चाहते हैं और उस स्थिति पर हम इसको देखना चाहते हैं कि यह ऐलोपैथी का मुकाबला कर सके। ऐसी हमारी सरकार की नीति है। लेकिन मैं इसको पूरा करने के लिये बहुत होशियारी के साथ कदम उठाना चाहता हूं, इस्तकलाल के साथ कदम आगे रखना चाहता हूं, ताकि हमारा कोई कदम गलत न हो और गलत कदम उठाने में अड़चन और रुकावट हो सकती है। मैंने आयुर्वेदिक कालेज खोला, नियुक्तियां भी कीं। कुछ माननीय सदस्यों ने संकेत के तौर पर बतलाया कि प्रिंसिपल को स्थायी क्यों नहीं किया गया। मैं उस समय तक नहीं करूंगा जब तक मैं यह जांच न लूं कि फलां शख्स इस काबिल है। गलत आदमी को मुस्तकिल बनाने से संस्था को धक्का पहुंच सकता है। हम प्रतीक्षा करेंगे और जब हमको इत्मीनान हो जायगा कि फलां आदमी इस योग्य है कि प्रिन्सिपल के पद पर स्थायीरूप से रखा जा सकता है तो बिला किसी की सिफारिश और कहने के हम फौरन ऐसा करेंगे। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे आयुर्वेदिक कालेज का काम जिस तरह से मैं चाहता हूं उस तरह से नहीं चल रहा है। हम तो चाहते हैं कि इस पद्धति की तरक्की जिस ढंग से सरकार और यहां के रहने वाले चाहते हैं वैसी हो। मैं गाफिल नहीं हूं। हालांकि मुझे सिर्फ दो महीने का अर्सा हुआ इस विभाग का चार्ज लिये हुये, लेकिन इतने वक्त में मैंने कुछ जानकारी हासिल करने की कोशिश की है और जहां-जहां पानी भर रहा है उस तरफ मेरी नजर गयी है और मैं उस स्रोत को बन्द करना चाहता हूं, ताकि हमारा विभाग ठीक से चले।

हमारे मित्र उदयशंकर जी ने कहा कि सर्विसेज मिनिस्ट्री से ऊपर है, मिनिस्ट्री सर्विसेज से ऊपर नहीं है। यह बात सर्वथा गलत है। वे खुद इस बात के शाहिद हैं और शाहिद होते हुये वाकयात को दबा कर उन्होंने ऐसी बात कही है जिसके लिये मुझे अफसोस है। ५-६ रोज का अर्सा हुआ, उन्होंने खुद मुझसे बताया कि बस्ती के अस्पताल में एक गरीब आदमी का बच्चा आया, लेकिन उसका ऐडमिशन नहीं हुआ और दवा नहीं पहुंची और बच्चा अस्पताल के कम्पाउन्ड में मर गया। मैंने फौरन डायरेक्टर आफ़ मेडिकल ऐंड हेल्थ सर्विसेज को फोन पर बुलाया, आर्डर नहीं लिखा, क्योंकि उसमें देर लगती और ताकीद की कि वे फौरन नेक्स्ट ट्रेन से बस्ती जायं और खुफिया तरीके से जायं और रिक्शे पर बैठ कर अस्पताल जायं। चुनान्चे ऐसा हुआ और उन्होंने वाकयात को सही पाया और लौट कर रिपोर्ट किया। मैंने सिविल सर्जन का फौरन टेलीग्रैफ़िक तबादला किया और तीन डाक्टरों को मुअत्तल किया। तो क्या इसके यह माने हैं कि सर्विसेज मिनिस्ट्री के ऊपर हैं? ऐसा हरगिज नहीं हैं। वे खुद इस बात के शाहिद हैं। उन्होंने ऐसी गलत बात कही, इसके लिये मुझे अफसोस है।

मेरे मित्र रघुरनतेज बहादुर जी ने फरमाया कि देहात की तरफ दवा दारू के बारे में सरकार का कोई इन्तजाम नहीं है, उसकी तरफ तवज्जह भी नहीं, नजर भी नहीं और गोंडा जिला बिल्कुल उपेक्षित है। ४० अस्पताल गोंडा जिले में हैं--कर्नेलगंज, मनकापुर, तुलसीपुर, इंटिया थोक वगैरह वगैरह में और हमारे मित्र के गांव में भी एक अस्पताल है, लेकिन वे कहते हैं कि सरकार की कोई तवज्जह ही नहीं है। अब गांवों के बारे में सुनिये। सन् १९४७ में कुल ५९ एलोपैथिक अस्पताल रूरल एरियाज में थे, लेकिन इस वक्त ४६३ एलोपैथिक हैं और ५७७ आयुर्वेदिक और यूनानी कुल १०४०। क्या यह फ़ीगर इस बात का सबूत देती है कि देहात की तरफ इस सरकार की तवज्जह नहीं है? अगर रात को रात कहा जाय तो असर पड़ सकता है, लेकिन अगर रात को दिन कहा जाय तो उसका असर विपरीत पड़ता है।

[श्री हुकुम सिंह विसेन]

जहां तक बूढ़ापार का संबंध है, पहले वहां की नियोजन समिति से रेकमेंड कराइये। जबतक उनका रेकमेंडेशन नहीं होगा तबतक नियम के मुताबिक हम विचार नहीं कर सकते। लिहाजा पहले मेरे मित्र अपना फर्ज पूरा करें और उसके बाद जब मेरी जिम्मेदारी आयेगी तो मैं उसे पूरा करने की कोशिश करूंगा। हमारे मित्र उदयशंकर ने हमें किफायतशारी का सबक पढ़ाया और कहा कि सिल्वर जुबली हेल्थ स्कूल की जो लेडी डाक्टर हैं उनके सुपुर्द वह सेवा कर दी जाय और असिस्टेंट डाइरेक्टर की पोस्ट तोड़ दी जाय। मैं क्या बताऊं कि वह लेडी डाक्टर नहीं हैं, वह नान-डाक्टर हैं। वह सर्विस अलग है और यह सर्विस अलग है। वह एक टेक्नीकल सर्विस है। अगर मैं उनकी सलाह मान लूं और एक अनाड़ी के हाथ में तलवार दे दूं तो वह बजाय अपना गला काटने के दूसरों का गला काट दें और हमारा भी गला काट दें। तो ऐसी गलती तो मैं नहीं कर सकता। उन्होंने बेसमझे बूझे राय दे दी है और अगर उन्होंने ऐसी राय दी है तो मैं मजबूर हूं कि उनकी राय न मानूं और मुझे उम्मीद है कि मेरे मित्र उसका बुरा भी नहीं मानेंगे।

अब मेरे मित्र, झारखंडेराय जी ने बड़ी माकूलियत से काम लिया। मैंने पहले ही कहा है कि मैं उनका बड़ा मशकूर हूं। मैं उनका दोस्त हूं और वे मेरे दोस्त भी हैं। आखिर में दो तीन मामलात जाती जो उन्होंने बतलाये हैं उन पर भी विचार करूंगा यदि हमारे पर्स ने इजाजत दी, लेकिन एक ही साल में एक जिले में तीन अस्पताल खोल दें, इसमें जरा दिक्कत सी मालूम होती है।

श्री झारखंडेराय--एक तो मंजूर हो चुका है।

श्री हुकुमसिंह विसेन--तो ठीक है दूसरे के लिये इंतजार कीजिये। अगर हमारे पर्स ने इजाजत दी तो हम आपके अमिला गांव में भी पहुंचेंगे जहां उनका घर है और जो दो जगहें हैं उनपर भी विचार किया जायगा। हमारे मित्र ने फरमाया था कि इंतजाम में बहुत गड़बड़ी है। मैं कभी दावा नहीं करता कि हमारा इंतजाम बिलकुल परफेक्ट है, लेकिन इतना दावा तो कर ही सकता हूं कि इस विभाग ने इंडिपेंडेंस के बाद काफी तरक्की की है और काफी विस्तार उसका हुआ है। मैं सदन के सदस्यों का समय आंकड़े देकर नहीं लेना चाहता गोकि इतनी फाइलें मेरे पास मौजूद हैं, जिनमें आंकड़े ही भरे हुये हैं, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि विकास हुआ है और होता है। मुझे एक बात की खुशी है कि यहां आज दोनों ग्रांटों पर दिन भर वादविवाद हुआ है और जितनी खुशी इस बात से हुई है, इतना संतोष हुआ है कि उतना संतोष और किसी खास बात से नहीं हुआ और न हो सकता है। इतना जबरदस्त एपीडेमिक इन्फ्लुएंजा और कालरा का हुआ हमारे सूबे में यह हमारे सभी मित्रों ने देखा, लेकिन शुक्रिया है कि किसी ने इस बात का संकेत नहीं किया कि इस विभाग की तरफ से कोई कोताही हुई। अगर कोई कोताही हुई होती तो मैं बख्शा न जाता, मुझे यकीन कामिल है और यही इस बात की दलील है और ऐसी अकाट्य दलील है कि हमारे मित्रों ने अपनी खामोशी से इस बात की दाद दी है कि इस विभाग ने अच्छा काम किया है।

श्री भगवती सिंह विशारद--यह बनारस का प्रसाद है।

श्री हुकुमसिंह विसेन--जहां भी आप जायेंगे प्रसाद तो मिलेगा ही। लेकिन बद्दुआ देने से काम नहीं चलता है जैसी आपने बद्दुआ दी कि यह सरकार मिट जायगी, लेकिन इससे काम नहीं चलता। देखिये व्यावहारिक ढंग से। हेल्थ हमारी आपकी दुरुस्त नहीं हो सकती जब तक कि जैसा हमारे भाई गोबिन्द सहाय जी ने कहा, हम अपने आदत को न सम्हालें। हमें कचालू खाने की आदत है, हमें चाट खाने की आदत है, अमीनुद्दौला पार्क में बूढे, बच्चे। एम० एल० ए० सभी चाट खाते हैं....

एक सदस्य--मिनिस्टर भी खाते हैं।

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां, मिनिस्टर भी खाते हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं खाई। हम मुस्तसना नहीं कर पाये अपने को उन खराब आदतों से। तो जब तक हम सफाई माइन्डेड नहीं होंगे तब तक दवा दारू से इसका इन्तजाम नहीं हो सकता। मैं तो कहना चाहता हूं कि इस लखनऊ शहर में १,८०० या २,००० मेहतर हैं। चार लाख आबादी अगर गन्दगी करने के लिये तैयार है तो २,००० मेहतर सफाई नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। हम भले ही कितनी कोशिश करें, हेल्थ आफिसर कितनी ही कोशिश करें, कितना ही सर के बल खड़े हो जायं, हम चाहे कुछ करें, यह काम हो नहीं सकता। आप अपने दिलों पर हाथ रखें, देखें, घरों का कूड़ा निकाल कर बाहर फेंक देते हैं, लेकिन उस स्थान तक जाने के लिये नहीं तैयार हैं कि जो कूड़े के लिये बना हुआ है। तो जो हमारी आदत हैं उसके रहने से इस तरह की बीमारियां फैलेंगी। हम तो उन बीमारियों को फैलने से रोकने की कोशिश करेंगे ही। जब हमने सिनेमा बन्द करने की बात कही, उसका आर्डर निकाला तो मेरे पास दरख्वास्त पर दरख्वास्त आई, एम० एल० ए० कितने ही आये, भाई, 'उन लोगों को क्यों परेशान कर रहे हो।' अब मैं जनता का स्वास्थ्य देखूं या आपकी पिक्चर न देख सकने की परेशानी। मैं आइसक्रीम बन्द करता हूं, आइस बन्द करता हूं, उसके लिये शिकायत आती हैं कि यह क्यों बन्द की जा रही है। (कुछ व्यवधान होने पर) मैं जानता हूं, 'दि शू हैज बिगन टु पंच' आप सुनते जाइये। मैं कहना चाहता हूं कि जो काम हम जनता के स्वास्थ्य के हित में करना भी चाहते हैं उसमें भी आप रखना अंदाज होते हैं। बस इतनी ही खुशी है कि रखना अंदाज तो हुये, लेकिन शिकायत नहीं की इस फ्लू और कालरा के बारे में। शिकायत करते तो मेरा दिल टूट जाता इतना कि जिसका जवाब नहीं।

कहीं कहीं तबादले का भी जिक्र कर दिया गया। जहां पर अफसर पार्टी बन्दी में पड़ेंगे 'आई विल बि वेरी स्टिफ फार देम'। बिजनौर के तबादले में भी पार्टीबन्दी थी और मेरे दिमाग में वह बात है। जो मैंने वायदा किया था उसे पूरा करूंगा। मैंने किसी की रू रियायत नहीं की है और न करूंगा ही जबतक कि आप लोग मुझे मजबूर नहीं करेंगे। मैंने अपना एक सिद्धांत बना लिया है। जैसा कि किसी सदस्य ने कहा कि गड़बड़ी है अस्पतालों में, वह सही है। मैं मानता हूं कि गड़बड़ है लेकिन सभी जगह ऐसा नहीं है। कुछ लोग एक्सेप्शन भी हैं कि जो ठीक काम करते हैं। माननीय झारखंडेराय जी, कटमोशन के मूवर हैं, एक पार्टी के लीडर हैं। बलरामपुर अस्पताल के बारे में उन्होंने कहा कि वहां गरीब, अमीर सब को एक-सा बरताव मिलता है। उनका सार्टिफिकेट बहुत महत्त्व रखता है। ऊदल साहब का सार्टिफिकेट उसके विपरीत जाता है, लेकिन लीडर का सार्टिफिकेट होने के बाद ऊदल साहब का सार्टिफिकेट कोई अहमियत नहीं रखता। बहुत सी संस्थाएं ऐसी हैं कि जहां ठीक से काम होता है और जहां-जहां खबर मिलती है कि फलां डाक्टर गड़बड़ कर रहा है तो एक मिनट मुझे नहीं लगता है ऐक्सन लेने में। लेकिन अगर हमारे मित्र इसका अहसास न करें तो मुझे इसका दुःख होता है। मैं हाथरस गया था अस्पतालों के निरीक्षण के सिलसिले में। वहां मेरे पास एक शिकायत आई। एक शख्स ने कहा कि मेरी स्त्री को बच्चा होने वाला था, उसके लिये लेडी डाक्टर ने २०० रुपया मांगा। मैं रुपया नहीं दे सका और उसकी वजह से वह इंडिफरेंट हो गई और जाने पर इस बुरी तरह से इंतजाम किया कि मेरी वाइफ मर गई। यह बात सुन कर मुझे बड़ा दुःख हुआ। मैंने उस लेडी डाक्टर को वहीं डांटा। हालांकि मुझे डांटना नहीं चाहिये था, लेकिन मैं इतना उत्तेजित हो गया था कि अपने को रोक नहीं सका और मैंने डांटा। मुझे उसका काम खराब दिखाई पड़ा। मैंने डिप्टी डाइरेक्टर को वहां भेजा और इन्क्वायरी हो रही है। वह ससपेन्ड हैं। इन्क्वायरी मेरे सामने आने वाली है और फिर उस पर निर्णय किया जायगा। जिस वक्त हमको कोई बात मालूम होती है उसमें मुझे जरा भी देर करने में दिलचस्पी नहीं मालूम होती है। मुझे आशा है कि चन्द महीनों में सारे सूबे के अस्पतालों के डाक्टर अपनी–अपनी ड्यूटीज को पूरी तरह

[श्री हुकुम सिंह विसेन]

से अदा करेंगे और जो लोग इसमें कोताही करेंगे उनके साथ जो मुनासिब बरताव होगा उसको करने में गुरेज नहीं करूंगा, नहीं करूंगा और नहीं करूंगा। आप लोगों की मेहरबानी हमारे साथ होनी चाहिये।

हमारे मित्र झारखंडेराय जी को दुःख हुआ यह देखकर कि इस ग्रांट के लिटरेचर में कहीं सोशलिस्टक पैटर्न नहीं लिखा। मैं अपने सेक्रेटरी से यह हिदायत करूंगा कि आइन्दा साल से वह एक जुमला कहीं लिख दिया करें। अगर इसको देखा जाय तो मालूम होगा कि जो इसमें प्राविजन है उससे गरीब जनता की मदद करने का प्रयास किया गया है। वही इस बात का द्योतक है कि सोशलिस्टक पैटर्न पर यह बजट बनाया गया है या नहीं? क्या हमारे मित्र कह सकते हैं कि गांवों में अस्पताल खोलने की जो हमारी नीति है उससे गरीब जनता को मदद नहीं पहुंचेगी? हमारी तो नीति यह है कि अगर गरीबों को दवाई देने का माकूल इन्तजाम न हो तो उसको सजा दी जाय यह सोशलिस्टिक पैटर्न की तरफ कदम बढ़ाता है या नहीं? लेबरर्स के लिये जो इन्श्योरेंस की स्कीम है यह सोशलिस्टिक पैटर्न की तरफ कदम बढ़ाती है या नहीं? गांवों में जो हेल्थ सेंटर खोलने की योजना है यह सोशलिस्टक पैटर्न की तरफ कदम बढ़ाती है या नहीं? इसी तरह के कामों से यह सारा बजट भरा पड़ा है। मैं यह कहने की जुर्रत तो नहीं करता कि हमारे मित्र ने बजट को पढ़ने की गलती नहीं की, लेकिन यह जरूर कहूंगा कि समझने की तकलीफ गवारा नहीं की।

एक बात यह कही गयी कि अडल्ट्रेशन के बारे में सरकार कुछ नहीं कर रही है। मैं आपको बताऊं कि ५,४२९ प्रासिक्यूशन किये गये अडल्ट्रेशन के बारे में और ३,२१० में कन्विक्शन हुआ और ३,४२,४८३ रुपये जुरमाना हुए और ७७ आदमियों को कैद की सजा दी गयी। यह सब कार्यवाही हम अडल्ट्रेशन ऐक्ट के अन्तर्गत कर रहे हैं मैं यह यकीन दिलाना चाहता हूं कि कानून के जरिये से यह मर्ज दूर नहीं होगा। हमको और आपको कमर बांध कर इसका मुकाबला करना पड़ेगा। हमको अपने देश के रहने वाले व्यापारियों का नैतिक स्तर ऊंचा करना पड़ेगा। हमको इस अडल्ट्रेशन के संबंध में एक जबर्दस्त पब्लिक ओपीनियन बनाना पड़ेगा। हम अगर कहीं स्ट्रे केसेज पकड़ लेते हैं और उनका प्रासिक्यूशन कर दें तो इससे काम चलने वाला नहीं है। यह तो रोजमर्रा अडल्ट्रेशन होता रहता है। मैं कहता हूं कि अगर आप लोग यह समझते हैं कि हम घी प्योर खाते हैं तो अपने आपको धोखा देते हैं। अगर आप यह समझते हैं कि प्योर तेल खाते हैं तो अपने आपको धोखा देते हैं। मैं यहां तक जानता हूं कि प्योर डालडा भी आपको मिलना मुश्किल है। इसलिये सरकार सारा प्रबन्ध करे यह मुश्किल है। तब तक सरकार कुछ नहीं कर सकती जब तक कि जनता की ओपीनियन उसके खिलाफ क्रियेट न की जाय। मैं आशा करता हूं कि जिस तरह से हमारे मित्र ने अपने विचार यहां पर प्रकट किये हैं और सरकार को सुझाव दिये हैं उस तरह से उन सुझावों को खुद भी अमल में लाने की कोशिश करेंगे। अगर ऐसा हो जाय तो हमारा काम बहुत आसान हो जायगा। जो हमारा और आपका उद्देश्य है उसको पूरा करने में हमको और आपको जरा भी देर नहीं लगेगी। और अगर आप चाहें कि यहां हमको सारे सुझाव देकर आप खामोशी अख्तियार कर लें तो उससे यह मामला हल होने का नहीं है। मैं किसी पर आक्षेप नहीं करना चाहता, लेकिन इसका एक उदाहरण है। हमारे कुछ जनसंघ के भाई कहा करते थे कि गो बध बन्द करो। सत्याग्रह भी किया, लेकिन जब सरकार ने कुछ एकानामिक कारणों से उसको बन्द कर दिया तो लोग खामोश हो गये और आज वे गो सदनों में एक पैसा भी मदद करने के लिये तैयार नहीं हैं। पहले कहा करते थे कि भरसक मदद करेंगे। मैं जौनपुर के राजा साहब से प्रार्थना करूंगा कि वे लोगों से चन्दा दिला कर इस संबंध में सरकार की मदद करें, क्योंकि सरकार अकेले इसके भार को वहन नहीं कर सकती। जैसे हमारे उन दोस्तों ने खामोशी अख्तियार की है वैसे इस मामले में आपने भी की तो फिर हम करते रहेंगे और आप देखते

रहिये। जितना हम कर सकेंगे उतना करेंगे, लेकिन आपके सहयोग की निहायत जरूरत है।

किसी साहब ने कह दिया कि मलेरिया को रोकने का कोई प्रबन्ध नहीं किया। हमने २० यूनिटें एन्टी मलेरिया की स्थापित की हैं और उसके इंसीडेंस को चेक भी कर दिया है। तमाम सूबे में और खास तौर से तराई के इलाके में उसने बड़ा भारी काम किया है। ऐतबार न करें तो त्रिलोकीसिंह जी से पूछ लें। किसी का घोंघा ठीक न हो सका हो तो शिकायत हो सकती है, लेकिन आम तौर पर इन सब बातों की तरफ ध्यान दिया गया है।

गालिबन प्रतापसिंह जी ने कहा कि एवरेज एज के बारे में कुछ नहीं बताया। आज एवरेज एज ३४.२ वर्ष है। पहले कम थी, अब बढ़ती जा रही है। एज में इजाफा हो रहा है, उसी तरह से जैसे और बातों में इजाफा हो रहा है।

मैं महिलाओं का आभारी हूं कि जिन्होंने मेरी एक राय से ताईद की, मर्दों ने भी ताईद की, लेकिन बोले मुखालिफत में, लेकिन महिलाओं ने जो कहा वैसी ही ताईद की। मैं उनको यकीन दिलाता हूं कि जहां तक हमारी रकम जो दी गयी है, वह हमारा साथ देगी, उनकी मांगों को पूरी करने का प्रयत्न करूंगा।

फेमिली प्लानिंग के बारे में भी कहा गया। चन्द्रावती जी ने भी कहा और दूसरे लोगों ने भी कहा और डिप्टी स्पीकर साहब ने भी कुछ आबजरवेशन किये। मुझे इस सम्बन्ध में इतना ही कहना है कि फेमिली प्लानिंग का काम बड़ा टेढ़ा है। इसमें जो प्रीच करेंगे वही मुल्जिम भी साबित हो सकते हैं। यह चीज बिलकुल नयी है और बड़ी मुश्किल से लोगों के इमीजेनेशन को कैच कर सकेगी। जनता इसके लिये बड़ी मुश्किल से राजी होगी। यह काम कानून के जरिये से नहीं हो सकता, लेक्चर के जरिये से भी नहीं हो सकता, जो खास-खास लीडर्स हैं वे एक्जाम्पिल सेट करें तभी यह काम हो सकता है और लोग उनका अनुकरण करेंगे। हमारे डिप्टी स्पीकर महोदय ने कहा कि मेरे ऊपर भी बड़ा असर पड़ा। श्री त्रिलोकी सिंह से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन श्री नारायणदत्त से मैं जरूर कहना चाहता हूं कि उन पर कोई असर पड़ा या नहीं पड़ा। जब तक कोई एक्जाम्पिल सेट नहीं किया जायगा, तब तक इसमें कामयाबी हो ही नहीं सकती। और मैं अपनी महिलाओं से भी कहता हूं कि इसमें आत्मसिद्धि होनी चाहिये, निग्रह होना चाहिये और कंट्रोल होना चाहिये। जब तक अपने आप पर कंट्रोल नहीं होगा, लेक्चर और कानून के जरिये फेमिली प्लानिंग कामयाब नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। मैं तो ऐसा कहना चाहता हूं कि अभी मैं दिल्ली हेल्थ मिनिस्टर्स कान्फ्रेन्स में गया था, तो वहां भी शिकायत थी कि इस ओर अब तक काफी प्रगति नहीं हुई है। मैंने स्कीम बनायी है और आप लोगों ने तो देखा होगा कि एक फेमिली प्लानिंग अफसर भी होगा, कुछ सेंटर भी होंगे। बलिया में भी खोला है, मेरठ में भी खोला है और देवरिया में भी खोलने जा रहे हैं।

एक सदस्य––बहराइच का क्या हाल है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन––वहां सभी कंट्रोल्ड हैं। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि दिल्ली में भी मैंने बिलकुल निडर हो कर कहा था कि यह नयी स्कीम है, जनता उसको कबूल करने के लिय तैयार नहीं है, क्योंकि वाकयात बिलकुल दूसरे किस्म के हैं हमारे देश के। मैं आप को अपना एक तजुर्बा बतलाता हूं कि एलेक्शन के जमाने में एक जिले में जा रहा था तो गांव के करीब पहुंचने पर मैंने देखा कि चार पांच आदमी गेहूं के खेत काट रहे थे। धूप तेज थी, इसलिये मैंने सोचा कि थोड़ी देर तक बाग में सुस्ता लें। मैं जीप से गया था मैंने सोचा कि इन आदमियों को बुला कर जरा पता तो लगा लूं कि वे वोट किसको देने वाले हैं और गांव में क्या हवा बह रही है। जैसे ही उन लोगों ने मोटर देखी कि वे भाग खड़े हुये। मेरे बहुत

[श्री हुकुमसिंह विसेन]

समझाने पर वे तीन कदम आते थे तो एक कदम पीछे हट जाते थे, बड़ी मुश्किल से वे १०, १५ मिनट में मेरे पास आये तो मैंने पूछा कि तुम लोग भाग क्यों ? तो उन लोगों ने कहा कि मैंने सुना है कि सरकार के लोग कोई सुई लगा देते हैं। श्री त्रिलोकी सिंह जरा कान खोल कर सुन लें कि वह जिला लखनऊ ही था जहां के लोग बड़े होशियार समझे जाते हैं। तो इस तरह से प्रोपेगेंडा किया गया थाँ देहातों में। तो मै नहीं समझता कि हमारे आदमी जो फैमिली प्लानिंग का प्रोपेगेंडा करने के लिये जायेंगे वे देहातों से लौट कर चले आयें तो यही खैरियत की बात होगी। लिहाजा यह काम आसानी से नहीं होगा। जब उस पार्टी के और इस पार्टी के नौजवान खासतौर से, बूढ़े तो मदद करेंगे ही, सब मिल कर इस समस्या को हल करने का बीड़ा उठा लें तो मुझे यकीन कामिल है कि इसमें जरूर सफलता होगी। यह कोई हंसने की बात नहीं है। अगर इसमें सफलता नहीं होगी तो केवल पूर्वी जिलों में ही नहीं, बल्कि सारे सूबे में भुखमरी बढ़ती चली जायगी और हम कितना ही अन्न पैदा करते जायेंगे एक स्टेज ऐसा आ जायगा कि डिमिनिशिंग रिटर्न्स की स्थिति आ जायगी। इस तरह से दिन दूनी रात चौगुनी तादाद बढ़ती जायगी तो फिर कहीं खड़े होने की जगह भी नहीं रह जायगी। आपको ताज्जुब होगा कि हमारे राज्य में २,००० आदमी रोज पैदा होते हैं। इसमें हंसने की कोई बात नहीं है, जो मरते हैं उनको मुजरा देकर यह संख्या है या क्या है, यह मैं नहीं कह सकता। लेकिन दो हजार आदमी रोज पैदा होते हों तो तीस दिन में ६०,००० हुए और बारह महीनों में ७,२०,००० हुए। १० वर्ष में बढ़ कर इनकी कितनी तादाद हो जायगी, आप जोड़ लें। अगर इंटेंसिव कल्टीवेशन भी करते चले जायं तो भी रहने की जगह नहीं रहेगी, खाने पीने को कौन कहे। लिहाजा इस चीज को सीरियसली देखा जाय और जैसा कि हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने कहा इसको हमें सफल बनाने की कोशिश करनी चाहिये।

एक और शिकायत की गई, लेकिन क्या बताऊं, मालूम होता है वह शिकायत तो नहीं है, कुछ इंस्पायर्ड बात वह कह गये। इतना समझने की अक्ल तो मैं रखता हूं कि एक ही आदमी डिप्टी डायरेक्टर भी है और हेड आफ एनाटामी और फिजियालाजी डिपार्टमेंट, आयुर्वेद का है। यह ठीक है वह डिप्टी डायरेक्टरी के अलावा हेड आफ दि एनेटामी विभाग की हैसियत से टीचिंग का या लड़कों को पढ़ाने का भी काम करते हैं, वह अपना अलग वक्त देते हैं, अपनी मोटर से आते हैं और इसके लिये उन को कोई कनवेन्स या एलाउन्स इस के लिये नहीं दिया जाता है, वह अपनी कास्ट यह सब करते हैं। तो फिर एतराज किस बात का ऐसा आदमी भी तो कोई हमें मिले, ऐसे आदमी मिलने आज के जमाने में बहुत दुश्वार है जो देश की सेवा के खयाल से इतना काम करे। कहा जाता है कि सरकारी मुलाजिमों पर और ऐडमिनिस्ट्रेशन पर खर्च बहुत बढ़ता जाता है, लेकिन अगर वह मुफ्त पढ़ाते हैं तो क्या यह फायदे की चीज नहीं है ? इस तरह से उनके साथ कोई पक्षपात नहीं है, वह अपने काम के अलावा पढ़ाया करते हैं और जो यूजफुल आदमी होते हैं उन से हम इस तरह से काम ले लेते हैं।

मिडवाइव्ज और मेटरनिटी सेण्टर्स के बारे में भी बहुत जोर दिया गया। मेरी समझ में यह नही आया कि एक तरफ तो फीमली प्लानिंग की बात कही गई और उसके साथ ही मेटर्नटी सेण्टर भी चाहिये, यह दोनों चीजें कुछ मेल नहीं खातीं एक दूसरे से। अगर फेमिली प्लानिंग होगी तो मेटर्नटी सेन्टर्स की ज्यादा जरूरत नहीं और अगर फेमिली प्लानिंग नहीं है तो मेटर्नटी सेन्टर्स की जरूरत हो सकती है। अगर आप दोनों चीजें साथ-साथ चाहते हैं तो इससे मालूम होता है कि आप का मन अभी दुविधा में है, लेकिन फिर भी हमारी इच्छा है और कोशिश है कि ऐसे सेन्टर्स की तादाद जगह-जगह बढ़े।

इसके अलावा मैं अपने मित्र श्री गोविन्द सहाय जी का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने बहुत ही कांस्ट्रक्टिव सुझाव दिये हैं। उन्होंने शुरू में तो कहा कि मैं इस ग्राण्ट की ताईद करता हूं, लेकिन बोले खिलाफ, वैसे उनके सुझाव बहुत कांस्ट्रक्टिव थे और मैंने उनको बड़े गौर से सुना। एक बात उन्होंने कही थी वह मेरे दिमाग से निकली जा रही है

वर्ना मैं उसका जिक्र करता। कुछ आसनों के लिये कहा था और बहुत सी बातों के लिये कहा था, अगर वह बात याद आ जाती तो मैं कह देता। फिर याद कर के उस पर अमल करने की कोशिश करूंगा।

टी० बी० बेड्स के बारे में भी कहा गया। मुझे दुःख है कि इस सूबे में यह मर्ज बढ़ रहा है बावजूद हमारी कोशिशों के, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं हर जगह बेड बढ़ाने की, लेकिन खाली बेड बढ़ाने से ही काम नहीं चल सकता, क्योंकि ४–६ मरीज तो मेरे पास ही रोज आते हैं। पहले मैं जब मिनिस्टर नहीं था तो मुझे इसका इतना अहसास नहीं था, यह मेरी भूल थी और गलती थी। हम अपने जिला अस्पतालों में भी कुछ बेड्स रखना चाहते हैं और क्लिनिक्स खोलना चाहते हैं, लेकिन जितनी बीमारी है उस हिसाब से हमारे लिये करना मुश्किल है, फिर भी जो कुछ सम्भव होगा वह किया जायगा। बहुत से सुझाव माननीय मित्रों ने अच्छे दिये उनका मैं बहुत आभारी हूं। कुछ लोगों ने तो बिलकुल गड़बड़ सुझाव दिये, लेकिन जिनके अच्छे सुझाव आये हैं उन पर हम अमल करने की चेष्टा करेंगे और लाभ उठावेंगे। इन शब्दों के साथ मैं सदन से प्रार्थना करूंगा कि वह इन मागों को स्वीकार करें।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १९---चिकित्सा की धनराशि में एक रुपये की कटौती की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १९---चिकित्सा---लेखा शीर्षक ३८---चिकित्सा के अन्तर्गत ४,१५,२२,७०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५७–५८ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २०---जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत १ रु० की कटौती की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २०---जन-स्वास्थ्य---लेखा शीर्षक---३९---जन–स्वास्थ्य के अन्तर्गत १,६७,७६,८०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५७–५८ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---एक निवेदन मैं माननीय सदन से करना चाहता हूं। आज जब मंत्री जी बोलने खड़े हुये तो दो बहुत पुराने सदस्यों ने एक तरह से प्रोटेस्ट करना शुरू किया और सदन में हल्ला मचाना शुरू किया। आपने मुझे यहां सदन का सम्मान बढ़ाने के लिये भेजा है। तो आज तो मैंने उनके साथ रियायत बरती, लेकिन आप ही के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करना पड़ेगा तो मुझे बड़ा क्लेश होगा और मैं सभी माननीय सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि सदन का सम्मान बढ़ाने के लिये पूरा सहयोग प्रदान करें।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ३० मिनट पर सोमवार, १२ अगस्त, १९५७ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ;
६ अगस्त, १९५७।

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३३५ पर)

क्रम-संख्या	पद	स्थानों की संख्या
	गजटेड—पी० आर०डी० हेडक्वार्टर्स	
१	ऐडमिनिस्ट्रेटिव कमान्डेन्ट	१
२	असिस्टेन्ट कमान्डेन्ट	२
३	असिस्टेन्ट कमान्डेन्ट (यूथ मूवमेन्ट)	१
४	असिस्टेन्ट कमान्डेन्ट (इन्चार्ज, फिजिकल कल्चर)	१
५	ऐडमिनिस्ट्रेटिव कमान्डेन्ट का निजी सहायक	१
		(बिना भरी हुई)
	नान गजटेड स्टाफ—हेडक्वार्टर	
१	आफिस सुपरिन्टेन्डेन्ट	१
२	सीनियर नोटर और ड्राफ्टर	२
३	एकाउन्टेन्ट	१
४	जूनियर नोटर और ड्राफ्टर	३
५	स्टेनोग्राफर	१
६	रूटीन क्लर्क	३
७	टाइपिस्ट	२
८	आफिस चपरासी	३
९	अर्डरली पीयन	९
१०	चौकीदार	३
११	रिकर्ड-कीपर	१
१२	क्लर्क (असिस्टेंट क्वार्टर मास्टर)	१
	एक्जीक्यूटिव स्टाफ	
१	क्वार्टर मास्टर क्लर्क	१
२	स्टोर-कीपर	२
३	ड्राइवर	४
४	क्लीनर	४
५	सूबेदार एडजूटेन्ट	१
६	कम्पनी हवलदार मेजर	१
७	कम्पनी क्वार्टर मास्टर हवलदार	१
८	हेड कानस्टेबुल गार्ड	३
९	कानस्टेबुल गार्ड	१०
१०	ड्रिल इन्सट्रक्टर	३
११	हेड ड्रिल इन्सट्रक्टर	१
१२	पार्ट टाइम मेडिकल आफिसर	१
१३	कम्पाउन्डर	१
१४	नर्सिंग आर्डली	१
१५	स्वीपर्स	४
१६	मैसन	१
१७	कुक्स	२

क्रम-संख्या	पद	स्थानों की संख्या
१८--वाटरमैन	.. ..	१
१६--स्टोरमैन	.. ..	१
२०--बुगलर्स	.. ..	२
२१--बैन्ड मास्टर	.. ..	१
२२--बैन्ड्स मैन	.. ..	१३

फिजिकल कल्चर--टेम्पोरेरी स्टाफ

१--रूटीन क्लर्क (टाइपिस्ट)	१
२--चौकीदार (कुंवर जसबीर सिंह मेमोरियल बोट हाउस के लिये) ..	१

टेम्पोरेरी स्टाफ--जिला क्वार्टर के लिये

१--डिस्ट्रिक्ट आर्गनाइज़र	४६
२--असिस्टेन्ट डिस्ट्रिक्ट आर्गनाइज़र	४६
३--जोन वर्कर	७२०
४--जोन वर्कर (ट्रेनिंग रिज़र्व)	६३
५--आफिस पीयन	३७
६--व्यायाम शाला इन्स्ट्रक्टर-कम-केयर टेकर	१५
७--क्लर्क	३७

प्रान्तीय रक्षक दल के लिए स्वीकृत स्थाई स्थानों की सूची

१--असिस्टेन्ट कमान्डेन्ट	१
२--सीनियर नोटर ड्राफ्टर	१
३--रूटीन क्लर्क	१
४--दफ्तरी	१
५--आफिस पीयन	१
६--आर्डरली पीयन	२
७--चौकीदार	१
८--क्वार्टर मास्टर	१
६--हेड कानेस्टेबिल आरमोरर	१
१०--आरमोरर मिस्त्री	१
११--हेड ड्राइवर	१
१२--ड्राइवर	१
१३--क्लीनर	१
१४--ड्रिल इन्स्ट्रक्टर	२
१५--हेड क्लर्क	१
१६--एकाउन्ट्स क्लर्क-कम-स्टोर कीपर	१
१७--ड्राफ्टर	१
१८--टाइपिस्ट-कम-डिस्पैचर	१
१६--रिफरेन्स क्लर्क	१
२०--स्टेनोग्राफ़र	१
२१--दफ्तरी	१
२२--पीयन	२
२३--अर्दली	२

क्रम-संख्या	पद	स्थानों की संख्या
२४--चौकीदार	.. ..	१
२५--वाटर मैन-कम-फर्रास	.. ..	१
२६--स्वीपर	.. ..	१
२७--(टेकनिकल असिस्टेन्ट) (इस स्थान को अबियन्स में छोड़ दिया गया है)		१

प्रान्तीय रक्षक दल के जिले के आफिसों के लिये स्वीकृत स्थाई स्थानों की सूची

१--डिस्ट्रिक्ट आर्गेनाइजर	.. .. ..	५
२--असिस्टेन्ट डिस्ट्रिक्ट आर्गेनाइजर	.. .. ..	५
३--जोन वर्कर	.. ..	८०
४--जोन वर्कर (ट्रेनिंग रिजर्व)	.. .. ..	७
५--क्लर्क	.. ..	१४
६--पीयन	.. ..	१४
७--डिस्ट्रिक्ट सुपरिन्टेन्डेन्ट, फिजिकल कल्चर (इस स्थान को अबियन्स में छोड़ दिया गया है)	.. ..	१४

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३४३ पर)

इलाहाबाद जिले में १९५६ के प्रत्येक त्रिमास में सीमेंट की प्राप्ति तथा उसके वितरण की सूची

त्रिमास, १९५६	प्राप्ति (टनों में)	वितरण (टनों में)	
		नगर में	ग्रामीण क्षेत्र में
प्रथम	१,३९६	६८६	७१०
द्वितीय	१,३६५	६२९	७३६
तृतीय	५६०	४५	५१५
चतुर्थ	२,०६८	१,०७९	९८९
योग ..	५,३८९ टन	२,४३९ टन	२,९५० टन

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३५३ पर)

जिला खीरी में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य की सूची

प्रथम पंच वर्षीय योजना के अधूरे कार्य	लम्बाई मील फ०	अनुमानित लागत रु०
१—लखीमपुर-ईशा नगर सड़क	११ ४	
२—लखीमपुर-निघासन सड़क	६ ६	
३—गोला-सिकन्दरा सड़क (सी० सी० ट्रैक) ..	६ ०	
४—गोला-कुकरा ,, ...	५ ३	
५—गोला-संसारपुर-कुराम्रा सड़क ,, ...	५ ४	
६—गोला-अलीगंज ७—गोला-मुहम्मदी ८—गोला-लखीमपुर ९—लखीमपुर-सिंघाई .. }	१२ ४	
१०—पलिया, त्रिकुलिया, सेमरी, खजुरिया व पुलों तथा पुलियों का बनाना	२१ ०	
११—निघासन-बैलरैन सड़क	११ २	
१२—भारी यातायात वाले मीलों का आधुनीकरण तथा सुधार—		
(क) लखीमपुर-गोला सड़क	१० ०	
(ख) सीतापुर-लखीमपुर सड़क	२ ०	
द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत कार्य,—नई पक्की सड़कों का निर्माण		
१३—मीरा मैलानी पवैया सड़क	११ ०	५,५०,०००
१४—गोला-बिलसंदा सड़क	१६ ०	९,००,०००
१५—मैलानी रेलवे फ़ीडर सड़क	३ ०	१,०८,०००
१६—लखीमपुर-मितौली-औरंगाबाद सड़क	२२ ०	७,९२,०००
१७—पलिया-मीरा सड़क	८ ०	४,००,०००
१८—औरंगाबाद-मैगलगंज सड़क	४ ०	१,४०,०००
१९—श्रमदान की सड़कें—		
(क) लखीमपुर-छपरतला	६ ०	
(ख) खीरी-लगेरा	५ ४	
(ग) ओएल-बहाजन	१५ २	
२०—स्थानीय पक्की सड़कों का पुनः निर्माण—		
लखीमपुर-औरंगाबाद सड़क	६ ५	१,९९,०००
२१—भारी यातायात वाले मीलों का आधुनीकरण तथा सुधार	१० ०	
२२—सी० सी० ट्रैक्स और पेन्टेड सड़कें (३३ प्रतिशत सहायता के आधार पर)—		
(क) फैक्ट्री से पी० डब्ल्यू० डी० सड़क खमरिया तक	० ६	
(ख) फैक्ट्री से खनवापुर के तरफ़ ..	२ ०	
(ग) फैक्ट्री से इब्राहीमपुर तक	१ २	

प्रथम पंच वर्षीय योजना के अधूरे कार्य			लम्बाई मील फ०	अनुमानित लागत
(ङ) फैक्ट्री सारिन्य खतौली	..	..	२ ०	
(च) बिबारी-बैबहा	..	..	५ ०	
(छ) मामरी-रोशनगंज-पीपरा	..	..	६ ०	
(ज) अलीगंज-सोनारीपुर	..	..	२ ०	
(झ) गरठनियां-सुहेला-कुकरा	..	..	८ ०	
(ञ) कुकरा स्टेशन से कुकराटाउन		..	३ ४	
(ट) बरखेरी नहर सड़क से गोला-लखीमपुर रोड		..	२ ०	
२३—पंचपेरीघाट पर सारदा नदी के ऊपर एक पैंटून पुल		..	..	३,२५,०००

सत्यमेव जयते

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७८–७९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३५३ पर)

मुजफ्फरनगर जिले में १९५५–५६ व १९५६–५७ में सीमेंट की प्राप्ति तथा उसके वितरण की सूची

प्राप्ति

वर्ष	सीमेन्ट कम्पनी का नाम			सीमेन्ट की प्राप्ति
				(टनों में)
१९५५–५६	१––सीमेन्ट मार्केटिंग कम्पनी	..	..	१,२७९
	२––रोहतास सीमेन्ट कम्पनी	..	..	३६३
	३––जापला सीमेन्ट कम्पनी	..	..	४६
	४––सवाई माधोपुर सीमेन्ट कम्पनी	..	..	१,११४
		योग	..	२,८०२ टन
१९५६–५७	१––सीमेन्ट मार्केटिंग कम्पनी	..	..	२,४१०
	२––सवाई माधोपुर सीमेन्ट कम्पनी	..	..	९५१
		योग	..	३,३६१ टन

वितरण

१९५५–५६	१––जिला सप्लाई अफसर द्वारा (नगर तथा दूसरे टाउन एरिया इत्यादि के लिये)	..	..	१,०५९
	२––जिला नियोजन अधिकारी द्वारा (नियोजन कार्यों तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिये)	..	..	१,७४३
		योग	..	२,८०२ टन
१९५६–५७	१––जिला सप्लाई अफसर द्वारा (नगर तथा दूसरे टाउन एरिया इत्यादि के लिए)	..	..	१,१७४
	२––जिला नियोजन अधिकारी द्वारा (नियोजन कार्यों तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिये)	..	..	२,१८७
		योग	..	३,३६१ टन

१९५५–५६ में ग्रामीण क्षेत्रों तथा नियोजन कार्यों के लिये प्राप्ति का ६२ प्रतिशत तथा नागरिक क्षेत्रों में ३८ प्रतिशत वितरण किया गया।

१९५६–५७ में ग्रामीण क्षेत्रों तथा नियोजन कार्यों के लिये प्राप्ति का ६५ प्रतिशत तथा नागरिक क्षेत्रों में ३५ प्रतिशत वितरण किया गया।

नत्थी 'ङ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३५९ पर)

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कानपुर जिले में निर्माण कार्य की सूची

योजना	नाम सड़क	अनुमानित लागत	कार्य जो होना है मय लम्बाई
		रु०	
चालू योजनायें	(अ) नई सड़कें		
	१--चौबेपुर-बेला ..	२,०७,०००	टौप कोट तथा अन्य कार्यों के के लिये। सड़क इन्टर कोट तक पूरी लम्बाई में बन चुकी है।
	२--सिकन्दरा-अकबरपुर	१७,४९,४००	२३ मील
	३--सिकन्दरा-मंगलपुर कच्ची सड़क	१,२७,०००	९ मील ३ फर्लांग
	(ब) आधुनीकरण		
	मील ६२५ से ६२९ जी० टी० रोड	४,८३,४१५	५ मील
	गंगा नहर के पश्चिमी मार्ग को सीमेंट से बनाना	३०,०००	१ मील
नई योजनायें द्वितीय पंच-वर्षीय	(अ) नई पक्की सड़कें		
	१--रसूलाबाद-झींझक	३,३८,०००	९ मील ३ फर्लांग कच्ची सड़क को पक्का करना
	(ब) आधुनीकरण		
	चौबेपुर-बेला	२,२२,०००	३ मील
	पुरानी सड़कों का जोर्णोद्धार ..		कुछ नहीं

पी० एस० यू० पी० ए० पी०-९७ एल० ए०--१९५७-७९६